वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत)

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली (मुख्यालय)
श्री अमिताव राय
समूह प्रमुख (प्रशासन)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
उत्पादकता भवन, 5-6 इंस्टिट्यूशनल एरिया लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003
ईमेल: amitav.ray@npcindia.gov.in

हैदराबाद
डॉ. बी. हेमंत
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
१० वां तल, ईस्टर्न विंग, गगन विहार कॉम्प्लेक्स
एम.जे. रोड, नामपल्ली हैदराबाद, आंध्र प्रदेश – 500001
फोन: 040- 24733473
ईमेल: hemant.rao@npcindia.gov.in, hyderabad@npcindia.gov.in

बेंगलुरु
श्री सी. नरेंद्र
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, द्वितीय तल, अभय कॉम्प्लेक्स
केएसडीबी बिल्डिंग, 55, रिसालदार स्ट्रीट शेषाद्रीपुरम, बेंगलुरु-560020
फोन: 080-23467294
ईमेल: c.narendra@npcindia.gov.in,
bangalore@npcindia.gov.in

जयपुर
श्री मुकेश सिंह
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
एसबी-96, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बापू नगर, जयपुर- 302004
फोन: **141- 2702935**
ईमेल: mukesh.singh@ npcindia.gov.in,
jaipur@npcindia.gov.in

भुवनेश्वर
श्री अविजीत नायक
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
ए/7, सूर्या नगर
भुवनेश्वर-751003, उड़ीसा
फोन: 0674-2397381/26
ईमेल: avijit.nayak@npcindia.gov.in

कानपुर
श्री सुनील कुमार
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
चौथा तल, कबीर भवन (यू.पी.एच.सी.लि. बिल्डिंग)
उद्योग निदेशालय (यू.पी.) कैंपस, जी.टी. रोड कानपुर – 208002
फोन: 0512- 2224176
ईमेल: sunil.kumar@npcindia.gov.in

चंडीगढ़
श्री सुवेन्दु शिवाकर
सहायक निदेशक एवं प्रभारी क्षेत्रीय निदेशालय
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
चंडीगढ़, एनसीडीसी बिल्डिंग
बे.नं. 1 & 2, सेक्टर- 14 पंचकुला, हरियाणा-134113
मोबाईल- 6287872655
ईमेल: suvyendu.s@npcindia.gov.in

कोलकाता
श्री एस. मलिक
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
9, सैयद अमीर अली एवेन्यू, पार्क सर्कस
कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700017
फोन: 033- 22876069
ईमेल: s.mallik@ npcindia.gov.in, kolkata@npcindia.gov.in

चेन्नई
श्री डी. श्रीनिवासुलू
प्रमुख (एआईपी)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
6, सिड्को इंडस्ट्रियल इस्टेट अंबतपुर चेन्नई, तमिलनाडु-600098
फोन: 044-26241059, 7200208675
ईमेल: d.sreenivasulu@npcindia.gov.in

मुंबई
सुश्री अरुंधती चट्टोपाध्याय
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नावेल्टी चेंबर्स, सातवाँ तल, ग्रांट रोड,
मुंबई, महाराष्ट्र – 400007
फोन: 022- 23002924, 23071322, 9869519366
ईमेल: achattopadhyay@ npcindia.gov.in, mumbai@npcindia.gov.in

गांधीनगर
श्री शिरीष पालीवाल
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
ई-5, जीआईडीसी, इलेक्ट्रोनिक इस्टेट,
सेक्टर- 26, गांधीनगर, गुजरात -382028
फोन: 079-23287344
ईमेल: shirish.p@npcindia.gov.in, gandhinagar@npcindia.gov.in

पटना
श्री पी.आर. उपाध्याय
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
द्वितीय तल, सुदामा भवन बोरिंग रोड क्रॉसिंग,
पटना, बिहार – 800001
फोन: 0612- 2558311
ईमेल: pr.upadhyay@ npcindia.gov.in,
patna@npcindia.gov.in

गुवाहाटी
डॉ. रजत शर्मा
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
राजगढ़ रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 32, उलुबारी पोस्ट ऑफिस,
गुवाहाटी, असम-781007
फोन: (कार्या.) 2453396, 2451896
फ़ैक्स: (0361) 2450160, 0361-3512552
ईमेल: rajat.sharma@ npcindia.gov.in, guwahati@npcindia.gov.in

दृष्टि

भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता संबंधी ज्ञान में सबसे आगे रहेगी।

लक्ष्य

उत्पादकता बढ़ाकर देश के सतत, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना।

गुणवत्ता नीति

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

QUALITY POLICY

We, at NPC are committed to achieve excellence in providing best in class Services to make Indian economy globally competitive and,

- Act as Catalyst for assisting Government and Industry,
- Promote Productivity through Consultancy, Research, Training and Skill Development,
- Support and Develop ecosystem for Innovation, Quality and Sustainability,
- Ensure Client Satisfaction.

We shall strive to upgrade our Services, human capital and infrastructure by reviewing effectiveness of management systems for continual improvement.

Director General

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या

महानिदेशक की कलम से

भारत में उत्पादकता आंदोलन 1950 के दशक में शुरू हुआ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की अगुवाई में इस आंदोलन ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है। वर्तमान में विशेषकर आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में उत्पादकता आंदोलन की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। सरकारी, निजी, सहकारी या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम; चाहे कोई भी संगठन हो, देश में उत्पादकता आंदोलन की नोडल एजेंसी के रूप में एनपीसी अर्थशास्त्र, औद्योगिक इंजीनियरिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन, अनुसंधान, कृषि, कृषि से संबद्ध व्यवसाय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से पेशेवरों के उपलब्ध संसाधनों से किसी भी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं विकसित और प्रतिपादित कर रही है।

उत्पादकता बढ़ाकर देश के सतत और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हम सतत रूप से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए, हमारे मूल्यों और उद्देश्य में हमारी प्रतिबद्धता और विश्वास सुदृढ़ करने वाले उनके सहयोग के लिए हम अपने सभी ग्राहकों और उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रति आभारी हैं। उत्पादकता आंदोलन को सुदृढ करने में हमारी सहायता के लिए, मैं स्थानीय उत्पादकता परिषदों के हमारे बृहद नेटवर्क के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं एनपीसी टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा है कि वे मजबूत भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे।

संदीप कुमार नायक, आईएएस
महानिदेशक

एनपीसी के बारे में

उत्पत्ति

स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक की शुरुआत में, प्रतिस्पर्धा करने और विश्व के अन्य देशों के समकक्ष बनने के लिए औद्योगीकरण पर ध्यान दिए जाने पर भारत में सचेत और व्यावहारिक उत्पादकता संचालित करने की अत्यावश्यक जरूरत महसूस की गई। इसके अलावा, भारतीय अंतरिक्ष आंदोलन के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 1956 में जापान का दौरा किया और 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र शामिल करके देश भर में उत्पादकता आंदोलन को गति देने के लिए केंद्रीय निकाय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इस उत्पादकता प्रतिनिधिमंडल के पश्चात, तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्त्वावधान में नवंबर 1957 को उत्पादकता संबंधी संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशें अन्य लोगों से साझा की गईं। संगोष्ठी में औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय निकाय की स्थापना के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए। इस तरह, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) स्वायत्त निकाय के रूप में अस्तित्व में आई और केंद्रीय उद्योग मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं।

एनपीसी भारत में उत्पादकता संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 1958 में उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एनपीसी एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन है। इसमें तकनीकी एवं पेशेवर संस्थानों और अन्य संबद्ध संस्थानों के साथ-साथ नियोक्ताओं एवं श्रमिक संगठनों और सरकार का समान प्रतिनिधित्व है।

अपनी स्थापना के बाद से उत्पादन और उत्पादकता के बीच के अंतर को समझने और प्राप्त इनपुट संसाधनों एवं आउटपुट के बीच संबंध समझने के लिए साधन और तरीके अनुकूलित करने में विभिन्न हितधारकों की सहायता करने के लिए अपनी विशेष सेवाओं के विस्तार से एनपीसी ने देश में उत्पादकता आंदोलन का आगे बढ़ाया है और अभी भी इसे आगे बढ़ा रहा है। इन सब से अंततः लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा, पिछले 64 वर्षों में अपने उत्पादकता कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए एनपीसी ने विभिन्न हितधारकों (सरकार/पीएसयू/पीवीटी) द्वारा क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थापना के पश्चात एनपीसी का विस्तार हुआ है। चेन्नई में प्रशिक्षण संस्थान सहित आज देश भर के 13 शहरों में इसकी अखिल भारतीय मौजूदगी है और औद्योगिक/आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिषद की सेवाओं के स्पेक्ट्रम में भी विविधता आई है। एनपीसी ने बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार स्वयं को ढाला भी है और जागरूकता लाने एवं भारतीय मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को I4.0 उन्मुख करने के लिए एपीओ के सहयोग से उद्योग 4.0 में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।

अंतराष्ट्रीय संबंध

एनपीसी ने चेन्नई में अपने परिसर में ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीईई) भी स्थापित किया है। सीईटीईई भारत-जापान सरकार के सहयोग की परिणति है और इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नव ऊर्जा विकास संगठन (एनईडीओ), जापान सरकार की सहायता से कार्यान्वित किया गया है। सीईटीईई का लक्ष्य है कि ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उन्नत ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी और तकनीकें प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। सीईटीईई "करके सीखो" की शिक्षण पद्धति पर आधारित है जिसमें प्रशिक्षुओं को "उद्योग की वास्तविक" परियोजनाओं से परिचित कराया जाता है।

भारत सरकार 1961 में स्थापित टोक्यो स्थित अंतर-सरकारी निकाय एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ)की संस्थापक सदस्य है। एनपीसीएपीओ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और यह उत्पादकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर एपीओ द्वारा सदस्य देशों के लिए पेश किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में भारतीय भागीदारी की व्यवस्था के लिए नोडल एजेंसी भी है। एनपीसी सदस्य देशों के प्रतिभागियों के लिए प्रत्येक वर्ष भारत में एपीओ कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

एपीओ सदस्य देश

संरचना

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं और उद्योग संव र्धन एवंआंतरिक व्यापार विभाग के सचिव परिषद के शासी निकाय के चेयरमैन हैं। महानिदेशक परिषद के प्रधान कार्यपालक अधिकारी हैं।

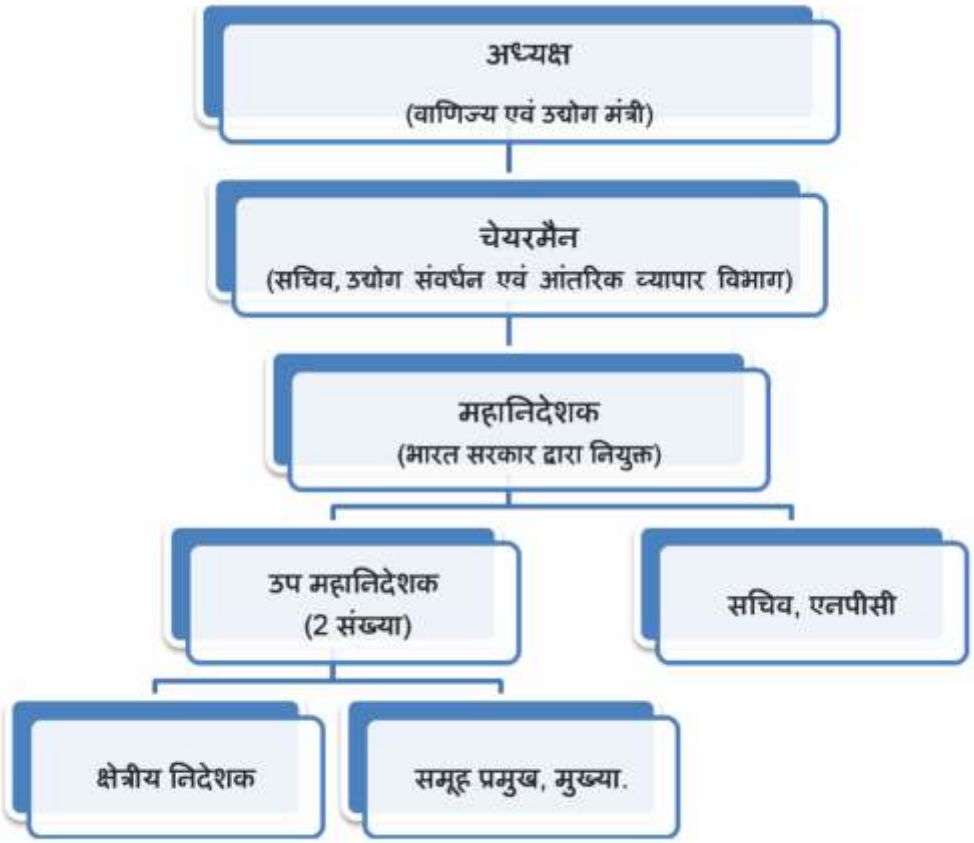

तालिका-1 एनपीसी की संगठनात्मक संरचना

मौजूदगी

जैसा कि मानचित्र-1 में दर्शाया गया है, प्रमुख राज्यों की राजधानियों/औद्योगिक केंद्र में एनपीसी के 12 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और चेन्नई में एक प्रशिक्षण संस्थान है। एनपीसी में लगभग 110 पूर्णकालिक पेशेवर/परामर्शदाता कार्यरत हैं, इसके साथ परियोजना-आधारित जरूरतों के लिए बाहरी विशेषज्ञ और संकाय भी सेवाएं देने के लिए सूचीबद्ध हैं।

अखिल भारतीय मौजूदगी	
मुख्यालय, दिल्ली	1
क्षेत्रीय निदेशालय	12
एआईपी संस्थान, चेन्नई	1

उद्देश्य

I. आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक – तीन निर्णायक बिंदुओं के संबंध में समाधान करते हुए समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सतत तरीके से नवाचार-आधारित उत्पादकता को बढ़ावा देना।

II. सरकार, व्यवसाय और समाज के बीच उत्पादकता चेतना और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना।

III. गुणक प्रभाव के लिए उन्नत उत्पादकता उपकरणों और तकनीकों के सृजन और अनुप्रयोग के माध्यम से मूल्यवर्धन प्रदर्शित करना।

IV. समझौतों और साझेदारियों के माध्यम से जरूरत अनुसार प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसंधान द्वारा उत्पादकता संवर्धन के लिए उद्योग, सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में सकल समाधान प्रदाता के रूप में कार्य करना

V. सहयोगात्मक नेटवर्किंग के लिए संस्थागत विकास और विकासशील प्लेटफार्मों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ताकि उत्पादकता आंदोलन सुदृढ़ हो।

VI. उभरते रुझानों पर नज़र रखते हुए उत्पादकता के संबंध में साक्ष्य-आधारित नीतिगत सहायता और सलाह प्रदान करके विशेषज्ञ समूह के रूप में कार्य करना।

VII. विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, योजनाओं और हस्तक्षेपों के लिए स्वतंत्र निरीक्षण संस्था बनना।

VIII. पुरस्कारों, संबद्धताओं, प्रमाणनों, प्रत्यायनों आदि के माध्यम से उत्पादकता अग्रणियों को मान्यता देना।

IX. आदान-प्रदान आधार पर उत्पादकता लाभ साझे करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क संवर्धित करना।

X. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा डेटा का संग्रह बनना।

XI. उत्पादकता लक्षण निदान के लिए सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय उत्पादकता मानक और स्व-मूल्यांकन वेब-आधारित मापन उपकरण तैयार करना।

गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

एनपीसी का लक्ष्य है कि यह पेशेवर दृष्टिकोण और सक्षमता सहित प्रचार-प्रसार संबंधी निकाय बने। संस्थान इसके लिए प्रयासरत है कि निम्नलिखित सहित विभिन्न तरीकों से उत्पादकता संवर्धन के अपने प्राथमिक उद्देश्य को साकार किया जाए:

परामर्श: कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और सेवा से जुड़े क्षेत्रों में उत्पादकता संवर्धन के लिए एनपीसी परामर्श कार्य करती है। इसके ग्राहकों में केंद्र और राज्य सरकारें, निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्र, उनकी एजेंसियों और अन्य ग्राहक समूह शामिल हैं। एनपीसी की परामर्श सेवाएं विकासात्मक दृष्टिकोण के साथ सहभागी और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से समस्या-समाधान और सकल समाधान पर भरोसा करती हैं।

प्रशिक्षण: कृषि और ग्रामीण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास में संलग्न कार्मिकों के विभिन्न स्तरों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

प्रचार-प्रसार:संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रकाशनों, उत्पादकता और गुणवत्ता कार्यक्रमों के आयोजन, अभियानों, प्रेरक पुरस्कारों और अन्य उपयुक्त तरीकों के माध्यम से उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना का प्रचार करना।

अनुसंधान: सामाजिक-आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सूक्ष्म और वृहत दोनों स्तरों पर मूल्यांकन एवं प्रभाव अध्ययनों का उत्तरदायित्व लेना और अनुसंधान सर्वेक्षण एवं अध्ययन आदि आयोजित करना। विभिन्न क्षेत्रों के लिए डेटाबेस तैयार करने के लिए उत्पादकता मापन अध्ययन निष्पादित किए जाते हैं।

रणनीतिक नियोजन: उत्पादकता और गुणवत्ता के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र चिह्नित करना, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए काम को उत्प्रेरित करना, जहां जरूरत हो वहां नए संस्थानों को बढ़ावा देना और नीति निर्माण के लिए इनपुट्स प्रदान करना।

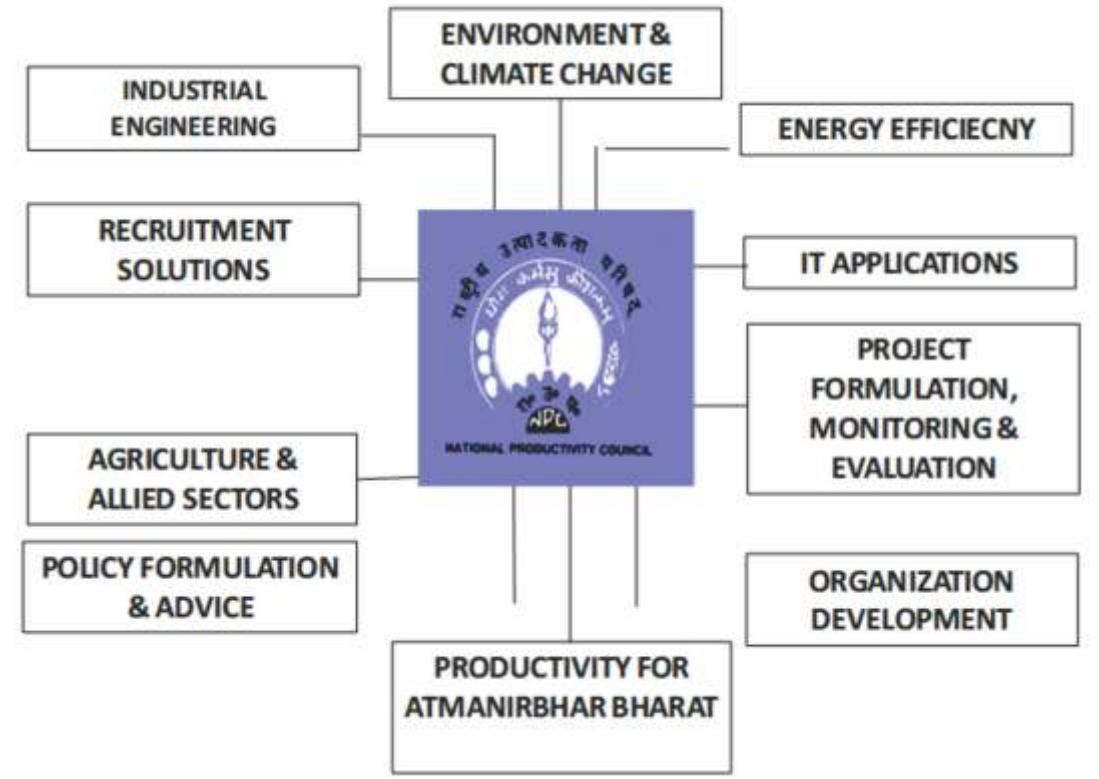

नेतृत्व और मार्गदर्शन

श्री पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री

माननीय श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग वर्ष (2019-वर्तमान), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण वर्ष (2020-वर्तमान), वस्त्र वर्ष (2021-वर्तमान) मंत्री और राज्य सभा नेता वर्ष (2021-वर्तमान) हैं। इससे पहले उन्होंने रेलवे, वित्त, कॉर्पोरेट मामले, कोयला, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खदान मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। वह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में, भारत ने 2021-22 में लगभग $675 बिलियन के अब तक के सर्वाधिक निर्यात की उपलब्धि हासिल की। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। इनमें से पहला समझौता विश्व स्तर पर अब तक का सबसे तेज़ वार्तालाप वाला एफटीए है और दूसरा भारत द्वारा दशक के बाद किसी विकसित देश से किया गया पहला समझौता है। विनिर्माण को अहम स्थान देने और विकास को गति देने एवं रोजगार सृजित करने में इसके महत्व पर बल देने के लिए उन्होंने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के शुभारंभ की देखरेख की।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में 2 वर्षों में लगभग 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण के माध्यम से उन्होंने विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इससे कोविड-१९ महामारी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित समाज के निर्धन, असुरक्षित एवं कमजोर वर्ग को सहारा मिला। उनके रेल मंत्री रहने के दौरान भारत ने रेल दुर्घटनाओं में शून्य यात्रियों की मृत्यु का अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकार्ड हासिल किया। विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों ने भारत के विद्युत क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों में अग्रणी भूमिका निभाई और ऊर्जा दक्षता के लिए विश्व के सबसे बड़े एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम (उजाला) को सफलतापूर्वक लागू किया। भारत के उर्जा क्षेत्र में पथ प्रदर्शक परिवर्तनों के लिए सम्मान के रूप में वर्ष 2018 में उन्होंने चौथा वार्षिक कार्नोट पुरस्कार भी प्राप्त किया।

श्री गोयल का शानदार शैक्षणिक रिकार्ड रहा है - अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट की परीक्षा में उन्हें दूसरा स्थान मिला था और मुंबई विश्वविद्यालय में कानून की परीक्षा में भी उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वे प्रख्यात बैंकर है तथा उन्होंने शीर्ष कॉर्पोरेट समूहों को प्रबंधन रणनीति एवं वृद्धि पर परामर्श दिया है। उन्होंने भारत के सबसे बडे वाणिज्यिक बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बडौदा के बोर्ड में भी कार्य किया। वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा उन्हें नदियों की इंटरलिंकिग संबंधी कार्य बल में भी नामित किया गया था।

नेतृत्व और मार्गदर्शन

श्री सोम प्रकाश

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री

माननीय श्री सोम प्रकाश 1972 बैच के आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अधिकारी हैं। 1972 में उन्होंने पंजाब राज्य नियोजन बोर्ड में अनुसंधान अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद, वह पंजाब उत्पाद शुल्क विभाग में उत्पाद तथा कराधान अधिकारी बन गए। वह पंजाब विश्वविद्यालय परिसर, चंडीगढ़ से एम.ए. (अर्थशास्त्र) हैं।

श्री सोम प्रकाश ने फरीदकोट, होशियारपुर और जालंधर के उपायुक्त के रूप में कार्य किया है और उन्होंने श्रम आयुक्त, पंजाब शहरी नियोजन तथा विकास प्राधिकरण (पुडा) के मुख्य प्रशासक, पंजाब वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक जैसे पदों पर भी कार्य किया है। वह फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र (पंजाब) से दो बार विधानसभा सदस्य (एमएलए) भी रहे हैं। वर्तमान में वह होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं।

नेतृत्व और मार्गदर्शन

श्री अनुराग जैन, आईएएस

सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा एनपीसी चेयरमैन

श्री अनुराग जैन, आईएएस (मध्य प्रदेश 1989) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार में सचिव और एनपीसी के पदेन चेयरमैन हैं। डीपीआईआईटी सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में उन्हें इसकी सबसे सफल पहलों में से एक विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की संकल्पना और कार्यान्वयन का श्रेय दिया जाता है।

श्री अनुराग जैन के पास वित्त क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में व्यापक अनुभव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में, वह लोक सेवा डिलीवरी प्रबंधन अधिनियम को कानूनी रूप देने के प्रमुख संचालक थे। इस अभिनव संकल्पना को देश में एक दर्जन से अधिक राज्यों द्वारा अपनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में राज्यों और संघ की ई-उन्मुखता आकलन रिपोर्ट में राज्य को शीर्ष पायदान पर ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह मध्य प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव (वित्त) और वित्त विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने भोपाल के जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया।

पेशेवर सेवाएं

उत्पादकता से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के बारे में परामर्श, क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन और पथ-प्रदर्शन के लिए एनपीसी समग्र समाधान प्रदाता है।

क. उत्पादकता प्रचार-प्रसार: राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के स्थापना दिवस १२ फरवरी को पूरे देश में प्रतिवर्ष उत्पादकता दिवस तथा इस पूरे माह को उत्पादकता माह के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि सभी संबंधित लोगों का ध्यान इस अवधारणा की तरफ आकर्षित किया जाए और समकालीन प्रासंगिक थीम्ससे उत्पादकता उपकरणों और तकनीकों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाए।

ख. परामर्श: एनपीसी द्वारा समग्र संगठनात्मक स्तर पर उत्पादकता, गुणवत्ता, लाभप्रदता और संवृद्धि में सुधार के लिए पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रों, केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग संघों, उनके सदस्यों आदि को परामर्श प्रदान करके एनपीसी उत्पादकता कौशल संवर्धित कर रही है और इनका प्रचार-प्रसार कर रही है।

ग. अनुसंधान: एनपीसी भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता से संबंधित विषयों पर डेटा और जानकारी संग्रहीत करने एवं इसका विश्लेषण करने के लिए परियोजना आधार पर गतिविधि-आधारित अनुसंधान आयोजित करती है। इन विषयों में मौजूदा चुनौतियां और क्षेत्रों की उभरती जरूरतें शामिल हैं।

घ. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: एनपीसी की प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधियां मुख्यतः मानव संसाधनों के विकास पर केंद्रित हैं: अर्थात ऐसे लोग तैयार करना जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादकता आंदोलन के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उद्योग और सेवा, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, और स्थानीय/क्षेत्रीय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता प्रबंधन संबंधी समस्याओं की वृहत श्रृंखला शामिल होती है। उभरती समस्याओं और निष्कर्षों पर ज्ञान प्रदान करने और इन पर प्रबंधन रणनीति संबंधी चर्चा के लिए एनपीसी क्षेत्रीय और सेक्टर-वार सम्मेलन भी आयोजित करती है। उद्यमों, सरकारों और अन्य संस्थाओं के लिए उत्पादकता/गुणवत्ता सुधार से संबंधित मामलों पर अध्ययन, अनुसंधान सर्वेक्षण, मूल्यांकन आदि आयोजित किए जाते हैं।

ङ. निगरानी एवं मूल्यांकन: एनपीसी औद्योगिक प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित विभिन्न सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं और योजनाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की पहलों से संबंधित उत्पादकता आकलनों और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एवं ई) अध्ययनों और निष्पादन प्रबंधन में शामिल रही है। अपने विभिन्न प्रभागों के माध्यम से एनपीसी ने सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य एजेंसियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में विविध तरह की परियोजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला है। जीआईएस आधारित एप्लिकेशन्स से संबंधित जीआईएससॉफ्टवेयर रखने के अलावा एनपीसी के पास ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जिनका परियोजना प्रबंधन एवं नियोजन और ऐसे डेटा के अर्थमितीय और सांख्यिकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है जिसे उपयुक्त नमूना तकनीक के माध्यम से प्राप्त किया जाना होता है। सरकारी योजनाओं और अवसंरचना विकास परियोजनाओं सहित परियोजनाओं की तत्क्षण निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड आधारित आईटी प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करने के लिए संस्थागत संबंधों को और अधिक विकसित किया है।

च. **भर्ती:** एनपीसी पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय (सीजीपीडीटीएम), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बीएसईस,पारादीप पत्तन न्यास आदि जैसे विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। एनपीसी को भर्ती के लिए शुरू से अंत तक आवेदन संसाधन, भुगतान गेटवे प्रदान करने, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन परीक्षा के संचालन, प्रश्न पत्र तैयार करने, मूल्यांकन, साक्षात्कार आयोजित करने आदि जैसे समाधान प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। एनपीसी अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करती रही है और व्यवसाय संबंधी कौशल परीक्षाएं और टंकण परीक्षाएं भी आयोजित करती रही है।

एनपीसी का लक्ष्य है कि मितव्ययी, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया प्रदान की जाए और यह सुनिश्चित हो कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, सख्ती से गोपनीय, परेशानी मुक्त तरीके से पूरी हो।

छ **डॉ. अम्बेडकर** उत्पादकता संस्थान (एआईपी) ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें कक्षाएं, छात्रावास और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। एआईपीका ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र (सीईटीईई) उद्योगों में लागू ऊर्जा दक्षता अवसर और ऊर्जा संरक्षण तकनीकें चिह्नित करने के तरीकों को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न औद्योगिक ऊर्जा उपयोगिता उपस्करों से सुसज्जित है। प्रशिक्षु निम्नलिखित के माध्यम से उपकरण संचालित कर सकते हैं और कुशल प्रचालन के प्रभाव को जानने के लिए प्रचालन मापदंड बदल सकते हैं, ऊर्जा बचत परिदृश्य और पद्धतियां बना सकते हैं, सिस्टम के निष्पादन मूल्यांकन के लिए परीक्षण कर सकते हैं:

- पंप प्रशिक्षण सुविधा
- कंप्रेसर प्रशिक्षण सुविधा
- पंखा प्रशिक्षण सुविधा
- बॉयलर प्रशिक्षण सुविधा
- स्टीमट्रैप प्रशिक्षण सुविधा
- खुला बर्नर प्रशिक्षण सुविधा और
- दहन भट्टी प्रशिक्षण सुविधा

डोमेन विशिष्ट सेवाएं

कृषि व्यवसाय सेवाएं:

कृषि-व्यवसाय समूह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए सूक्ष्म और वृहत दोनों स्तरों पर कृषि, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए परामर्श एवं जागरूकता लाने में संलग्न है। इसका बल इस पर है कि सामाजिक आकांक्षाएं प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं को मितव्ययी, लक्ष्य उन्मुख, गतिशील सामाजिक-आर्थिक माहौल के प्रति अनुक्रियाशील बनाया जाए।

कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में एनपीसी की ताकत निम्नलिखित में निहित है:

- विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन
- नीति निर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन
- ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास योजनाएं बनाना
- सहकारी उन्नति
- डाटा बेस तैयार करना
- फसल उत्पादकता में सुधार
- कृषि व्यवसाय और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन
- प्रौद्योगिकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन
- खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी एवं मुर्गी पालन प्रसंस्करण उद्योगों में उत्पादकता मापन एवं संवर्धन
- खाद्य और कृषि-व्यवसाय में मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, संगष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन
- खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) और गोदामों के खाद्य सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना

- **आर्थिक सेवाएं**

एनपीसी के आर्थिक सेवाएं समूह को संबंधित प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और सामाजिक कारक चिह्नित करने और इकाई, क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के विश्लेषण के उद्देश्य से वृहत और उप-वृहत स्तर की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययनों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

आर्थिक सेवाएं समूह ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न बाहरी पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। इन मूल्यांकन अध्ययनों ने योजनाएं संशोधित करने और उन्हें अधिक उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मूल्यांकन अध्ययनों के अलावा, आर्थिक सेवाएं समूह उत्पादकता पत्रिका (त्रैमासिक) के 4 विशेष अंक लाया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता वार्षिकी 2020 तैयार करने में एनपीसी ने आईएमडीस्विट्जरलैंड को भागीदार संस्थान सेवाएं भी प्रदान की हैं।

एपीओ उत्पादकता डाटाबुक 2020 के आगामी प्रकाशन के लिए आर्थिक सेवाएं समूह ने एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) जापान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ सेवाएं भी प्रदान की हैं।

इस प्रभाग में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञों की मुख्य टीम है। समूह की मुख्य क्षमता निम्नलिखित में निहित है:

- क्षेत्र-वार / उद्योग / उत्पाद प्रोफाइल अध्ययन
- बाजार संभावना आकलन
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव अध्ययन
- नीति फोकस / प्रभाव अध्ययन
- उत्पादकता डेटा-बेस तैयार करना
- उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता अध्ययन
- सरकारी योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन
- विपणन और उत्पाद संवर्धन अध्ययन

- **ऊर्जा प्रबंधन**

एनपीसी का ऊर्जा प्रबंधन (ईएम) प्रभाग1964 से परामर्श/प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान कर रहा है। लगभग २० बीईई प्रमाणित ऊर्जा ऑडिटर ईएम पेशेवरों की मुख्य नफरी में शामिल हैं। इस प्रभाग की विशेषज्ञ सेवाओं के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- सभी प्रकार के उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों एवं प्रतिष्ठानों, विद्युत उत्पादन संयंत्रों, वितरण प्रणाली में ऊर्जा प्रबंधन और ऑडिट
- औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान देने सहित मांग पक्ष प्रबंधन संभावना
- वरिष्ठ, मध्यम एवं शॉप स्तर के अधिकारियों के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नीतिगत पहलू सुदृढ़ करना और ऊर्जा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना
- क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन और संसाधन संरक्षण
- ऊर्जा दक्षता में एपीओ सदस्य देशों के प्रति तकनीकी विशेषज्ञता सेवाएं
- ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र में क्रियाशील प्रशिक्षण और डॉ. अंबेडकर उत्पादकता संस्थान, चेन्नई के क्षेत्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में भारत-जापान परियोजना।

- **पर्यावरण प्रबंधन**

पर्यावरण प्रबंधन समूह उत्पादकता सुधार के अनुरूप अपशिष्टन्यूनीकरण और प्रदूषण रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण संबंधी सेवाओं में निगरानी एवं विश्लेषण, प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का डिजाइन और संसाधन संरक्षण शामिल हैं। 1985 में प्रारंभ किए गए भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग की सहायता से इस समूह ने पर्यावरण प्रबंधन में विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता निर्मित की है।

समूह ने लघु एवं मध्यम उद्यमों और बड़े उद्योगों, केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केंद्र/राज्य स्तर पर पर्यावरण और वन मंत्रालयों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित 2500 से अधिक उद्यमों की सहायता की है। यह समूह एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) और सार्क सदस्य देशों के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्वच्छ उत्पादन
- ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन
- सीआईएस एवं क्षेत्रीय पर्यावरण नियोजन
- जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण
- हरित उत्पादकता।
- पर्यावरण ऑडिट और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

- **मानव संसाधन प्रबंधन**

संगठनों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एचआरएम समूह मानव संसाधनों के सतत विकास और संवृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- श्रमशक्ति नियोजन एवं इसे तर्कसंगत बनाना
- संगठन पुन: डिजाइन अध्ययन
- मानव संसाधन नीति और मैनुअल समीक्षा अध्ययन
- सक्षमता / कौशल मैपिंग / आकलन
- प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन एवं विश्लेषण
- पुनः तैनाती के लिए परामर्श एवं पुन: प्रशिक्षण
- नौकरी/कर्मचारी/ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण
- प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
- निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
- समग्र ऑफ़लाइनभर्ती समाधान
- नौकरी विवरण / विनिर्देश समीक्षा एवं डिजाइनिंग
- टीम कार्य एवं टीम प्रबंधन
- क्रांतिकारी नेतृत्व एवं आत्म-प्रेरण
- संचार एवं प्रस्तुति कौशल
- समस्या समाधान एवं निर्णय लेना
- तनाव और समय प्रबंधन
- मनोवृत्ति परिवर्तन एवं कार्य संस्कृति
- ज्ञान प्रबंधन
- प्रभावी कार्यालय प्रबंधन
- आरटीआई अधिनियम कार्यक्रम
- कार्यालय प्रक्रियाओं संबंधी कार्यक्रम

- **सूचना प्रौद्योगिकी**

ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतें पूरी करने के लिए मजबूत सिस्टम कौशलों के साथ उत्कृष्ट ज्ञान और कौशल-आधार आईटी समूह की प्रमुख ताकत है। परामर्श और प्रशिक्षण इसके प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र हैं।

एनपीसी, आईटी समूह ई-गवर्नेंस/आईसीटी परियोजनाओं/ज्ञान प्रबंधन और वेब आधारित एप्लिकेशन तैयार करने के लिए रणनीतिक नीति एवं नियोजन संबंधी मामलों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह सेवाएं विभिन्न संगठनों के आईटी-संबंधित क्षेत्रों में कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण पहलों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार दी जाती हैं।

आईटी समूह द्वारा निम्नलिखित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग और आईसीटीपहलों का अनुपालन ऑडिट
- ई-गवर्नेंसपहलों का आकलन और प्रचार-प्रसार
- ज्ञान प्रबंधन कार्यान्वयन और आकलन
- आईसीटी परियोजना कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं
- संगठनात्मकआईसीटी नीति के लिए रणनीतिक नियोजन
- वेब आधारित एप्लिकेशन तैयार करना
- आईसीटी में नवाचारों का संवर्धन एवं आकलन

एनपीसी, आईटी समूह प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। समय-समय पर सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, एनपीसी विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण सेवाएं भी प्रदान करती है। आईटी समूह द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ज्ञान एवं नवाचार प्रबंधन
- आईसीटीरणनीतिक नियोजन
- सूचना जोखिम प्रबंधन और आईएसएमएस
- सरकारी क्षेत्र में कार्यालय प्रबंधन के लिए आईटी एप्लिकेशन्स
- उन्नत आईसीटी उपकरण और तकनीकें
- आईसीटी के माध्यम से संगठनात्मक निष्पादन में वृद्धि

- **औद्योगिक इंजीनियरिंग**

औद्योगिक इंजीनियरिंग समूह उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रक्रिया सुधार पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है। परामर्श, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के माध्यम से यह समूह अपने कौशलों और अनुभव को रचनात्मक रूप से संगठन के निष्पादन को गहराई से प्रभावित करने वाले और वृद्धि एवं सफलता की नींव रखने वाले घटकों पर लागू करता है। संगठनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:

- सर्वोत्तम व्यवहार मानदंड
- प्रक्रिया और उत्पादकता सुधार अध्ययन
- संगठनात्मक पुनर्संरचना और जनशक्ति को तर्कसंगत बनाना
- न्यूनतम अपशिष्ट में अधिकतम उत्पादन
- उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं
- सिक्स सिग्मा
- आईएसओ 9001: 2015 और गुणवत्ता प्रबंधन
- ईएफक्यूएम/एमबीएनक्यूए व्यवसाय उत्कृष्टता ढ़ांचे पर आधारित मूल्यांकन
- परियोजना प्रबंधन
- समय एवं गति अध्ययन

- **प्रौद्योगिकी प्रबंधन**

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भौतिक संपत्ति उत्पादकता में सुधार लाना प्रौद्योगिकी प्रबंधन सेवाओं का लक्ष्य है। परामर्श परियोजनाएं निष्पादित करने और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान प्रदर्शन प्रदान करने के लिए नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त किए गए हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- ५ एस (S) कार्यान्वयन एवं प्रमाणन
- प्रौद्योगिकी मूल्यांकन अध्ययनसकल उत्पादक अनुरक्षण
- सुरक्षा एवं जोखिम आकलन तथा ऑडिट
- अनुरक्षण प्रणालियां
- स्थिति जाँचना
- अनुरक्षण ऑडिट
- बाहरी पक्ष आरटीआई पारदर्शिता ऑडिट

एनपीसी पेशेवरों ने जीटीजेड, जर्मनी; फ्रॉनहोफर सूचना केंद्र बेंचमार्किंग, जर्मनी; सेंटर फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन, इंग्लैंड; पीआईएमएस, इंग्लैंड; अमेरिकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता केंद्र, अमेरिका;जेरेटथोर इंटरनेशनल, अमेरिका; एशियाई उत्पादकता संगठन, टोक्यो; विश्व श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर काम किया है।

अन्य पहलें

पारदर्शिता पहलें

एनपीसी भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और इसकी कार्यप्रणाली भलीभांति परिभाषित और पारदर्शी मानदंडों पर आधारित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता, सक्रिय प्रकटीकरण और सांविधिक दायित्वों के अनुपालन संबंधी अपने लक्ष्यों का पालन करते हुए, एनपीसी प्रभावी रूप से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी प्रदान कर रही है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सांविधिक दायित्वों के पालन के लिए जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं। सीपीआईओ, पीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के विवरण एनपीसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सतर्कता बढ़ाना

सतर्कता एनपीसी प्रबंधन प्रकार्यों का अभिन्न अंग है। प्रभावी जांच और नियंत्रण उपायों से भलीभांति निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ-साथ मजबूत प्रणालियों और कार्य-पद्धतियां सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। इसमें एनपीसी प्रबंधन को जानकारी में रखते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी (भारत सरकार द्वारा नियुक्त) द्वारा किए जाने वाले निवारक निगरानी और दंडात्मक उपाय शामिल हैं। 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। हिंदी और अंग्रेजी में शपथ दिलाकर इससे संबंधित गतिविधियां शुरू की गईं।

निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन और गैर-अर्जक संपत्तियों से संबंधित डेटा का अनुरक्षण, वार्षिक संपत्ति विवरणों और अनुबंधों की छानबीन और औचक जांच जैसे निगरानी उपाय किए गए।

आउटसोर्सिंग

कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिए, एनपीसी अनुबंध आधार पर उपयुक्त कार्मिक नियुक्त कर रही है। आउटसोर्स किए गए व्यक्तियों के प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और आउटसोर्स की गई सेवा की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर के अनुरूप हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। किसी एजेंसी के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के मामले में, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सेवा प्रदाता स्थानीय सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार और अन्य सांविधिकअपेक्षाओं के अनुरूप एनपीसी में तैनात व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करे।

एनपीसी पुस्तकालय

एनपीसी में 20220 से अधिक पुस्तकों, जर्नल्स, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टों, एपीओ की उत्पादकता जर्नल्स, पत्रिकाओं, तकनीकी जर्नल्स आदि सहित भलीभांति सुसज्जित पुस्तकालय है। इसमें दिल्ली और कुछ महानगरों से प्रकाशित हिंदी के 12 समाचारपत्रों सहित 29 दैनिक समाचारपत्र उपलब्ध होते हैं। सूचना संग्रहण और पुनर्प्राप्ति के लिए पुस्तकालय लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम (LIBSYS 4X) का उपयोग करता है।

ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

ज्ञान प्रबंधन किसी भी संगठन के सकलज्ञान प्रबंधन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। इससे संगठन के कर्मचारियों के लिए अपना ज्ञान प्रदान करने, साझा करने और चर्चा करने के लिए एक मंच बनाने में सहायता मिलती है। एनपीसी का ज्ञान प्रबंधन पोर्टल अध्ययन रिपोर्टों, नीतिगत दस्तावेजों, प्रशिक्षण नियमावलियों, प्रस्तावों, प्रशासनिक सूचनाओं, ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन आदि का संग्रह है।

2021-22 के दौरान मुख्य गतिविधियों की गहन जानकारी

हिंदी पखवाड़ा

14 सितंबर 2021 से 28 सितंबर 2021 के बीच की अवधि के दौरान एनपीसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। इस अवधि के दौरान हिंदी वाद-विवाद, हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ, श्रुतलेख आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं ताकि कर्मचारियों को हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रतियोगिताओं की प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया। कोविड प्रतिबंधों के कारण अधिकांश कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे।

शासी निकाय बैठक

29 मार्च 2022 को डीपीआईआईटी में श्री अनुराग जैन, आईएएस,भारत सरकार के सचिव, डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयकी अध्यक्षता में एनपीसी की शासी निकाय की १११वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, फिक्की, इंटक, एआईएफएलपीसी (अखिल भारतीय स्थानीय उत्पादकता परिषद फेडरेशन) आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एनपीसी ने पिछले तीन वर्षों (2018-2021) की गतिविधियों और प्रमुख परियोजनाओं की अपनी मुख्यझलकियां प्रस्तुत कीं। एनपीसी ने एनपीसी के डिजिटलरूपांतरण और वित्तीय वर्ष 2018 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021 की अवधि के लिए एनपीसी के वित्तीय निष्पादन जैसी नई पहलों पर चर्चा की।

इसके अलावा, एनपीसी ने भविष्य के लिए नियोजित गतिविधियों पर भी चर्चा की।इन गतिविधियों में 2047 में अमृत काल और एनपीसी, अभिनव तथा टिकाऊ राजस्व प्रवाहों की प्रगति, दीर्घकालिक तथा उच्च मूल्य अखिल भारतीय परियोजनाओं को एनपीसी के विशिष्ट क्षेत्रों में बदलना, नए राजस्व प्रवाहों का विस्तार करना औरसूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उन्नयन शामिल हैं।

उत्पादकता संवर्धन

एनपीसी की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी, तब से एनपीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को अपने स्थापना दिवस को उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फरवरी 2022 में, एनपीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, निजी संगठनों में आगे वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके "उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता"थीम पर "उत्पादकता माह 2022"मनाया और लगभग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता व्यवहार सिखाने के लिए लगभग 1881 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

उत्पादकता सप्ताह मुख्य कार्यक्रम:

उत्पादकता सप्ताह 2022 के दौरान एनपीसी क्षेत्रीय निदेशालय, गुवाहाटी ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के सहयोग से कुल 2 (दो) वेबिनार आयोजित किए। इनमें 15 फरवरी 2022 को "ऊर्जा बदलाव में हाइड्रोजन ईंधन परिप्रेक्ष्य" और 17 फरवरी 2022 को "सकल शून्य उत्सर्जन एवं भविष्य का मार्ग" विषयों पर लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम आईओसीएल, गुवाहाटी द्वारा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। (तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं)

(Bhupendra Patel)
Chief Minister, Gujarat State

Date : 10.02.2022

MESSAGE

The right production process for each organization typically depends on factors like available technology, equal quantity of each product, how many products the company needs to produce and organization structure as well. Gujarat has established itself as a global business destination for next generation sustainable manufacturing and service industry that stimulate development and balanced regional growth. **Father of the nation Mahatma Gandhi** was earnest on the idea of Swadeshi towards making our country **"Atma-Nirbhar"**.

I am much pleased to learn that after formation of the **National Productivity Council in 1958**, 12-18 February of each year is being observed as **"Productivity Week"** to enhance productivity consciousness across all sectors of the company throughout the country. It is my appeal to all citizens and industries of the state, that during the forthcoming Productivity week, please adopt modern concepts of **Productivity improvement, and take-up "Make in India and Vocal and Local as the new definition of Swadeshi to attain self-reliance"** for further socio-economic growth and enhanced economic opportunities in Gujarat State. I convey my best wishes to National Productivity Council, Gandhinagar for conducting productivity improvement related activities in the state.

(Bhupendra Patel)
Chief Minister, Gujarat State

National Productivity Council

राज्य में उत्पादकता संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए गुजरात राज्य में स्थानीय उत्पादकता परिषदों और अन्य हितधारकों से समन्वय करते हुए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री का संदेश हितधारकों तक पहुंचाया गया।

आंतरिक हितधारकों और कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, गांधीनगर के कार्यालय में उत्पादकता अवधारणाओं पर सत्र आयोजित किए गए।

नई पहलें

ग्रामीण पहुंच के लिए आईपीएल केंद्र की स्थापना

इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने एनपीसी के साथ मिलकर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के जुड़ाव, तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों से आईपीएल ग्रामीण पहुंच केंद्र (आईसीआरओ) स्थापित किया है। आईसीआरओ की स्थापना आईपीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में की गई है । इसमें आईसीआरओ की परियोजना के निष्पादन में एनपीसी अपनी सेवाएं प्रदान करेगी और तीन वर्ष की अवधि के लिए इस परियोजना में अखिल भारतीय गतिविधियां होंगी। ग्रामीण पहुंच कार्यक्रमों का संचालन, अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अध्ययन, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा/जल ऑडिट, प्रशिक्षु कार्यक्रम आदि आईसीआरओ द्वारा एनपीसी के माध्यम से की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं।

प्रमुख नियत कार्यों का संक्षिप्त विवरण

❖ **टैंजेडको (TANGEDCO), तमिलनाडु के पांच तापीय विद्युत स्टेशनों में कार्य आवंटन और कर्मचारी पैटर्न की समीक्षा संबंधी अध्ययन**

तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैंजेडको) ने एआईपी, एनपीसी को नामांकन के आधार पर अपने पांच तापीय विद्युत स्टेशनों में कार्य आवंटन और कर्मचारी पैटर्न की समीक्षा करने संबंधी परियोजना सौंपी।

यह अध्ययन टूटीकोरिन तापीय विद्युत स्टेशन (टीटीपीएस) में पूरा किया गया। इसमें 11 प्रभागों में 42.3% जन शक्ति जरूरत को सर्वोत्कृष्ट बनाया गया।

इसके अलावा, एनपीसी द्वारा प्रत्येक प्रभाग और पूरे टीटीपीएस के लिए उत्पादकता में सुधार के लिए सिफारिशें दी गईं जिन्हें टैंजेडको के प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया।

उत्तरी चेन्नई तापीय विद्युत स्टेशन-II (एनसीटीपीएस-II) में अगले चरण का अध्ययन संचालित किया जा रहा है।

थूथुकुड़ितापीय विद्युतस्टेशन, तमिलनाडु

कोल जेट्टी, टीटीपीएस में एनपीसी टीम

❖ **ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा ऑडिटर्स के लिए 21वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का आयोजन**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की तरफ से 25 एवं 26 सितंबर 2021 को पूरे भारत में 24 केंद्रों पर २१वीं राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा (एनसीई) आयोजित की गई। इस परियोजना का कुल मूल्य जीएसटी के बिना 1,99,92,450/- था। परीक्षा के लिए कुल 5641 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया थाजिनमें से 592 उम्मीदवारों ने ऊर्जा प्रबंधक के रूप में और 179 ने ऊर्जा लेखा ऑडिटर के रूप में अर्हता प्राप्त की है। एनपीसी ने अब तक 9631 प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों और 10609 ऊर्जा ऑडिटरों का पूल तैयार किया है। इन लोगों से संवर्धित ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन की पूर्ति में सहयोग मिलता है।

परीक्षा केंद्र

परीक्षा टीम – चेन्नई केंद्र

❖ **बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत बॉयलर प्रचालन इंजीनियर (बीओई) के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र (सीओपी) प्रदान करने के लिए 11 और 12 दिसंबर 2021 को आयोजित परीक्षा**

केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड (सीबीबी), डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारने एआईपी, एनपीसीको "बॉयलर प्रचालन इंजीनियर (बीओई)" के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। इसकी कुल कीमत 85.77 लाख रुपए है। 11 और 12 दिसंबर 2021 को पूरे भारत में 17 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। इसमें कुल 3196 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। 2756 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए और इनमें से 1893 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की और मौखिक परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हता प्राप्त की।

इससे एआईपी, एनपीसी देश के विभिन्न राज्यों में बाजार में प्रमाणित बीओई की जरूरत और उपलब्धता के अंतर को कम करने में सीबीबी की सहायता करने के अलावा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तर पर बार-बार परीक्षा आयोजित करने के अतिरेक को कम करने में सक्षम हो पाया।

श्री टीएसजी नारायणन, तकनीकी सलाहकार (बॉयलर)

श्री टीएसजी नारायणन द्वारा चेन्नई केंद्र के निरीक्षण की झलक

❖ **डीजल लोकोमोटिववर्क्स (डीएमडब्ल्यू), पटियाला के नियत कार्य के हिस्से के रूप में 200वें वैप (WAP) 7 रेल इंजन संख्या 39184 के सभी उत्पादन प्रचालनों का अध्ययन**

एनपीसी, चंडीगढ़ ने "समूह प्रोत्साहन योजना की समीक्षा" के संबंध में डीजल लोकोमोटिववर्क्स (डीएमडब्ल्यू), पटियाला (पंजाब), रेल मंत्रालय के नियत कार्य के हिस्से के रूप में 200वें वैप लोको संख्या 39184 के सभी उत्पादन प्रचालनों का समय अध्ययन पूरा किया और 22-09-2021 को श्री एस एन दूबे, प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू पटियाला द्वारा झंडी दिखाकर रेल इंजन को रवाना किया गया।

200वां वैप रेल इंजनसंख्या39184

❖ एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला की जल, सौर, पवन और तापीय परियोजनाओं का जोखिम मूल्यांकन अध्ययन

एनपीसीचंडीगढ़ ने एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला की जल, सौर, पवन और तापीय परियोजनाओं का जोखिम मूल्यांकन किया और जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं तैयार कीं। एसजेवीएन के मौजूदा व्यवहारों में खामियां निर्धारित करने और खामियां दूर करने के लिए आईएसओ31000: 2018 में निर्धारित सर्वोत्तम व्यवहार चिह्नित करने के लिए खामियों का आकलन किया गया।

जोखिम आकलन अध्ययन के लिए एसजेवीएन और एनपीसी के अधिकारियों की बैठक

❖ ट्रिब्यून ट्रस्ट की जनशक्तिमैपिंग/जनशक्ति आकलन अध्ययन

एनपीसी, चंडीगढ़ ने ट्रिब्यून प्रिंटिंग के चंडीगढ़, जालंधर, भटिंडा और गुरुग्राम में स्थित केंद्रों और दिल्ली, जालंधर, भटिंडा और गुरुग्राम में स्थित ट्रिब्यून उप कार्यालयों में जनशक्तिमैपिंग / जनशक्ति आकलन अध्ययन किया। संपादकीय एवं व्यवसाय प्रचालनों और अन्य संबद्ध गतिविधियों में जनशक्ति को तर्कसंगत बनाकर ट्रस्ट संचालन की दक्षता में सुधार लाना अध्ययन का उद्देश्य था।

❖ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के लिए बिजली सुरक्षा की मूल बातों पर जागरूकता कार्यक्रम

क्षेत्रीय निदेशक, चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय बिजली सुरक्षा सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के लिए बिजली सुरक्षा की मूल बातों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एचपीसीएल के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एचपीसीएल के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए यह कार्यक्रम जूमप्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के लिए बिजली सुरक्षा की मूलभूत बातों पर जागरूकता कार्यक्रम

❖ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के लिए संगठनात्मक अध्ययन:

एनपीसीमुख्यालय से कार्य करते हुए आरएम एवं सीओई समूह ने गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के लिए 'संगठनात्कपुनर्संरचना और मानव संसाधन नीति समीक्षा' शीर्षक से मानव संसाधन अध्ययन किया।

भर्ती, पदोन्नति, निष्पादन प्रबंधन, प्रशिक्षण और स्थानांतरण एवं कार्य परिवर्तन से संबंधित उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों से मानव संसाधन के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए कुशल और प्रभावी संगठन संरचना का सुझाव देना और सिफारिश करना इस अध्ययन का उद्देश्य था। इस अध्ययन का लक्ष्य यह था कि प्रत्येक विभाग के कामकाज और सभी विशिष्ट भूमिकाओं के लिए काम के विवरण की समीक्षा के साथ-साथ अहर्ताओं/अनुभव आदि के अनुसार पद भरने के लिए महत्वपूर्ण पदों और कौशलों की जरूरत चिह्नित की जाए।

❖ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के लिए संगठनात्मक अध्ययन एवं भर्ती :

भारत के विदेशी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान देने के लिए 1963 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में आईआईएफटी की स्थापना की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, आईआईएफटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन और रणनीति पर ध्यान देने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है और संस्थान की सभी तीन प्रमुख गतिविधियों: अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा में यह ध्यान परिलक्षित होता है।

आईआईएफटी के प्रचालनों के वर्तमान और भविष्य के स्तर के लिए संस्थान का सही आकार तय करने, संगठनात्मक रणनीति से भलीभांति संरेखित भूमिकाओं के साथ एक नई या बेहतर संरचना का सुझाव देने, भर्ती नियमों (आरआर) की समीक्षा करने और मसौदा बदलाव योजना तैयार करने और बदलाव की अवधि के दौरान जरूरी सहयोग के लिए बजट तय करने के लिए एनपीसी द्वारा अध्ययन किया गया।

❖ दालों के बफर भंडार की नीति का प्रभाव मूल्यांकन

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्षेत्र सहित देश में उपभोक्ता संरक्षण की नोडल एजेंसी है। दालों की कीमतें स्थिर करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना कार्यान्वित की जा रही है। उपरोक्त योजना के प्रभाव आकलन की दृष्टि से, उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली को २०१६-१७ से २०१९-२० तक देश में दालों के उत्पादन, आयात, निर्यात, उपलब्धता और मांग की समीक्षा, दालों की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर, बफर स्टॉक की अवधारणा और दालों के बफर भंडार के मानदंड - बफर भंडार की खरीद एवं निपटान और दालों की खरीद, परिवहन, दालों के भंडारण और निपटान से जुड़े बफर भंडार की परिचालन दिक्कतें जैसे प्रमुख विचारार्थ विषयों सहित अध्ययन का उत्तरदायित्व सौंपा है।

❖ उत्तराखंड में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का प्रभाव मूल्यांकन

देश में डेयरीपालन की बुनियादी संरचना तैयार और मजबूत करने के उद्देश्य से डेयरी और पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी, 2014-15 में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्ता पूर्ण दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना तैयार करना एवं इसे मजबूत बनाना और किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ना योजना का मूल उद्देश्य है। उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड सहकारी डेयरीपरिसंघ (यूसीडीएफ) द्वारा अपने जिला सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन किया जा रहा है। उत्तराखंड सहकारी डेयरीपरिसंघ राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) है और जिला दुग्ध संघ (डीएमयू) एनपीडीडी योजना की अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियां (ईआईए) हैं। एनपीसी द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन किया गया। अध्ययन के तहत पांच जिलों नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर को शामिल किया गया। इन चयनित जिलों में आगे 5 जिला दुग्ध संघों, 5डेयरी संयंत्रों, 2बल्क दुग्ध कूलर्स, 38डेयरी सहकारी समितियों और 230 उत्पादक सदस्यों को शामिल किया गया है।

❖ सीएसआईआर-आईएचबीटी द्वारा विकसित जंगली गेंदा की कृषि प्रौद्योगिकियों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सीएसआईआर-आईएचबीटी ने कृषि-प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण किया है और 2001 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 'हिमगोल्ड' नामक उन्नत किस्म जारी की है। यह प्रौद्योगिकियां कृषि और प्रसंस्करण के लिए बड़ी संख्या में किसानों को उपलब्ध कराई गईं ताकि इनका व्यावसायिक उपयोग हो सके। 15 से अधिक वर्षों से प्रौद्योगिकी प्रसार के साथ; जंगली गेंदा (टैगेटेसमिनुटा) के लिए कृषि-प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना सीएसआईआर-आईएचबीटी का उद्देश्य है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को "जंगली गेंदा संबंधी कृषि प्रौद्योगिकियों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव" शीर्षक से अध्ययन सौंपा गया था। प्रौद्योगिकी का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मापने के लिए, मुख्य हितधारकों से फीडबैक ली गई।

चार राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में यह अध्ययन किया गया। सीएसआईआर-आईएचबीटी की जंगली गेंदा प्रौद्योगिकियों के लिए चयनित लाभार्थियों के अध्ययन के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर से कुल ७४ नमूने शामिल किए गए।

❖ मौजूदा पीएलबीएस की समीक्षा और नई उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना (पीएलबीएस) की पुनर्संरचना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एनपीसी को नई पीएलबी योजना तैयार करने के साथ-साथ समूह 'सी' कर्मचारियों के लिए मौजूदा उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना की समीक्षा/मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन सौंपा। यह अध्ययन ईएसआईसी प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली; क्षेत्रीय कार्यालय-दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता, क्षेत्रीय कार्यालय-वडोदरा, क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय-जयपुर और क्षेत्रीय कार्यालय-चेन्नई जैसे ०६ क्षेत्रीय कार्यालयों, डीसीबीओ-फाल्टा (पश्चिम बंगाल), एसआरओ-नोएडा और शाखा कार्यालय-नोएडा, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, केके नगर, चेन्नई; ईएसआईसी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली में किया गया । अध्ययन पूरा हो गया है और अध्ययन रिपोर्ट अनुमोदन के लिए ईएसआईसी को प्रस्तुत की गई है।

❖ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता पर आधारभूत सर्वेक्षण

मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवंडेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने मई 2020 में देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदारी पूर्ण विकास के लिए रु. 20,050 करोड़ के निवेश से प्रधान मंत्री मत्स्यसंपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के नाम से महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी।भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए एनपीसी को पीएमएमएसवाई की अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के रूप में अधिसूचित किया है।

एनपीसी को "भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के उत्पादन और उत्पादकता पर आधारभूत सर्वेक्षण" संबंधी अध्ययन सौंपा गया। यह अध्ययन 18 प्रमुख मछली उत्पादक राज्यों: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और तेलंगाना, में आयोजित किया गया है। अध्ययन में 1000 मछली पालकों को शामिल किया गया है।

केरल राज्य के कोल्लम जिले में समुद्री पिंजरों का उपयोग करके मछली पालन

मां संतोषी स्वयं सहायता समूहमानेश्वर, अरडा, संबलपुर/ओडिशा के टैंक में मछली पालन

❖ भांडागारण विकास एवं विनियामक अधिनियम के तहत डब्ल्यूडीआरए के लिए गोदामोंका भौतिक निरीक्षण

एनपीसी क्षेत्रीय निदेशालय हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भारतीय खाद्य निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी संस्थाओं के गोदामों का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की।

राज्य भंडागारणनिगम-गोदाम, वारंगल, तेलंगाना राज्य के प्रबंधक और कर्मचारियों के साथ एनपीसी टीम

❖ आईबीए नामिकायन के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निजी सिक्योर प्रिंटरों का निरीक्षण

एनपीसी क्षेत्रीय निदेशालय हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में आवंटित निजीसिक्योर प्रिंटरों का निरीक्षण किया और आईबीए, मुंबई को निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी।

❖ डीपीआईआईटी, भारत सरकार के लिए एमआईआईयूएस योजना की परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए)

एमआईआईयूएस योजना के लिए पीएमए के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए एनपीसी मुख्यालय ईसीए समूह से समन्वय करते हुए एनपीसीआरडी हैदराबाद ने मेडक जिले के पाशामायलाराम औद्योगिक क्षेत्र का फील्ड दौरा किया है। इस योजना को कुल १०४.२४ करोड़ रुपए के परियोजना मूल्य के साथ स्वीकृत किया गया है जिसमें से तेलंगाना राज्य को २५.७६ करोड़ का केंद्रीय अनुदान मिलेगा और इसमें टीएसआईआईसी को एसआईए के रूप में नामित किया गया है। फील्डविजिट के दायरे और विचारार्थ विषयों के सभी पहलू शामिल करते हुए फील्डविजिट रिपोर्ट डीपीआईआईटी को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दी गई है।

तेलंगाना राज्य के मेडक जिले के पाशामायलाराम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एमआईआईयूएसपरियोजना कार्यों में टीएसआईआईसी अधिकारियों और हितधारकों के साथ एनपीसीटीम

❖ **मत्स्य विभाग, भारत सरकार के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन के उत्पादन और उत्पादकता पर आधारभूत सर्वेक्षण**

"अंतर्देशीय मत्स्य पालन के उत्पादन और उत्पादकता पर बेस लाइन सर्वेक्षण" नामक परियोजना के लिए एनपीसीआरडी हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कुल 25 जिले शामिल करते हुए फील्ड अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया।

जिला मत्स्य अधिकारी, अनंतपुरम जिला, आंध्र प्रदेश राज्य कार्यालय परिसर में स्थित फिंगरलिंग तालाबों (उत्पादन इकाइयों) में जिला अधिकारियों और श्रमिकों के साथ एनपीसी टीम।

❖ **जीएमआर समूह [जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जीएमआर हैदराबाद वायु कार्गो और जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट विस्तार परियोजना] की व्यवसाय इकाईयों में 5एस (S) प्रणाली का कार्यान्वयन और प्रमाणन**

5एस की अखिल भारतीय टीम के हिस्से के रूप में आरडी हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित जीएमआर समूह की व्यवसाय इकाइयों के लिए 5एस प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रमाणन में संलग्न है। तदनुसार, आरडी हैदराबाद के टीम सदस्य इसमें संलग्न हैं और उन्होंने निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 5एस के कार्यान्वयन के लिए सफलतापूर्वक परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं।

❖ **बीईई, भारत सरकार की तरफ से ऊर्जा प्रबंधकों/ऊर्जा ऑडिटर्स के लिए एनसीई परीक्षा**

केंद्र निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी के रूप में एनपीसीआरडी हैदराबाद के उप निदेशक श्री वी. संजन्ना ने अखिल भारतीय परीक्षा कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र राज्य के नागपुर केंद्र में बीईई के लिए ईएम/ईए परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

❖ केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का बाहरी पक्ष मूल्यांकन: पैकेज॥ 2013 एवं आईडीएस2017

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को डीपीआईआईटी द्वारा दो योजनाओं के बाहरी पक्ष मूल्यांकन अध्ययन को निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें से पहली योजना "जम्मू-कश्मीर (पूंजीगत निवेश सब्सिडी, केंद्रीय ब्याज सब्सिडी और समग्र बीमा सब्सिडी) और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड (पूंजी निवेश सब्सिडी) के लिए के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं पैकेज॥ (2013)" और दूसरी योजना "संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए आईडीएस-2017) और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए (हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए आईडीएस-2017) औद्योगिक विकास योजना-2017" थी। एनपीसी अध्ययन दल ने माध्यमिक डेटा के विश्लेषण और संरचित प्रश्नावलियों एवं अनुसूचियों की सहायता से लाभार्थी एवं गैर-लाभार्थी इकाइयों, संवितरण एजेंसियों, राज्य उद्योग निदेशालय और संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और संघ शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के विभिन्न जिलों में जिला औद्योगिक केंद्रों और उद्योग संघों से गहन फील्ड स्तरीय साक्षात्कार के आधार पर दोनों रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

❖ स्वदेश दर्शन उत्तर-पूर्व सर्किट के तहत थेनजाल एवं साउथ जोत, जिला सेरछिप और रीक, मिजोरम में नए पर्यावरण-मित्र पर्यटन का एकीकृत विकास

पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को इस बारे में अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। "थेनजोल एवं साउथजोथ, जिला सेरछिप और रीक का एकीकृत विकास" के लिए स्वदेश दर्शन योजना उत्तर-पूर्व सर्किट के तहत यह परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है और दिसंबर 2019 में इसका शुभारंभ किया गया है। पर्यटन मंत्रालय चाहता है कि क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार सृजन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, पर्यटन बुनियादी संरचना के विकास, क्षेत्र में पर्यटन की भविष्य की संभावनाओं को मजबूती देने आदि को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार किया जाए। स्वदेश दर्शन उत्तर-पूर्व सर्किट के तहत थेनजाल एवं साउथ जोत, जिला सेरछिप और रीक, मिजोरम में नए पर्यावरण-मित्र पर्यटन संबंधी एकीकृत विकास परियोजना को 92.25 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि सहित मंजूरी मिली थी। इसमें से 64.48 करोड़ रुपए की राशि गोल्फ कोर्स सहित थेनजोल में विभिन्न घटकों के लिए स्वीकृत की गई थी। एनपीसी अध्ययन दल ने संरचित प्रश्नावली की सहायता से पर्यटन मंत्रालय, गोल्फ कार्यक्रम आयोजक, होटल/रेस्तरां/होम स्टे, ग्राम परिषदों/स्थानीय संघों आदि के साथ विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण किया और द्वितीयक डेटा विश्लेषण भी किया।

❖ आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा वार्षिकी 2018 (वार्षिक): भारत से भागीदार संस्थान

एनपीसी का आर्थिक सेवाएं समूह पिछले कई वर्षों से विश्व प्रतिस्पर्धा वार्षिकी के प्रकाशन में भारत से भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान (आईएमडी) लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड द्वारा विभिन्न देशों के भागीदारों के सहयोग से डब्ल्यूसीवाई २०२१ को लाया गया था। आईएमडीस्विट्जरलैंड के साथ संबंध डेढ़ दशक से अधिक समय से जारी है। आईएमडीस्विट्जरलैंडसे साझेदारी 2000 में शुरू हुई और यह सहयोग अब भी जारी है। डब्ल्यूसीवाई 2021विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकतारैंकिंग की रिपोर्ट करता है और इसमें 300 से अधिक कड़े (प्रकाशित) और मृदु (सर्वेक्षण) डेटाचरों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता का अनुमान लगाया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धा वार्षिकी का नवीनतम संस्करण वर्ष 2021 के लिए है। इसमें सर्वेक्षण प्रारूप के अनुसार 300 से अधिक मापदंडों के लिए कार्यपालक अधिकारी राय सर्वेक्षणों और (पिछले पांच वर्षों के लिए) द्वितीयक डेटा अनुमानों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत कोरैंकिंगदी गई है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता वार्षिकी (डब्ल्यूसीवाई) 2021में भारत ने 43वां स्थान बरकरार रखा।

❖ कोच्चिमेट्रो रेल लिमिटेड की प्रचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं संबंधी अध्ययन

- कोच्चि स्थित कोच्चिमेट्रो रेल लिमिटेड की'प्रचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं संबंधी अध्ययन का संचालन' शीर्षक से असाइनमेंट पूरीकी गई। इस चुनौती पूर्ण कार्य को आरडीबेंगलूर द्वारा पूरा किया गया। अगस्त 2020 में शुरुआत के बाद, कोविड-19 महामारी के दौरान और सभी कोविड-19 प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फील्ड अध्ययन और डेटा संकलन निष्पादित किए गए।

- २०२१-२२ में कोविड-१९ लॉकडाउन के दौरान एमसीएफ लिमिटेड, मैंगलोर में कैप्टिव पावर प्लांट के सह-उत्पादन प्रमाणन के लिए अध्ययन किया गया था।
- इस वर्ष कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित बॉश लिमिटेड संयंत्रों में 'कार्य विश्लेषण एवं स्तरीकरण' शीर्षक से नियत कार्य सफलतापूर्वक किया गया। कार्य के मूल्यांकन में आमतौर पर, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है और कार्य की महत्ता की गणना की जाती है। इस मामले में गतिविधि का मूल्यांकन किया गया था और अन्य गतिविधियों की तुलना में गतिविधि के महत्व और स्थिति को तालिकाबद्ध किया गया था। ग्राहक और एनपीसी दोनों के लिए यह अपनी तरह की पहली कवायद थी। ४ संयंत्रों में सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम सेग्राहक संगठन की अपेक्षाएं पूरी करके एनपीसी टीम ने नियत कार्य पूरा किया।
- एम.एस. रमैया अस्पताल में 'जनशक्ति आकलन अध्ययन' शीर्षक वाला नियत कार्य ग्राहक संगठन और एनपीसी दोनों के लिए अपनी तरह का पहला अध्ययन था, फिर भी इसे ग्राहक संगठन की संतुष्टि के अनुरूप पूरा किया गया। ग्राहक संगठन द्वारा अध्ययन सिफारिशों की काफी सराहना की गई।
- दक्षिण-पश्चिम रेलवे के केएसआर रेलवे स्टेशन, बेंगलूर स्थित कोचिंग डिपो में 'अग्नि सुरक्षा ऑडिट का संचालन' शीर्षक से नियत कार्य पूरा किया गया और ग्राहक संगठन ने इस पर अपनी संतुष्टि प्रकट की।

❖ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के 8 तकनीकी संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन

विकास आयुक्त- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को "८ तकनीकी संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन" का काम सौंपा गया था। यह मूल्यांकन निम्नलिखित ८ स्वायत्त संस्थानों में आयोजित किया गया:

- प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा
- प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ

- केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा
- केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा
- ग्लास उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
- फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज
- इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाएं एवं प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर
- विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई

अध्ययन के तहत एनपीसी ने पिछले 5 वर्षों में संस्थान के उद्देश्यों, उपलब्धियों और लाभार्थियों पर प्रभाव की समीक्षा की है। इस अध्ययन में प्राथमिक (प्रश्नावली सर्वेक्षण के माध्यम से) और द्वितीयक डेटा का संग्रह और हितधारकों की बैठकें आयोजित करना शामिल है। उनके मौजूदा बुनियादी ढांचे और उनकी वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा के लिए साइट दौरा भी किया गया था। विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण एवं व्याख्या किए गए और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट में संसाधनों के उपयोग के लिए वित्तीय अनुपातों की निगरानी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्राहक ने रिपोर्ट स्वीकार की और मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों और सुझावों को भविष्य की प्रौद्योगिकी अपेक्षाएं एकीकृत करने में सहायक पाया। इनसे संस्थान अपने संबंधित क्षेत्र में अग्रणी बन पाएंगे।

❖ भारत में गुणवत्ता सुधार के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (एचसीएफ) के लिए क्षमता निर्माण एवं नए काम में सहयोग के लिए प्रदर्शन परियोजना"

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने "भारत में गुणवत्ता सुधार के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (एचसीएफ) के लिए क्षमता निर्माण एवं नए काम में सहयोग के लिए प्रदर्शन परियोजना" के लिए पहल की है। एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ), टोक्यो, जापान द्वारा परियोजना के लिए वित्त पोषण सहायता उपलब्ध करवाई गई है। यह परियोजना केंद्र/राज्य सरकार के तहत 9 स्वास्थ्य सुविधाओं/अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में कार्यान्वित की जा रही है और इसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों में व्यापक अनुभव रखने वाले एनपीसीपैनलबद्ध सेवा प्रदाताओं/एजेंसियों से समर्थन प्राप्त है। एनपीसी सेवा प्रदाता/एजेंसियां 9 स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में अंतराल आकलन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) - राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) में प्रवेश स्तरीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए अस्पतालों के मार्गदर्शन एवं सहयोग में सहायता करती हैं। एनपीसी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली नए काम में सहायता के बाद अस्पताल मान्यता के लिए मानक अपेक्षाएं पूरी करने की स्थिति में होंगे और क्यूसीआई/एनएबीएच प्रवेश स्तरीय प्रमाणन के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे जिससे गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से अंततः रोगी लाभान्वित होंगे।

❖ खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक इन्वेंट्री का औचक सत्यापन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों के ऑडिटऔचकनिरीक्षणों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) को नियुक्त किया है। ऑडिट कवायद में अपशिष्टइन्वेंट्री का निरीक्षण, वैधानिक अनुमोदन प्रलेखन, उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा, खतरनाक अपशिष्टभंडारण क्षेत्र और औद्योगिक इकाइयों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशा में नियंत्रण शामिल है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त सुझावों और सिफारिशों सहितसीपीसीबी को ११ औद्योगिक इकाइयों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

❖ नालागढ़, सोलन, हिमाचल प्रदेश में टीएसडीएफ का बाहरी पक्ष पर्यावरण ऑडिट

एनपीसी ने मैसर्स शिवालिकसॉलिडवेस्टमैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा संचालित नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में उपचार, भंडारणएवं निपटान परिसर (टीएसडीएफ) स्थल का बाहरी पक्ष पर्यावरणऑडिट किया है। इस अध्ययन के तहत एनपीसी ने साइट और आसपास के स्थानों से भूजल, मिट्टी, परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन के प्रतिनिधि नमूनोंके संग्रह की निगरानी की है। विभिन्न पर्यावरण अनुपालनों, रिकॉर्ड और प्रलेखन को सत्यापित किया गया। आगे डेटा का विश्लेषण एवंव्याख्या किए गए, रिपोर्ट तैयार की गई और इसे ग्राहक को प्रस्तुत किया गया।

❖ डीपीआईआईटी में युवा पेशेवरों की नियुक्ति

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपाआईआईटी), भारत सरकार ने एनपीसी को युवा पेशेवर नियुक्त करने में विभाग की सहायता करने और सहयोग देने का काम सौंपा है। युवा पेशेवर के पद के लिए लगभग 224 उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से केवल 183 उम्मीदवार छांटे गए और उन्होंने अंतिम साक्षात्कार में भाग लिया।

❖ टीएसडीएफबीईआईएल का समग्र पर्यावरण ऑडिट

एनपीसी ने गुजरात के अंकलेश्वर में स्थित टीएसडीएफ (उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा), बीईआईएल का समग्र पर्यावरण ऑडिट पूरा किया। यह टीएसडीएफ परिसर कचरा प्रबंधन में अग्रणी है और खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए भारत में सबसे बड़े परिसरों में से एक है। यह गुजरात में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में काफी योगदान देता है और गुजरात के अंकलेश्वर, पनोली, झगड़िया आदि जिलों में स्थित उद्योगों की जरूरतें पूरी करता है। टीएसडीएफ, बीईआईएल के पास सुरक्षित लैंडफिल परिसर के 688 सदस्य उद्योग हैं और सामान्य भस्मीकरण प्रणाली के लिए 719 सदस्य हैं।

❖ दिल्ली, डीपीसीसी में सीबीडब्ल्यूटीएफ की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं

एनपीसीने दिल्ली में सीबीडब्ल्यूटीएफ की स्थापना के लिए परामर्शी सेवाओं का नियत कार्य पूरा किया।इसके तहत एनपीसीने निम्नलिखित गतिविधियां शुरू कीं: दिल्ली में अतिरिक्त सीबीडब्ल्यूटीएफकी संख्या और क्षमताओं की आवश्यकता का अंतर विश्लेषण; स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों से अपशिष्ट निर्माण कारक का अनुमान; बीएमडब्ल्यू प्रबंधन प्रणाली और सीबीडब्ल्यूटीएफ के स्थापना पैटर्न के अध्ययन के लिए 3 राज्यों में सफल बीएमडब्ल्यू प्रबंधन का अध्ययन; सीबीडब्ल्यूटीएफ की लागत का अनुमान; क्षमताओं और उपचार प्रौद्योगिकियों के विभिन्न संयोजनों के लिए वित्तीय मॉडलिंग; दिल्ली में मौजूदा परिचालन सीबीडब्ल्यूटीएफ का आकलन; जैव चिकित्सा अपशिष्ट सृजन और सीबीडब्ल्यूटीएफकी तद्नुसार जरूरत की भावी मांग का विश्लेषण और अंततः दिल्ली में लागू होने योग्य सबसे बेहतर मौजूदा बीएमडब्ल्यू प्रबंधन परिदृश्य को निर्धारित करना।

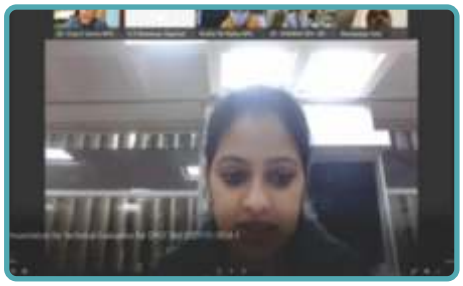

❖ पर्यावरण अनुपालन के लिए 3 स्तरीय निगरानी तंत्र तैयार करना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनपीसी को पर्यावरण अनुपालन पश्चात निगरानी के लिए 3 स्तरीय निगरानी तंत्र विकसित करने का काम सौंपा है। इस राष्ट्रीय प्रमुख परियोजना के तहत, अपने कार्यान्वयन भागीदारों एनईईआरआई, क्यूसीआईऔर जीआईजेड़के साथ एनपीसी निम्नलिखित में शामिल है:

- एसओपी और टेम्प्लेट तैयार करना
- प्रमाणित पर्यावरण ऑडिटर योजना तैयार करना
- वेबपोर्टल और ज्ञान उत्पाद तैयार करना
- एमओईएफ एवं सीसी, सीपीसीबी और एसपीसीबी के लिए क्षमता निर्माण जरूरत का आकलन करना
- पूरे भारत में उपलब्ध पुराने ईसीडेटा का आकलन और इसके बाद क्षेत्र-वार वर्गीकरण

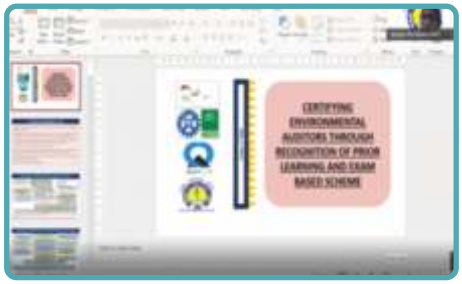

❖ संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) का मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एनपीसी के पर्यावरण एवं जलवायु कार्य समूहको "संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन" परियोजना सौंपी गई है। वर्ष 2012 में शुरू की गई इस योजना को ईएसडीएम क्षेत्र के परिवर्धन के समाधान के लिए क्रमिक रूप से विकसित दिशानिर्देशों और प्रतिभागी इकाइयों में प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन को सुगम बनाने, निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ कैपेक्स सब्सिडी (एसईजेड क्षेत्रों में इकाइयों के लिए 20% कैपेक्स सब्सिडी और गैर-एसईजेड क्षेत्रों में इकाइयों के लिए 25%) प्रदान करने के माध्यम से परिकल्पित योजना कवरेज के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध 44 क्षेत्रों/वर्टिकल्ससेसार रूप से संलग्न होने के माध्यम सेमजबूत किया गया है । वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, मोबाइल एवं सहायक उपकरण, उपभोक्ता उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर, पीसीबी, एलईडी, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि जैसे उप-क्षेत्रों के तहत आने वाली इकाइयों में 1189 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि संवितरण किया गया है । मूल्यांकन में बाजार परिदृश्य और आधारभूत रुझानों, निर्यात और आयात किए जाने वाले उत्पादों/कच्चे माल आदि की प्रकृति और प्रतिभागी इकाइयों की बिक्री विशेषताओं के बारे में, करोड़ रूपए के निवेश पर रोजगार सृजन संभावना, फर्मअनुसार निवेश की क्षेत्रीय और सेक्टर-वार विशेषताएं आदिपर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा अध्ययन में योजना के सूक्ष्म और वृहत् पहलुओं और इसकी अनुक्रिया शीलता, आवेदक अनुमोदनों की प्रक्रिया और प्रोत्साहन संवितरण की गति, प्रलेखन अपेक्षाओं और अनुकूलनों के दायरेकी छानबीन के साथ-साथ उद्योग एवं हितधारक की अपेक्षाएं, समस्याएं और बाधाएं दर्शाई गईं और साथ ही व्यवसाय करने में आसानी, वित्तीय अनुपातों, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों आदि के बारे में आगे बढ़ने पर भाग लेने वाली इकाइयों के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया गया और सेक्टर और योजना के अत्यधिक महत्व के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा आगे विचार किए जाने के लिए सुधारों के अतिरिक्त दायरे और सीमा की भी संस्तुति की गई।

पहलुओं और इसकीअनुक्रियाशीलता, आवेदक अनुमोदनों की प्रक्रिया और प्रोत्साहन संवितरण की गति, प्रलेखनअपेक्षाओं और अनुकूलनों के दायरेकी छानबीन के साथ-साथ उद्योग एवंहितधारक की अपेक्षाएं, समस्याएं और बाधाएं दर्शाई गईंऔर साथ ही व्यवसाय करने में आसानी, वित्तीय अनुपातों, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों आदि के बारे में आगे बढ़ने पर भाग लेने वाली इकाइयों के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया गयाऔर सेक्टर और योजना के अत्यधिक महत्व के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा आगे विचार किए जाने के लिए सुधारों केअतिरिक्त दायरे और सीमा की भी संस्तुति की गई।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का फील्ड दौरा

❖ उद्योगों का 5"एस"प्रमाणन

उच्च गुणवत्ता पूर्ण गृह-प्रबंध, अपशिष्ट नियंत्रण और सुरक्षित संचालन के व्यवहार और इसे बरकरार रखने के लिएउद्योगों द्वारा उपकरण के रूप में 5"एस" का उपयोग किया जाता है। '5एस' कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को प्रेरित करने और इसे चिह्नित करने के लिएएनपीसीप्रगति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणन प्रदान करती है। इस प्रमाणन योजना को अपनाने वाले उद्योगों के लिए आरडी भुवनेश्वर ने प्रमाणन ऑडिट और निगरानी ऑडिट सेवाएं संचालित कीं।

5'एस' निगरानीऑडिट के दौरान जीएमआरकमालांगाऊर्जा टीम के साथ एनपीसी टीम

❖ मुंबई और सूरत में मेगा सीएफ़सी की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, गांधीनगर कार्यालय को "मुंबई और सूरत में मेगा आम सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन संचालित करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने" के लिए परियोजना सौंपी है। एनपीसी ने पहले परियोजना के चरण। अर्थात "सूरत और मुंबई में मेगा सीएफ़सी की जरूरत और अपेक्षाओं के आकलन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन" संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एनपीसी द्वारा प्रस्तुत प्रथम चरण की रिपोर्ट जीजेईपीसी द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

अन्य संस्तुतियों सहित एनपीसी चरण। के अध्ययन का निष्कर्ष है कि सूरत और मुंबई क्षेत्रों में मेगा सीएफ़सी की जरूरत है और सूरत और मुंबई स्थानों पर मेगा सीएफ़सी व्यवहार्य और व्यावसायिक रूप से साध्य हैं। एनपीसी ने परियोजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में "मुंबई में मेगा सीएफ़सी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" भी प्रस्तुत की है। जीजेईपीसी ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मेगा आम सुविधा केंद्र अनिवार्यतः ऐसा स्थान हैजहां एक ही केंद्र में, विश्व भर से सर्वश्रेष्ठ 3टी (प्रौद्योगिकी, तकनीकें एवं प्रशिक्षण) उपलब्ध कराए जाएंगे। मेगा सीएफ़सी का उद्देश्य है कि सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक सभी कंपनियों को बेहद मितव्ययी और कुशल तरीके से 3टी का लाभ उठाने के समान अवसर दिए जाएं।

❖ अग्रणी टायर कंपनी में वायु प्रदूषण नियंत्रण डिवाइसेस का प्रदर्शन मूल्यांकन

एनपीसी, गांधीनगर कार्यालय ने एक अग्रणी टायर कंपनी में "वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के प्रदर्शन मूल्यांकन" पर अध्ययन किया है। उनके प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए एनपीसी ने विभिन्न वायु प्रदूषण नियंत्रण डिवाइसेस का फील्ड अध्ययन किया है और उत्सर्जन की निगरानी की है। निगरानी परिणामों की उत्सर्जन विसर्जन मानकों से तुलना की गई और इस बारे में रिपोर्ट किया गया। एनपीसी के मूल्यांकन अध्ययन से कंपनी को उनकी वास्तविक उत्सर्जन स्थिति/परिदृश्य चिह्नित करने और पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने की शर्तों के अनुपालन में सहायता मिली है।

❖ खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक इन्वेंट्री का औचक सत्यापन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एनपीसी, गांधीनगर कार्यालय को "खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक इन्वेंट्री के औचक सत्यापन" पर परियोजना सौंपी है। परियोजना के हिस्से के रूप मेंएनपीसी गांधीनगर के अधिकारियों ने इन कंपनियों द्वारा अपनाए गए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों के अध्ययन के लिए सीपीसीबी और जीपीसीबी अधिकारियों के साथ गुजरात, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली क्षेत्रों में स्थित कंपनियों का संयुक्त दौरा किया है और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए संस्तुतियों सहित संबंधित रिपोर्टें सीपीसीबी को प्रस्तुत की गई हैं।

❖ अहमदाबाद में औषध-निर्माण क्षेत्र के लिए "भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समूहों की ऊर्जा और संसाधन मैपिंग"

एनपीसी गांधीनगर ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत ऊर्जा एवं संसाधन मैपिंग अध्ययन पूरा किया।

परियोजना के पहले चरण में, एनपीसी ने विस्तृत डेटा संग्रह प्रश्नावली के माध्यम से अहमदाबाद क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औषध-निर्माण इकाइयों का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के परिणाम अनुसार अहमदाबाद औषध-निर्माण क्लस्टर फॉर्म्युलेशन क्लस्टर के रूप में सामने आया है। चरण-II में, विस्तृत ऊर्जा ऑडिटप्रोफाइलिंग के लिए 10 इकाइयां चयनित की गई थीं। चयनित इकाइयां विभिन्न उत्पाद फॉर्मूलेशन में संलग्न 5 मध्यम, 3 छोटी और 2 सूक्ष्म इकाइयों वाले परिवर्तशील औषध-निर्माण सेक्टर प्रोफाइलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इकाइयों की विद्युत और तापीय दोनों उपयोगिताओं में परिचालन लागत में कमी लाने के लिए ऊर्जा संरक्षण चिह्नित करने के लिए एनपीसी द्वारा तकनीकी अध्ययन आयोजित किए गए थे। गुजरात क्षेत्र की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औषध-निर्माण इकाइयों की सक्रिय भागीदारी के साथ 17 सितंबर 2021 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारतीय दवा निर्माता संघ - गुजरात राज्य मंडल के सहयोग से अहमदाबाद में प्रचार-प्रसार कार्यशाला आयोजित की गई। ऊर्जा ऑडिट अध्ययन में ऐसे 14 हस्तक्षेप चिह्नित किए गए हैं जिन्हें परिचालनों में ऊर्जा बचत के लाभ के लिए किसी भी औषध-निर्माण इकाई द्वारा आसानी से लागू किया जा सकता है।

❖ v पुनः संरचितत्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) परियोजना

विद्युत वित्त निगम, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, आरडी गांधीनगर को गुजरात राज्य के लिए बाहरी-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। एनपीसी आरडी गांधीनगर ने गुजरात राज्य में सभी चार विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अध्ययन पूरा किया। एनपीसी ने पूरे गुजरात राज्य को शामिल करते हुए परियोजना क्षेत्रों के 84 शहरों के लिए सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां निर्धारित की हैं। एनपीसी ने पांच वर्ष की अवधि के लिए सभी चार विद्युत वितरण कंपनियों के लिए अलग-अलग समग्र उपयोगिता संबंधी हानियों की गणना की है। इसके अलावा एनपीसी ने परियोजना क्षेत्रों अर्थात टीओआर2 में परियोजना के तहत कवर किए गए 64 शहर, की वार्षिक एटीएंडसी हानियां सत्यापित की हैं। आरएपीडीआरपी परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि परियोजना के तहत शामिल किए गए गुजरात के सभी 84 शहरों की एटीएंडसी हानियां कम की जाएं। इसके लिए हानि में निरंतर कमी के संदर्भ में वास्तविक, दर्शाने योग्य निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

❖ गुजरात राज्य में उद्योगों के जल ऑडिट

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन 100 घन मीटर से अधिक भूजल निकालने वाले सभी उद्योगों के जल ऑडिटके लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को प्रमाणित ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। एनपीसी, आरडीगांधीनगर ने गुजरात में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में 50 से अधिक जल ऑडिट किए हैं और जल संचयन, पानी के पुनः चक्रण और वर्षा जल उपयोग के माध्यम से प्राप्त करने योग्य जल बचत की बड़ी संभावना से सभी उद्योग लाभान्वित होते हैं। इन जल ऑडिट अध्ययनों से औद्योगिक परिसरों में सभी जल उपयोगों की इन्वेंट्री बनाने का तरीका मिलता है और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के तरीके चिह्नित होते हैं। इससे जल के नुकसानों में कमी आती है।

❖ केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची के लिए दर सूची (एसओआर) तैयार करना

केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची अपनी ओपन कास्ट परियोजनाओं में कोयला निकालने और परिवहन के काम को आउटसोर्स कर रहा है। इसके लिए अपेक्षित है कि आउटसोर्सिंग निजी एजेंसियों को ठेका देने के लिए आधार बनने वाली विभिन्न प्रचालनों की उचित लागत निर्धारित की जाए।

ओपन कास्ट परियोजना में काम कर रहा पेलोडर

एनपीसीओबी एवं कोयले के खनन और परिवहन संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए दर सूची दस्तावेज तैयार करती है। इस दस्तावेज़ से कोयला सहायक कंपनियों द्वारा बोलीदाताओं के लिए सबसे उचित लागतों पर निविदाएं जारी करना सुगम हो जाता है। विभिन्न गतिविधियों के लिए दर सूची तैयार करने से कोयला सहायक कंपनियों को कार्यों के निष्पादन की समग्र लागत कम करने में सहायता मिलती है। ऐसे काम में चूंकि भारी मात्रा में ओबी और कोयले का निष्कर्षण और परिवहन शामिल है, कोयला सहायक कंपनियां इन परिचालनों के लिए लागत में पर्याप्त कमी लाने में सक्षम होती हैं। इस अध्ययन से उत्पादकता अर्थात विभिन्न भारी वाहन मशीनरी बेड़े का आकार, उपकरण उपयोग, उत्पादन संसाधन दर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जनशक्ति, ऊर्जा उपयोग आदिको मापने और सुधारने में भी सहायता मिलती है।

सर्फेस माइनर से कोयले की कटाई

❖ अध्ययन आउटपुट की प्रयोज्यता

दर सूची के लिए ठेकेदार फर्मों की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के मानकीकरण की जरूरत पड़ती है। इससे प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया में अपव्यय कम करने में सहायता मिलती है। दर सूची बनाने से बोली दाताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है ताकि उनके संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और आगे उनके अतिरिक्त लाभ को बढ़ाया जा सके।

यह अध्ययन हालांकि कोयला खनन क्षेत्र के लिए किया गया है, फिर भी यह पद्धति विनिर्माण गतिविधियां, सेवा गतिविधियां आदिउन सभी मानकीकृत गतिविधियों के लिए उपयोगी होगी जहां आउटसोर्सिंग की जाती है।

❖ अध्ययन आउटपुट की प्रयोज्यता

दर सूची के लिए ठेकेदार फर्मों की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के मानकीकरण की जरूरत पड़ती है। इससे प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया में अपव्यय कम करने में सहायता मिलती है। दर सूची बनाने से बोली दाताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है ताकि उनके संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और आगे उनके अतिरिक्त लाभ को बढ़ाया जा सके।

यह अध्ययन हालांकि कोयला खनन क्षेत्र के लिए किया गया है, फिर भी यह पद्धति विनिर्माण गतिविधियां, सेवा गतिविधियां आदिउन सभी मानकीकृत गतिविधियों के लिए उपयोगी होगी जहां आउटसोर्सिंग की जाती है।

❖ निष्पादित गतिविधियां

- केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के लिए रेल वैगन में कोयले के लदान सहित कोयले के लदान और परिवहन के लिए सीसीएल दर सूची (एसओआर) में संशोधन
- कोयला/ओबी उत्खनन, लदान और परिवहन और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए मौजूदा दर सूची के तहत गैर-शामिल सभी मदों के लिए दर सूची तैयार करने सहित सीसीएल की मौजूदा दर सूची (एसओआर) में संशोधन।

❖ **त्रिपुरा के सभी जिलों में खतरनाक और अन्य अपशिष्टसृजित करने वाले उद्योगों/इकाइयों के संबंध में राज्य स्तरीय अध्ययन**

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता द्वारा त्रिपुरा राज्य के सभी जिलों में खतरनाक और अन्य अपशिष्ट पैदा करने वाले उद्योगों/इकाइयों को सूचीबद्ध करने संबंधी अध्ययन पर राज्य स्तरीय परियोजना आयोजित की गई। यह परियोजना त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा सौंपी गई थी। इन अध्ययनों में त्रिपुरा राज्य में फील्ड स्तरीय दौरे, खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नमूनों का विश्लेषण, खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट दूषण स्थलों की पहचान और कचरे के प्रकार के आधार पर खतरनाक अपशिष्ट सृजन कारक का विकास शामिल हैं। फील्ड दौरों के आधार पर, सूचीकरण गतिविधि के दौरान राज्य में चल रही खतरनाक कचरा पैदा करने वाली इकाइयों और खतरनाक कचरे के कुल सृजन का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा, गैर-पुनः नवीनीकरण योग्य, गैर-उपयोग योग्य खतरनाक कचरे को सुरक्षित लैंडफिल में लैंडफिलिंग या भस्मीकरण द्वारा निपटाने के लिए राज्य में खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया थाक्योंकि त्रिपुरा राज्य में गैर-पुन: उपयोग योग्य, अनुपयोगी खतरनाक कचरे के लिए उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) नहीं है। इससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान विकल्पों को अधिक मजबूती मिलेगी।

टीएसपीसीबी कार्यालय में एनपीसी द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति

❖ **टेक्समाको रेल एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, पश्चिम बंगाल में आईएस:14489 के अनुसार आयोजित बाहरी सुरक्षा ऑडिट**

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कोलकाता ने मेसर्स टेक्समाको रेल एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, पश्चिम बंगाल में आईएस 14489 के अनुसार बाहरी सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया।

इस ऑडिट का मूल उद्देश्य यह था कि संगठन की विभिन्न इकाइयों की समग्र सुरक्षा लब्धि में सुधार लाने के तरीके निर्धारित किए जाएं।

फैक्ट्री अधिनियम और नियम; भारतीय विद्युत नियम इत्यादि जैसे सभी प्रासंगिक आईएस कोड्स एवं नियमों के अनुसार पूर्वाभ्यास निरीक्षण किया गया जिसमें विद्युत, रसायन आदि सहित सुरक्षा के विविध पहलुओं पर बल दिया गया। एचटी/एलटी उप स्टेशन, पैनल रूम, डीबी आदि जैसी सभी उपलब्ध विद्युत सुविधाओं के आधार पर थर्मोग्राफी आयोजित की गई थी।

सिफारिशों को काफी सराहा गया और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी।

❖ उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए शोध अध्ययन आयोजित करना

डीसी एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए शोध अध्ययन" शीर्षक वाला यह अध्ययन एनपीसी को सौंपा गया था। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य यह थे कि उत्तर-पूर्व और सिक्किम के स्टार्टअप्स की आधारभूत स्थिति तैयार की जाए और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप इको सिस्टम की जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय सर्वोत्तम नीतियों/व्यवहारों/पहलों का प्रलेखन किया जाए।

अध्ययन में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप इको सिस्टम के विभिन्न पहलुओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र के सभी आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम और स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, सलाहकार, निवेशक एवं स्टार्टअप पहल के क्रियान्वयन में संलग्न राज्यों के विभाग जैसे अध्ययन के विभिन्न हित धारकों को शामिल करते हुए फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप इको सिस्टम के अनुसार सर्वोत्तम व्यवहारों, नीतियों और पहलों के प्रलेखन के लिए महाराष्ट्र और केरल के स्टार्टअप इको सिस्टम को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इज़रायल, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ताइवान के स्टार्टअप इको सिस्टम के प्रलेखन को भी शामिल किया गया है और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप इको सिस्टम की जरूरत के आधार पर उनकी पहलें चयनित की गई हैं।

अध्ययन निष्कर्ष उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप इको सिस्टम के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश इंगित करते हैं। सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों में ज्ञान केंद्र तैयार करना, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्टार्टअप पहल के कार्यान्वयन के लिए समर्पित क्लस्टर सिस्टम तैयार करना, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और इसे साझा करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संस्थानों को आपस में जोड़ना, स्टार्टअप इको सिस्टम के विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और इस क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं के प्रतिभा पलायन को रोकना और उन्हें बनाए रखना शामिल हैं।

❖ पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के दौरों/आगंतुकों के आंकड़ों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में नियुक्त किया है ताकि उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनके दौरों के अनुमान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभागों में क्षमता निर्मित की जा सके।

पर्यटक यात्राएं, होटल कारोबार, रोजगार, विदेशी मुद्रा आय, अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन, भारतीय नागरिक प्रस्थान जैसे जिलावार पर्यटन विकास संकेतकों की जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। इस डैशबोर्ड से राज्य के पर्यटन विभागों को उनके राज्यों के पर्यटन संकेतकों की निगरानी करने और उनकी नीतियों एवं पहलों के संबंध में सही दिशा में योजना बनाने के लिए तंत्र प्राप्त होगा।

❖ सीपीएसई में "सार्वजनिक खरीद/जीईएम एवं अनुबंध प्रबंधन/मध्यस्थता से संबंधित समस्याएं" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

०6 दिसंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक "सीपीएसई में सार्वजनिक खरीद/जीईएम और अनुबंध प्रबंधन/मध्यस्थता से संबंधित समस्याएं" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इसे लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के अधिकारियों ने भाग लिया और उनके द्वारा इसकी काफी सराहना की गई।

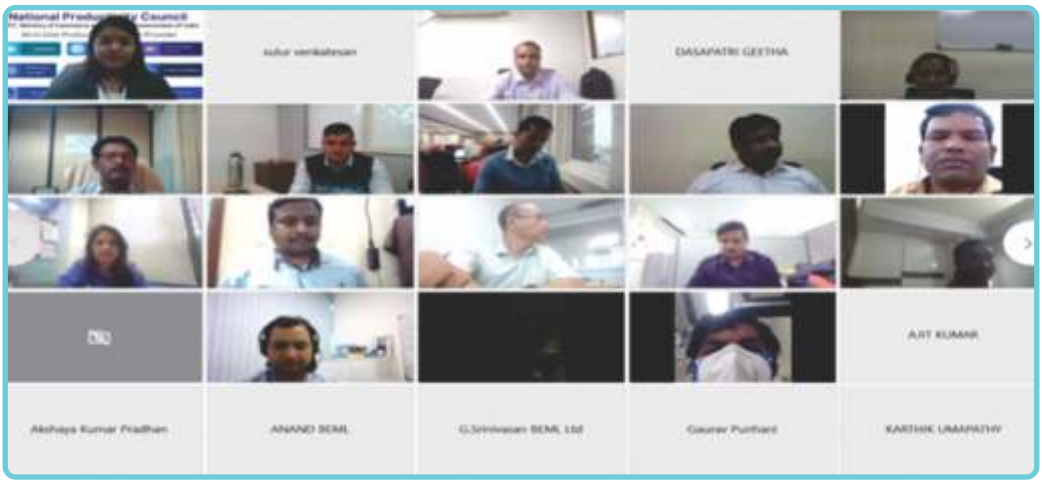

❖ सतत सुधार प्रबंधन और सिक्ससिग्मा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनपीसी समूह ने मानेसर संयंत्र की हमदर्द प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के लिए प्रयोगशाला में ही सतत सुधार प्रबंधन और सिक्स सिग्मा पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- एनपीसी के निरीक्षण प्रभाग ने 11.06.2021 को एफएसएसएआई (लेबलिंग और डिस्प्ले विनियम), 2020 शीर्षक से वेबिनार आयोजित किया। इसके लिए 698 प्रतिभागियों ने भुगतान करके वेबिनार के लिए पंजीकरण कराया। मदरडेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड, बनास डेयरी (अमूल), दूध मानसागर डेयरी (अमूल), जीएचसीएल (पूर्ववर्ती गुजरात हेवी केमिकल्स), सन फार्मा स्युटिकल्स वडोदरा, हमदर्द, कानकोर इनग्रीडिएंट्स लिमिटेड, बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, कन्ननदेवन चाय बागान, मुन्नार, सोनीपत शूगर्स, हल्दीराम आदि प्रमुख भागीदारों में शामिल हैं।

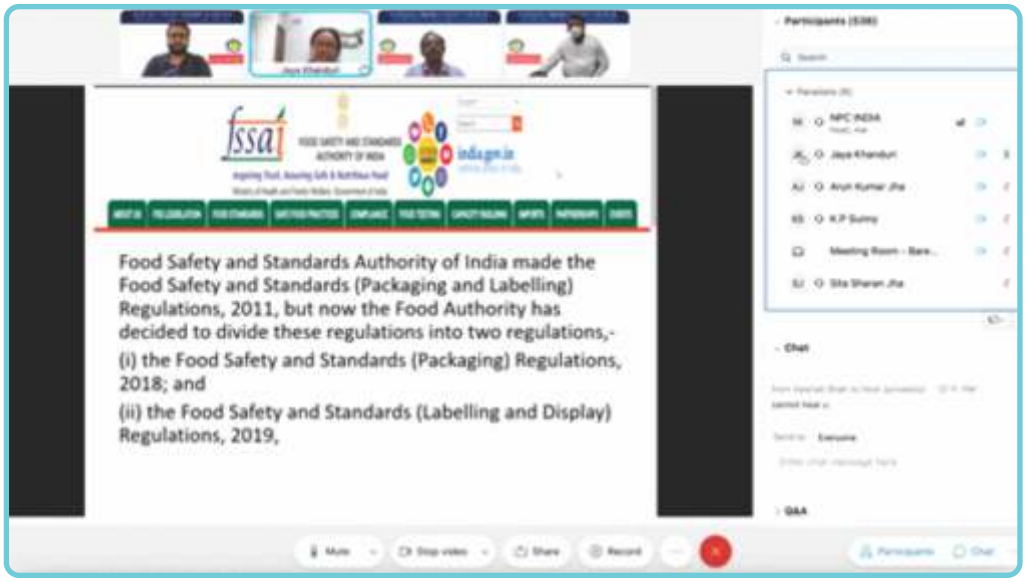

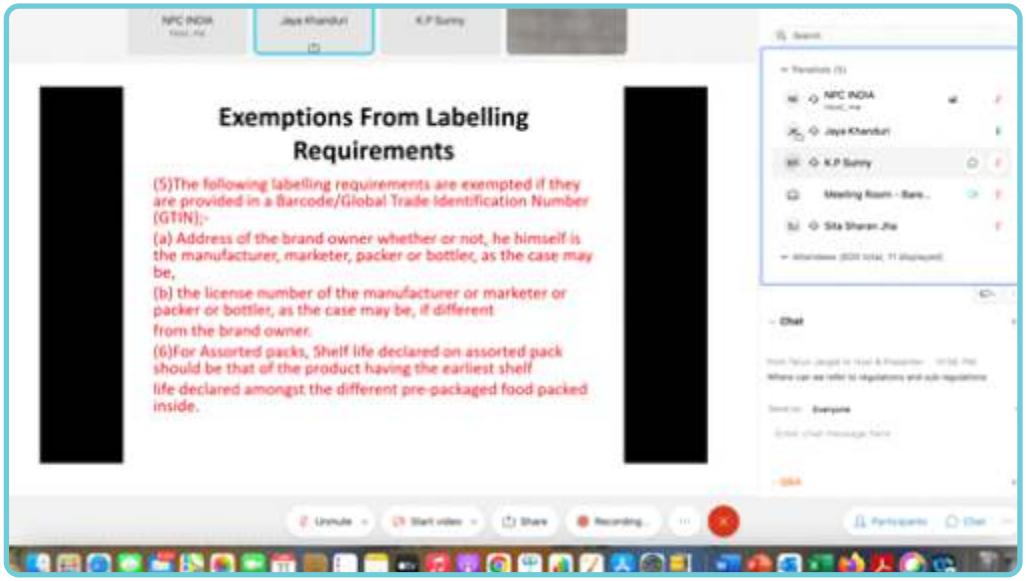

❖ एनपीसी ने देश भर में डब्ल्यूडीआरए के 147 एफसीआईडिपुओं का निरीक्षण किया

❖ डब्ल्यूडीआरए नियम, 2017 के अनुसार गोदामों के निरीक्षण के लिए एनपीसी को भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) में निरीक्षण एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एनपीसी के निरीक्षण प्रभाग ने अगस्त-नवंबर २०२१ के दौरान डब्ल्यूडीआरए के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले 147 एफसीआईडिपुओं का निरीक्षण कार्य निष्पादित किया है।

आरडी गुवाहाटी टीम ने सीजीडब्ल्यूए दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार विभिन्न ग्राहकों के लिए जल ऑडिट अध्ययन किए। इन अध्ययनों में सीजीडब्ल्यूए मानदंडों के अनुसार इकाइयों और अनुपालन स्थिति के लिए जल संरक्षण अवसरों पर प्रकाश डाला गया। जल ऑडिट संबंधी फील्ड अध्ययन की कुछ तस्वीरें नीचे दी गईं हैं:

फील्ड फोटोग्राफ – जल ऑडिट अध्ययन

फील्ड फोटोग्राफ – जल ऑडिट

फील्ड फोटोग्राफ – जल ऑडिट अध्ययन

फील्ड फोटोग्राफ – जल ऑडिट अध्ययन

फील्ड फोटोग्राफ – जल ऑडिट अध्ययन

समूह फोटो- साइबर सुरक्षा पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

❖ **"एनपीसी को डीसी, एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय द्वारा "उत्तर-पूर्व के स्टार्टअप के लिए अनुसंधान अध्ययन" सौंपा गया था। उत्तर-पूर्व के स्टार्टअप की आधारभूत स्थिति तैयार करना अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था।**

अध्ययन में उत्तर-पूर्व के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। क्षेत्र के सभी आठ राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया है और स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, मार्गदर्शक, निवेशक और स्टार्टअप पहल के क्रियान्वयन में संलग्न राज्यों के विभाग जैसे अध्ययन के विभिन्न हित धारकों इसमें शामिल किया गया है। उत्तर-पूर्व के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुकूल सर्वोत्तम व्यवहारों, नीतियों और पहलों के प्रलेखन के लिए महाराष्ट्र और केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इज़रायल, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ताइवान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रलेखन को शामिल किया गया है और उत्तर-पूर्व के स्टार्टअप इकोसिस्टम की जरूरत के आधार पर उनकी पहलें चयनित की गईं हैं।

अध्ययन निष्कर्ष उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश इंगित करते हैं। सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों में ज्ञान केंद्र तैयार करना, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्टार्टअप पहल के कार्यान्वयन के लिए समर्पित क्लस्टर सिस्टम तैयार करना, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और इसे साझा करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संस्थानों को आपस में जोड़ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना और इस क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं के प्रतिभा पलायन को रोकना और उन्हें बनाए रखना शामिल हैं।

❖ **पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के दौरों/आगंतुकों के आंकड़ों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण**

पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में नियुक्त किया है ताकि उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या और उनके दौरों के अनुमान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभागों में क्षमता निर्मित की जा सके।

पर्यटक यात्राएं, होटल कारोबार, रोजगार, विदेशी मुद्रा आय, अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन, भारतीय नागरिक प्रस्थान जैसे जिलावार पर्यटन विकास संकेतकों की जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। इस डैशबोर्ड से राज्य के पर्यटन विभागों को उनके राज्यों के पर्यटन संकेतकों की निगरानी करने और उनकी नीतियों एवं पहलों के संबंध में सही दिशा में योजना बनाने के लिए तंत्र प्राप्त होगा।

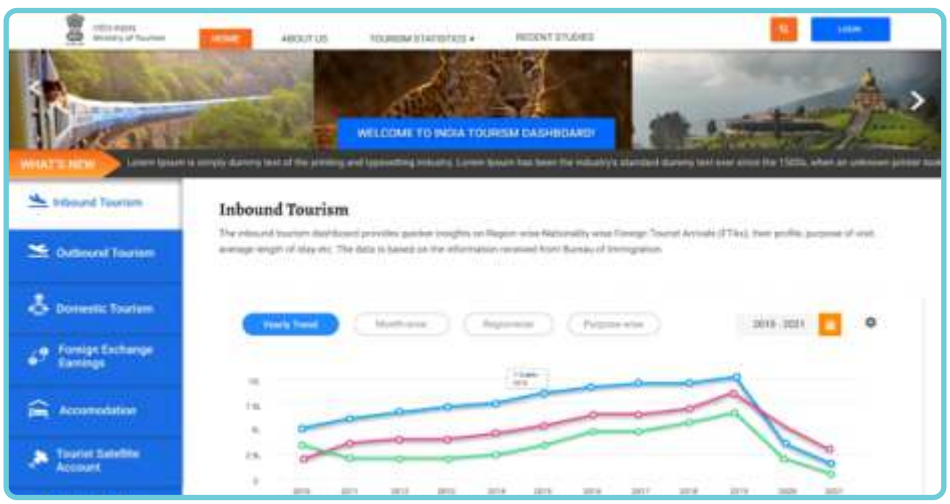

❖ ऊर्जा ऑडिट

आरडी भुवनेश्वर ने वाणिज्यिक भवनों, अस्पतालों, तापीय विद्युत स्टेशनों और पंपिंग स्टेशनों जैसे क्षेत्रों में 11 ऊर्जा ऑडिट किए। उपयोगिताओं का उपयोग करके ऊर्जा के प्रदर्शन मूल्यांकन और ऊर्जा संरक्षण के अवसरों को सामने लाना इन अध्ययनों का उद्देश्य था।

❖ डायमंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता में विस्तृत ऊर्जा और जल ऑडिट

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कोलकाता ने मैसर्स डायमंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता में विस्तृत ऊर्जा और जल ऑडिट आयोजित किया।

अपनी विनिर्माण सुविधा और बॉटलिंग संयंत्र की ऊर्जा और जल की संपूर्ण खपत के ऑडिट के इरादे से मैसर्स डायमंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता ने एनपीसी कोलकाता से संपर्क किया और अध्ययन के दायरे में उद्योग में प्रवेश से उद्योग से निकास तक के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विशिष्ट ऊर्जा एवं जल दोनों के खपत मूल्यांकन शामिल थे।

मौजूदा एचवीएसी प्रणाली, मोटरों, इन्सुलेशन सिस्टम आदि पर विशेष बल देते हुए ऊर्जा ऑडिट में ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, प्रचलित हार्मोनिक्स आदि सहित संपूर्ण विद्युत वितरण प्रणाली का विश्लेषण किया गया था। सिफारिशें और ऊर्जा/पानी के बचत उपाय व्यवहार्य एवं उपयोगी दोनों हैं । इनकी काफी सराहना की गई और प्रबंधन से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

डायमंड बेवरेजेज, कोलकाता में एनपीसी द्वारा रिपोर्ट निष्कर्षों की प्रस्तुति एवं फील्ड ऑडिट की झलकें

❖ **इंडियन पोटाश लिमिटेड की आईसीआरओ परियोजना के तहत मैसर्स श्री केवीएस इंडस्ट्रीज में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन संचालित किया गया और आईपीएलसीएसआर गतिविधि के हिस्से के रूप में ऊर्जा संरक्षण उपाय सुझाए गए**

❖ **राजश्री सीमेंटवर्क्स, कर्नाटक में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट**

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "राजश्री सीमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, मलखेड, गुलबर्ग, कर्नाटक" में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट आयोजित किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है। ऑडिट टीम ने सीमेंट संयंत्र और साथ ही एकीकृत तापीय विद्युत संयंत्र में अध्ययन किया है। सीमेंट संयंत्र अध्ययन में प्रीहीटर, भट्ठी, कूलर, रॉ मिल, कोल मिल, सीमेंट मिलों और उपयोगिताओं जैसी विभिन्न प्रक्रिया प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन में 47.47 किलो कैलोरी/किलोग्राम क्लिंकर की तापीय बचतों के संदर्भ में बचतें चिह्नित की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप 20,076 टन कोयले जबकि विद्युत के मामले में 18.64 मिलियन यूनिट की बचत होगी। कुल मिलाकर इस ऊर्जा ऑडिट में 22.99 करोड़ रुपए की बचतें चिह्नित की गई हैं।

❖ कोटपूतली सीमेंट वर्क्स, राजस्थान में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "कोटपुतली सीमेंट वर्क्स, अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान" में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है। ऑडिट टीम ने सीमेंट संयंत्र और साथ ही एकीकृत तापीय विद्युत संयंत्र में अध्ययन किया है। सीमेंट संयंत्र अध्ययन में प्रीहीटर, भट्ठी, कूलर, रॉ मिल, कोल मिल, सीमेंट मिलों और उपयोगिताओं जैसी विभिन्न प्रक्रिया प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने 6.88 किलो कैलोरी/किलोग्राम क्लिंकर की तापीय बचतों के संदर्भ में बचतें चिह्नित की है। इसके परिणामस्वरूप 5,266 टन कोयले जबकि विद्युत के मामले में 11.67 मिलियन इकाइयों की बचत होगी। कुल मिलाकर इस ऊर्जा ऑडिट में 8.28 करोड़ रुपए की बचतें चिह्नित की गई हैं।

❖ केसीपी सीमेंट्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों / प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "केसीपी सीमेंट्स लिमिटेड, मुक्तयाला इकाई, आंध्र प्रदेश" में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है। ऑडिट टीम ने सीमेंट संयंत्र और साथ ही एकीकृत तापीय विद्युत संयंत्र में अध्ययन किया है। सीमेंट संयंत्र अध्ययन में प्रीहीटर, भट्ठी, कूलर, रॉ मिल, कोल मिल, सीमेंट मिलों और उपयोगिताओं जैसी विभिन्न प्रक्रिया प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने 54.3 किलो कैलोरी/किलोग्राम क्लिंकर की तापीय बचतों के संदर्भ में बचतें चिह्नित की है। इसके परिणामस्वरूप 11,124 टन कोयले जबकि विद्युत के मामले में 7.38 मिलियन इकाइयों की बचत होगी। कुल मिलाकर इस ऊर्जा ऑडिट में 12.76 करोड़ रुपए की बचतें चिह्नित की गई हैं।

❖ ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद में ऊर्जा ऑडिट

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों / प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, गागिलापुर, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने 54.3 किलो कैलोरी / किलोग्राम क्लिंकर की तापीय बचतों के संदर्भ में बचतें चिह्नित की है। इसके परिणामस्वरूप 141 टन कोयले जबकि विद्युत के मामले में 0.86 मिलियन इकाइयों की बचत होगी। कुल मिलाकर इस ऊर्जा ऑडिट में 0.70 करोड़ रुपए की बचतें चिह्नित की गई हैं।

❖ अरबिंदो फार्मा लिमिटेड इकाई-4 (यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज लिमिटेड इकाई-3) में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "अरबिंदो फार्मा लिमिटेड इकाई-4 (यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज लिमिटेड इकाई-3, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने विद्युत बचतों के संदर्भ में 27.44 लाख किलोवाटहॉर्स की बचतें और 471 टन की तापीय बचतें (कोयला एवं फर्नेस तेल) चिह्नित की हैं। इससे 98.73 लाख रूपए के निवेश से 2.25 करोड़ रुपए धन की बचत (विद्युत एवं तापीय) की जा सकती है जिससे कार्बनडाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2986 टन तक कम होगा।

❖ अरबिंदो फार्मा लिमिटेड इकाई-3 में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "अरबिंदो फार्मा लिमिटेड इकाई-3, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने विद्युत बचतों के संदर्भ में 10.62 लाख किलोवाटहॉर्स की बचतें और 138 टन की तापीय बचतें (कोयला एवं फर्नेस तेल) की बचतें चिह्नित की हैं। इससे 167.7 लाख रूपए के निवेश से 1.25 करोड़ रुपए धन की बचत (विद्युत एवं तापीय) की जा सकती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 1182 टन तक कम होगा।

❖ अरबिंदो फार्मा हेल्थकेयर लिमिटेड इकाई-1 में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "अरबिंदो फार्मा लिमिटेड इकाई-3, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने विद्युत बचतों के संदर्भ में 6.62 लाख किलोवाटहॉर्स की बचतें और 33 टन की तापीय बचतें (कोयला एवं फर्नेस तेल) चिह्नित की हैं। इससे 56 लाख रूपए के निवेश से 58 लाख रुपए धन की बचत (विद्युत एवं तापीय) की जा सकती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 710 टन तक कम होगा।

❖ दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इकाई-1 में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इकाई-1, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने विद्युत बचतों के संदर्भ में 2.59 लाख किलोवाटहॉर्स की बचतें और 182.57 टन की तापीय बचतें (कोयला एवं फर्नेस तेल) चिह्नित की हैं। इससे 31.59 लाख रूपए के निवेश से 30.56 लाख रुपए धन की बचत (विद्युत एवं तापीय) की जा सकती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 509 टन तक कम होगा।

❖ दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इकाई-2 में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इकाई-2, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने विद्युत बचतों के संदर्भ में 7.45 लाख किलोवाटहॉर्स की बचतें और 888.56 टन की तापीय बचतें (कोयला एवं फर्नेस तेल) चिह्नित की हैं। इससे 221 लाख रूपए के निवेश से 395 लाख रुपए धन की बचत (विद्युत एवं तापीय) की जा सकती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3045 टन तक कम होगा।

❖ दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इकाई-3 में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, हैदराबाद ने विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों/प्रणालियों का निष्पादन निर्धारित करने और ऊर्जा संरक्षण अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से "दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इकाई-2, हैदराबाद" में ऊर्जा ऑडिट किया है। विद्युत संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट की अपेक्षा पूरी करने के लिए संयंत्र द्वारा यह ऑडिट किया गया है।

ऊर्जा ऑडिट अध्ययन ने विद्युत बचतों के संदर्भ में 1.90 लाख किलोवाटहॉर्स की बचतें और 81.74 टन की तापीय बचतें (कोयला एवं फर्नेस तेल) चिह्नित की हैं। इससे 14.10 लाख रूपए के निवेश से 17.94 लाख रुपए धन की बचत (विद्युत एवं तापीय) की जा सकती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 296 टन तक कम होगा।

❖ उद्योगों में जल ऑडिट

बोरेवेल जल प्रवाह मीटर का नरीक्षण करती एनपीसी टीम

क्षेत्रीय निदेशालय भुवनेश्वर ने धातु, खनन, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न उद्योगों में लगभग 35 जल ऑडिट अध्ययन आयोजित किए। संयंत्र/खदान के भीतर विभिन्न उपयोगिताओं द्वारा भूजल खपत का लेखा-जोखा करना और जल संरक्षण संभावना को प्रकट करना इस ऑडिट का उद्देश्य था। सभी जल ऑडिट अध्ययन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। यह हमारी संसाधन संरक्षण सेवाओं का एक हिस्सा है।

❖ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर में विस्तृत जल ऑडिट

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कोलकाता ने मैसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भाटिनमाइन्स-जमशेदपुर में विस्तृत जल ऑडिट संचालित किया।

मैसर्स यूसीआईएल प्रबंधन ने अपनी भाटिनखदान इकाई की संपूर्ण जल खपत के ऑडिट के इरादे से एनपीसी कोलकाता से संपर्क किया और अध्ययन का दायरा उद्योग में प्रवेश से लेकर उद्योग से निकास तक के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विशिष्ट जल खपत मूल्यांकन तक विस्तारित था।

विस्तृत जल ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि कुल जल खपत कम करने के तरीके निर्धारित किए जाएं। देश भर में स्थित यूसीआईएल (नरवापहाड़ खानों के बाद) की सात खदानों में से यह दूसरी खदान थी जिसमें ऐसी कवायद की गई थी।

सिफारिशें और जल बचत उपाय प्राप्य और व्यावहारिक थे और इनकी काफी सराहना की गई और यूसीआईएल प्रबंधन की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी।

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर द्वारा एनपीसी में फील्डऑडिट की झलकें

वित्त वर्ष 2021–22 में निष्पादित परामर्श परियोजनाओं की सूची

क्र0	परामर्श परियोजना का नाम
1	Energy Audit for SBI Administrative Building, BBSR
2	Surveillence Audit of SA 8000 in respect of Six Operative Mines for OMC,BBSR
3	Turbine Performance Study for NTPC-SAIL Power Company Ltd, Rourkela
4	Environment Awareness Training Programme for JSW Cement, Jajpur
5	IGEA Audit Sewerage Treatment Plant at Puri for SDA,Odisha
6	SA 8000 Certification in respect of 3 Mines
7	IGEA Audit At DHH,Phulbani For SDA, Odisha
8	Training Programe on Retirement Plan For NPCIL,Mumbai
9	Organizing Road Show For Promotion of Electric Vehicles For SDA, Odisha
10	Time & Motion Study At Khondalite Mines of OMC, BBSR
11	5-S Certification Audit for Adani Hazira Port Ltd., Surat
12	5-S Certification Audit for Marine Infrastructure Developer Pvt. Ltd., Chennai
13	Third Party Independent Evaluation Agency-RAPDRP for Gujarat region for Power Finance Corporation, New Delhi
14	5-S Certification Audit for Adani Ennore Container Terminal Pvt. Ltd., Chennai
15	5-S Certification Audit for Adanu Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd
16	5-S Certification Audit for PG India Logistics Pvt Ltd., Sanad
17	Manpower Optimization & Restructuring Study for Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd
18	5-S Certification Audit for BASF India Ltd., Bharuch
19	Random verification of annual inventory of hazardous waste management for Central Pollution Control Board, Delhi
20	Training of 64-Safaimitras for Municipal Corporation, Singrauli
21	Preliminary Visit for Time & Motion Study for Adani Wilmar Limited, Ahmedabad
22	5-S Certification Audit for Adama India Pvt Ltd
23	Performance evaluation of pollution control systems including ESP, Bag filters installed in 20 MW CPP for Bal Krishna Industries Ltd, Bhuj
24	Manpower Optimization Study for Adani Wilmar Limited, Ahmadabad
25	5-S Certification Audit for Adani Hazira Port Ltd., Surat
26	5-S Certification Audit for Marine Infrastructure Developer Pvt. Ltd., Chennai
27	5-S Certification Audit for Adani Ennore Container Terminal Pvt. Ltd., Chennai
28	5-S Certification Audit for Adanu Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd
29	5-S Certification Audit for PG India Logistics Pvt Ltd., Sanad

वित्त वर्ष 2021–22 में निष्पादित परामर्श परियोजनाओं की सूची

क्र0	परामर्श परियोजना का नाम
30	Manpower Optimization & Restructuring Study for Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd
31	5-S Certification Audit for BASF India Ltd., Bharuch
32	Random verification of annual inventory of hazardous waste management for Central Pollution Control Board, Delhi
33	Training of 64-Safaimitras for Municipal Corporation, Singrauli
34	Preliminary Visit for Time & Motion Study for Adani Wilmar Limited, Ahmedabad
35	5-S Certification Audit for Adama India Pvt Ltd
36	Performance evaluation of pollution control systems including ESP, Bag filters installed in 20 MW CPP for Bal Krishna Industries Ltd, Bhuj
37	Manpower Optimization Study for Adani Wilmar Limited, Ahmadabad
38	Research study for the Start ups and develop the baseline status of the Start-ups of North Eastern Region
39	The study and analysis of Hazardous and other waste samples, Identification of Hazardous and other wastes contaminating sites and development of Hazardous waste generation factor based on the type of waste
40	A Detailed Energy & Water Audit at M/s Diamond Beverages Pvt. Ltd., Kolkata.
41	Third-Party Evaluation Study of two Schemes "Central Sector Schemes Package II (2013) for J & K (Capital Investment Subsidy, Central Interest Subsidy and Comprehensive Insurance Subsidy) and for Himachal Pradesh & Uttarakhand (Capital Investment Subsidy)" and "Industrial Development Scheme for UT of J&K and UT of Ladakh-2017 (IDS-2017 for J&K and Ladakh) for the States of Himachal Pradesh & Uttrakhand-2017(IDS-2017 for H.P. & Uttarakhand).
42	Study on Operation & Maintenance Processes
43	Study for cogeneration certification of captive power plant at MCF Limited
44	'Manpower Assessment Study' at M.S. Ramaiah Hospitals`
45	Manpower Assessment Study', at Britannia Industries Limited plant
46	Consultancy services of setting up CBWTFs in Delhi, DPCC

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

क्र0	कार्यक्रम का नाम
1	Training programs for the Department of Public Enterprises, Government of Karnataka
2	Advance training on electrical safety: hazards, safety audit, standards ,electrical safety act, 2003
3	Awareness programme on basics of lightning protection for Hindustan Petroleum Corporation Ltd. as part of National Electrical Safety Week celebration
4	Training Program on 'Energy Efficiency Practitioners Course in Industrial Utilities
5	Training Program on Industrial Environment Management through Techno-Managerial and Policy Issues
6	Energy Efficiency Practitioner's Course in Industrial Utilities
7	Technical Policy Instruments & Frameworks for shifting to Renewable Energy for ITEC
8	Effective Office Administration and Financial Management in Leh, Ladakh
9	Project Management Planning and Monitoring& Evaluation in Gangtok, Sikkim
10	Performance & Financial Management for Organizational Excellence
11	Training programme on Effective Office Administration and Financial Management
12	Online training on Environment management and Energy efficiency for officials of M/s Brookfield properties
13	Training Program on Air Pollution & Air Modelling
14	Training Programon 'How to improve your cities/town's ranking under Swachh Survekshan Ranking'
15	ETP & CETP Operation and Maintenance
16	Adequacy & Efficacy PETP ETP and CETP
17	Oil and Waste Management – HPCL
18	Residential Training Program for CPSEs & SPSEs
19	Residential Training Program for Divyang participants
20	Procurement, GeM, Arbitration and Contract Management sponsored by DPE, Govt of India
21	Self run training program on Administrative Effectiveness, Focus: RTI & Preventive Vigilance at Goa
22	Training Programme on Supply Chain Management
23	Training Programme on Effective Office Secretary
24	Training Programme on Creative Problem Solving
25	Training Programme on Developing Managerial & Supervisory Skills
26	Training Programme on Office Procedure: Noting & Drafting
27	Training Programme on Public Financial Management System
28	Training Programme on Establishment Rule
29	Training Programme on Tendering Process & Contract Management
30	Training Programme on Public Procurement: e-Procurement & GEM
31	Training Programme on Preventive Vigilance
32	Training Programme on Right to Information Act
33	Training Programme on Vigilance & Disciplinary Proceedings
34	Training Programme on General Financial Rule
35	Training program on Lean Management & Six Sigma

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण

क्र0	कार्यक्रम का सूची	कार्यक्रम का प्रकार
1	Implementation of 50001 :2018 energy management system for improving energy performance	Webinar
2	Industrial safety and industrial safety acts, rules and regulations	Webinar
3	Effective implementation of the energy conservation act, 2001	Webinar
4	Process safety, process safety management and ensuring process safety through ISO HAZOP	Webinar
5	Integrated implementation of ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 and ISO 45001 :2018 standards	Webinar
6	Education 4.0 – digital transformation of education aligning with industry 4.0	Webinar
7	Safety audit, safety audit techniques, planning and conducting a safety audit	Webinar
8	Marketing 4.0 – digital transformation of marketing function aligned with industry 4.0	Webinar
9	Smart manufacturing – digital transformation of manufacturing	Webinar
10	ISO 22000:2018 food safety management system- documentation, implementation and certification	Webinar
11	Manuals preparation to document ISO 45001 :2018 occupational health and safety management system	Webinar
12	Lockout/ tagout (loto) for control of hazardous energy	Webinar
13	ISO 37001:2016 anti-bribery management system - documentation, implementation and certification	Webinar
14	Methods/practices for achieving higher energy efficiency in industry	Webinar
15	Industrial safety , industrial safety acts, rules ,regulations, implementation issues and challenges	Webinar
16	Electrical safety, electrical safety audit, electrical hazards , electrical safety act, 2003 and rules	Webinar
17	How to document Energy Management System for effective implementation of ISO 50001:2018 Standard?	Webinar
18	Fire safety, fire risk assessment, fire safety audit and control of fire hazards	Webinar
19	Smart factory– digital transformation of processes at shop floor	Webinar
20	Documentation requirements of ISO 14001 :2015 standard and preparation of manuals for an environment management system	Webinar
21	Lightning & earthing precautions during heavy wind /stormy weather :lightning /thunderstorm safety	Webinar
22	Advance course on RTI act, 2005 with judgments of CIC/SIC & various high courts & supreme court of India	Webinar
23	First aid, first aid kits and occupational diseases and remedial and preventive measures	Webinar
24	Non-destructive testing (ndt) methods, technologies and their applications in industry	Webinar
25	Energy efficient technologies and their implementation	Webinar
26	Manuals preparation to document quality management system as per ISO -9001:2015 standard	Webinar
27	Manuals preparation to document iso 27001:2013 information security management system	Webinar

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण

क्र0	कार्यक्रम का सूची	कार्यक्रम का प्रकार
28	Hazardous chemicals rules, 1989 and latest amendments, material safety data sheet (msds) and its usage	Webinar
29	Six waste management rules,2016	Webinar
30	Manufacturing 4.0 & maintenance 4.0 –use of digital technologies for operational excellence	Webinar
31	Detailed energy audit: objectives, methodology, instruments used, report preparation & presentation	Webinar
32	Personal protective equipment(PPE) : usage, types, kits, proper maintenance, storage & disposal of PPE's	Webinar
33	Manuals preparation to document food safety management system as per ISO 22000:2018 standard	Webinar
34	Maximizing benefits by implementing ISO 45001: 2018 occupational health & safety management system	Webinar
35	Fire safety,control of fire hazards,fire evacuation plan,fire safety audit,control of fire incidents	Webinar
36	Maximizing benefits from implementation of Iso 50001: 2018 energy management system	Webinar
37	Plant safety management practices for minimizing hazards, risks, accidents and near misses	Webinar
38	Occupational safety,health& working conditions code,2020, electricity act& hazardous chemical rules	Webinar
39	Vibration analysis for effective preventive and predictive maintenance	Webinar
40	Behavior based safety(BBS): principles ,method, practices & tools to develop good safety behaviour	Webinar
41	Operational excellence through digital technologies under manufacturing 4.0 & quality 4.0	Webinar
42	Advance training on electrical safety: hazards , safety audit, standards ,electrical safety act, 2003	Webinar
43	Energy audit: preliminary & detailed energy audit, methodology, instruments used, conducting an energy audit	Webinar
44	Chemical Safety, Control of Chemical Hazards, MSDS, hazardous chemical rules, 1989, PPE's requirements	Webinar
45	Manual preparation for integrated management system as per ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 & ISO 45001 :2018	Webinar
46	Energy conservation in electrical utilities & electrical system for reducing power & energy demands	Webinar
47	Lightning & thunderstorm safety: safety measures, protecting lives, installations, buildings or structures	Webinar
48	Improving plant safety for minimizing hazards, risks, accidents and near misses	Webinar
49	Smart factory–key components, principles & technology used in its creation for smart manufacturing	Webinar
50	Advance training on electrical safety: hazards , safety audit, standards ,electrical safety act, 2003	Webinar
51	Design, development, application and maintenance of tools, dies, jigs and fixtures	Webinar
52	Fire safety management , control of fire hazards and accidents and fire emergency plan	Webinar
53	Improving energy performance by implementing an effective ISO 50001: 2018 energy management system	Webinar

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण

क्र0	कार्यक्रम का सूची	कार्यक्रम का प्रकार
54	Electrical safety, control of electrical hazards and electrical emergency plans and procedures	Webinar
55	Improving health & safety perpormance by controlling hazards by implementing ISO 45001: 2018 system	Webinar
56	Planning and conducting safety audit, effective safety audit management for maximizing benefits	Webinar
57	Six waste management rules,2016	Webinar
58	Design, development, application and maintenance of tools, dies, jigs and fixtures	Webinar
59	Improving quality and customer satisfaction by implementing ISO -9001:2015 quality management system	Webinar
60	Improving environmental performance by implementing ISO 14001 :2015 environment management system	Webinar
61	Safety acts -occupational safety, health & working conditions code,2020, electricity act,2003 & hazardous chemicals rules,1989	Webinar
62	Effective plant safety management for controlling hazards & preventing accidents	Webinar
63	Improving quality & customer satisfaction through ISO 9001 2015 & IATF 16949 2016 QMS implementation	Webinar
64	Improving workplace safety through behavior based safety(BBS) methods and practices	Webinar
65	Improving information security & reliability through ISO 27001:2013 isms	Webinar
66	Electrical safety, measures against electrical accidents& implementing electrical emergency plans	Webinar
67	2 day online practice training course on boiler efficiency calculation	Webinar
68	Boiler Engineering Drawing	Webinar
69	Cleaner Production- Need of Hour	Webinar
70	Constructional features and functioning of DC Batteries, Procedure of first charging and their Resi	Webinar
71	Data Analysis and QC tools With Excel	Webinar
72	E- Waste (Management) Rules, 2016	Webinar
73	Energy Saving In HVAC and Compressors through MAXR100-200 Technology	Webinar
74	Go Beyond HAZOP- Do LOPA and SIL Studies to safeguard your plant from disasters	Webinar
75	How to write a Book	Webinar
76	Improving Productivity in Services	Webinar
77	Introduction to advanced supply chain concepts - Day1	Webinar
78	Material Flow CostAccounting: ISO 14051	Webinar
79	Measuring the Performance of People- A case study	Webinar
80	Plastic Waste Management Rules, 2016	Webinar
81	Resume Writing & 8 Steps of Job Application	Webinar
82	Super Critical Technology	Webinar
83	Online Training & Certification Program on 'Six Sigma Green Belt' covering advanced concepts of Six Sigma Technology	Online Training
84	Online Training & Certification program on 'transformation to data driven decision making	Online Training
85	Online Training & Certification program on 'six sigma green belt' covering advanced concepts of six sigma methodology	Online Training
86	Unlocking The Secretes & Science Of Happiness For PGCIL, BBSR	Online Training

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण

क्र0	कार्यक्रम का सूची	कार्यक्रम का प्रकार
87	In company e-training program on Public Procurement & RTI for NABARD	Online Training
88	In company e-training program on Preventive Vigilance & Right to Information Act for DVC	Online Training
89	In company e-training program on Preventive Vigilance for Goa Shipyard Ltd., Goa	Online Training
90	In company e-training program on Enhancing Interpersonal communication skills for MSTC Ltd.	Online Training
91	E-training program on Pre promotion training for SIDBI	Online Training
92	Two Days Online Training Programme on Carbon Footprint Reduction and Clean Development Mechanism (CDM)	Online Training
93	Online Training Program on "Issues related to public procurement/GeM& contract management/ Arbitration in CPSE's	Online Training
94	1 Day Online Training Programme on Implementation of 5S for Bharat Oman Refineries Limited	Online Training
95	How PSUs Can help in Atmanirbhar Bharat of Govt of India (IOCL)	Online Training
96	Green building design constraints	Online Training
97	Procurement Management through GeM	Online Training
98	How to start Oxygen Manufacturing Plant	Online Training
99	Introduction to Sustainable Development in Business	Online Training
100	Online Training on Right to Information ACT	Online Training
101	How to setup Solar PV System for residential & commercial establishments	Online Training
102	Two day online Training on Excellence in Leadership	Online Training
103	Setting up an Oxygen Manufacturing Plant in India	Online Training
104	SA 8000 - Social Certification	Online Training
105	Value Stream Mapping for Industries	Online Training
106	Internal Auditing of Integrated Management System- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Online Training
107	Reservation in Services and preparation of Roster	Online Training
108	Operational Excellence through Lean Management and Six Sigma	Online Training
109	Salient Features of RTI Act and Records Management in government organisations	Online Training
110	Financial Basics for Entrepreneurs and Startups	Online Training

वित्त वर्ष 2021–22 में निष्पादित जल ऑडिट के ग्राहकों की सूची

क्र0	ग्राहक
1	Visaka Industries Ltd, Sambalpur
2	Apar Industries Ltd, Jharsuguda
3	Shyam Metalics & Energy Ltd, Sambalpur
4	Prakash Industries,Cg
5	Ultratech Cement Ltd, Baikunth,Cg
6	Brandsteel, Keonjhar
7	Imfa,Rayagada
8	N.H Goel World School,Cg
9	Shiva Cement, Rourkela
10	Magnum Sea Foods Ltd, Bbsr
11	Triveni Mines, Keonjhar
12	Godawari Natural Resources Pvt Ltd, Cg
13	J.K.Lakshmi Cement Ltd, Cuttack
14	Ultratech Cement Works, Cuttack
15	Sreerangam Exports Pvt Ltd, Bbsr
16	Nuvoco Vistas Corporation(Sonadih Cement Plant),Cg
17	Misrilal Mines, Jajpur & Dhenkanal
18	R.R.Energy Ltd, Cg
19	Nuvoco Vistas Corporation(Arasmeta Cement Plant),Cg
20	Hari Marine Pvt, Ltd, Balasore
21	Sevenstar Steels Ltd, Jharsuguda
22	Grasim Industries,Ganjam
23	Rexon Strips Ltd, Rourkela
24	Rungta Mines Ltd, Keonjhar
25	Adani Enterprises Ltd,Cg
26	Apar Industries Ltd,Sambalpur
27	Suraj Products Ltd,Rajgangpur
28	Ultratech Cement Jharsuguda
29	Ardent Steel Pvt Ltd, Keonjhar
30	Sarda Mines Ltd, Keonjhar
31	Abc Ashpro,Cuttack
32	Falcon Marine Exports Ltd., Balasore
34	BanswaraSyntex, Banswara
35	Dr.Oetker India Pvt. Ltd., Alwar
36	Jaqar SP-53 & SP 496B, Alwar
37	Maharaja AgroAgro Foods Pvt. Ltd.
38	Roochi Soya
39	Reliance Chemotex
40	Kemwell Biopharma Private Limited
41	Resipharm Pharmaservices Private Limited
42	IPCA Laboratories Limited, Ranoli, Baroda
43	TTK Prestige Ltd., Vadodara
44	J K Lakshmi Cement Ltd., Sirohi
45	Huber Group India Pvt. Ltd., Silvassa
46	Huber Group India Pvt. Ltd., Daman
47	Gadre Marine Export Pvt. Ltd, Chorwad
48	TML Industries Ltd, Bharuch

वित्त वर्ष 2021–22 में निष्पादित जल ऑडिट के ग्राहकों की सूची

क्र0	ग्राहक
49	Gujarat Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd, Ahmedabad
50	Ambuja Cements Ltd., Gir Somnath
51	TranspekSilox Industry Pvt. Ltd., Vadodara
52	TML Industries Ltd., Vadodara
53	Aarti Surfactants Ltd., Silvassa
54	Mayur Dyechem Intermediates Ltd., Vadodara
55	Sun Pharmaceutical Medicare Ltd., Panchmahal
56	Gujarat Insecticides Ltd., Ankleshwar
57	Sabic IP India Pvt. Ltd., Vadodara
58	Astron Paper & Board Mill Ltd., Morbi
59	Archean Chemical Industries P Ltd, Kutch
60	Reliance Industries Ltd., Vadodara
61	Siddhi Industries Ltd., Ahmedabad
62	Lonsen Kiri Chemical Industries Ltd, Padra, Baroda
63	Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd., Surat
64	Saurashtra Cement Ltd., Porbandar
65	Gujarat Sidhee Cement Ltd., Sidheegram
66	Nirma Ltd. Kalol
67	Nirma Ltd. Mehsana
68	Nirma Ltd. Porbandar
69	AIA Engineering Ltd., Ahmedabad- 1
70	BanswaraSyntex, Banswara
71	Dr.Oetker India Pvt. Ltd., Alwar
72	Jaqar SP-53 & SP 496B, Alwar
73	Maharaja AgroAgro Foods Pvt. Ltd.
74	Roochi Soya
75	Reliance Chemotex,
76	M/s Ajanta Pharma
77	M/s Hindustan Unilever Ltd.
78	M/s NEEPCO Ltd.
79	M/s Excelcare Hospitals
80	M/s NEFA Breweries
81	M/s Star Cement Ltd.
82	M/s Rhino Agencies
83	M/s Brahmaputra Crackers & Polymer Ltd.
84	M/s Ultratech Cement Limited,Near Daniyaw Village Shajahnapur
85	M/s. Shah Sponge & Power Ltd, JURI, Near HATA,
86	Metalsa India | Jamshedpur Plant
87	Britania Industries Ltd.
88	Triveni Sainik Mining Pvt Ltd
89	M/s Majhaulia Sugar PvtLtd.
90	M/s. Mateshwari Paper Mill Pvt Limited, Mahuli, Patna City
91	M/s. Smrity Paper Mill Pvt Limited, Chhitma, Mahooli Road, Patna City
92	M/s Madhepura Electric Locomotive plant
93	Bholaram Papers & Power Pvt. Ltd
94	M/s Hindustan Urvarak &Rasayan Limited, Bihat (Nagar Parisad) Barauni,Begusarai, Bihar

वित्त वर्ष 2021–22 में ए पी ओ कार्यक्रमों की सूची

क्र0	स्मार्ट कृषि पर सम्मेलन	तारीख
1	Conference on Smart Agriculture	19-Apr-21
2	5th International Conference on Bio-fertilizers and Bio-pesticides: Marketing and Commercialization	28 April 2021
3	Workshop on Productivity promotion movement in the Digital Age	20–22 April 2021
4	Workshop on Green Productivity for Sustainable Development	7–9 April 2021
5	Basic Training Course on Foresight for Public-sector Organizations	25-27 May 2021
6	Workshop on Diversity and Organizational Performance in the Public Sector	18–20 May 2021
7	Training Course on Critical Big Data Analytics to Drive Productivity (DMC)	26-28th April 2021
8	Conference on Emerging Technologies for Productivity Enhancement	8th April 2021
9	Multi-country Observational Study Mission on Modern Farm Machinery	15-17 June 2021
10	Workshop on Women's Empowerment for Productivity Gains	22-24 June 2021
11	Workshop on Service Design for Business Growth and Improvement	1-3 June 2021
12	Multi-country Observational Study Mission on Advanced Food Safety Management.	28–30 June 2021
13	Individual-country Observational Study Missions	April–December 2021
14	Technical Cooperation Program for COVID-19 Pandemic Recovery: Capability Development on Cold Chain Systems in Agri-food SMEs	1 December 2020–30 November 2021
15	Research on an Aging Asia and Pacific: Preparing for the Future	April–December 2021
16	Management of the APO Accreditation and Certification Program	April–December 2021
17	Development of Demonstration Companies and the Application Guidelines.	April–December 2021
18	Workshop on Ecological Models of Agro-forestry Systems	16–18 June 2021
19	Workshop on Productivity Gain-sharing Models in Agribusiness Enterprises	14–16 July 2021
20	Labor Productivity Index	June–December 2021
21	Research on Labor Market Policies for Changing Market Demands	June–December 2021
22	Research on the Complementarities of the Circular Economy and Green Productivity	June–December 2021
23	Observational Study Mission on Emerging Models of Controlled-environment Agriculture	27–29 July 2021
24	Conference on Enabling Regulations to Accelerate Agricultural Innovations	22-Jul-21
25	Training Course on Productivity Measurement for Service-Sector Organization	21–23 July 2021
26	Conference on Promoting the Circular Economy in Manufacturing through Green Productivity	30-Jul-21
27	Workshop on Modern Food Transportation and Regulation	13–15 July 2021
28	Workshop on Regulatory Ecosystems for Startups	28–30 July 2021
29	Conference on Public-sector Productivity: Ensuring Public Services in the New Normal	25-Aug-21
30	Workshop on Smart Transformation for Various Economic Sectors	21 July to 23 July 2021
31	Multi-country Observational Study Mission on Enhancing Equal Opportunities for Inclusive Engagement of the Workforce	28-30 July 2021
32	Workshop on Enhancing Productivity for SMEs: Measuring and Analyzing Productivity Gains	11-13 August 2021

वित्त वर्ष 2021–22 में ए पी ओ कार्यक्रमों की सूची

क्र0	स्मार्ट कृषि पर सम्मेलन	तारीख
33	Research on Innovation-led Productivity Growth for Middle-Income Trap Avoidance	July–December 2021
34	Training Course on Internet of Things Applications for Smart Manufacturing	25–27 August 2021
35	Conference on Social Empowerment in Agriculture	Thursday, September 2, 2021
36	Workshop on Agricultural Innovations	15–17 September 2021
37	Training of Assessors for the Green Productivity Specialists Certification	23-25 August 2021
38	Workshop on Cyber security and Network Resilience Approaches for Industry 4.0	7-9 September 2021
39	Workshop on Blockchain Solutions for SME Productivity	25-27 August 2021
40	Workshop on Continuing Education for the Aging Societies	15-17 September 2021
41	Workshop on Rural Economic Development through Development of Village Tourism	5-7 October
42	Conference on Urban Agro-ecology and Food Security	Thursday, September 9, 2021
43	Workshop on Digitization of SMEs in the Manufacturing Sector	28-30 September 2021
44	Conference on Organic Farming and Agro-ecology	Thursday, October 7, 2021
45	Training Course for Green Productivity Specialists	13–17 September 2021
46	Workshop on the Circular Economy in the Agro-industry Sector and guidelines on the implementation procedures	12-14 October 2021
47	Strengthening the Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (India)	September–December 2021
48	Workshop on Evaluating Regulatory Quality and Performance to Improve Public-sector Productivity	10-12 Nov 2021
49	Workshop on Enhancing Service Productivity through Effective Business Models	19-21 October 2021
50	Workshop on Development of New Innovation Standards for SMEs	13-15 October 2021
51	Multicountry Observational Study Mission on Service Quality and Productivity for the Retail Industry	27-29 October 2021
52	Research on Need Assessment on Innovation Management	October–December 2021
53	Development of APO-certified Public-sector Productivity Specialists	6-10 December 2021 (three days)
54	Multicountry Observational Study Mission on Support for Digital Transformation for SMEs	10–12 November 2021
55	Training Course on Innovative Aquaculture Models	16–18 November 2021
57	Training Course on Service-sector Productivity Specialists	10–12 November 2021
58	Workshop on Innovations in Farmers' Cooperatives and Producers' Associations	9–11 November 2021
59	Multicountry Observational Study Mission on Data Governance in the Public Sector to Improve Productivity	24–25 November 2021
61	Workshop on Waste Management in Manufacturing SMEs through MFCA and Lean	24–26 November 2021
62	Workshop on Food Storage Models	30 November–2 December 2021
63	Workshop on Modern Mechanization Technologies for Increasing Rice Productivity	24–26 November 2021
64	Workshop on Developing National Innovation Systems	23–25 November 2021
65	Workshop on Innovative Business Models for Industry 4.0	24–26 November 2021

वित्त वर्ष 2021–22 में ए पी ओ कार्यक्रमों की सूची

क्र0	स्मार्ट कृषि पर सम्मेलन	तारीख
66	Workshop on Nurturing Social Enterprises	6–8 December 2021
67	Workshop on the Circular Economy for the SDGs	
68	Workshop on Agroecological Systems	14–16 December 2021
69	Workshop on Adoption of Industry 4.0 Applications for SMEs	7–9 December 2021
70	Training Course on Strategic Management for Public- sector Productivity Enhancement	30 November-3 December 2021
71	Workshop on Requirements and Management System for APO Certification of Persons Scheme	7–9 December 2021
72	Development of APO-certified Public-sector Productivity Specialists	6–10 December 2021
73	Training Course on Data Analysis and Applications for Digitization in SMEs	14–17 December 2021
74	Training Course on Energy Audits and Management	20-24 December 2021 (four days)
75	Workshop on Enhancing Employee Productivity in the Digital Workplace	23–25 February 2022
76	Demonstration Farm on Innovative Agriculture	January 2022–August 2024
77	Development of APO-certified Productivity Specialists	7–11 March 2022 (five days)
78	Workshop on the Internet of Things in Agriculture and Food Supply Chain Management	9–11 March 2022 (three days)
79	Workshop on Decentralized Governance and Public Accountability	23–25 March 2022 (three days)
80	Workshop on Talent Development for the Future of Work	29–31 March 2022 (three days)

ANNUAL REPORT

2021-22

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

(Under Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
योगः कर्मसु कौशलम्
रा० उ० प०
NPC

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

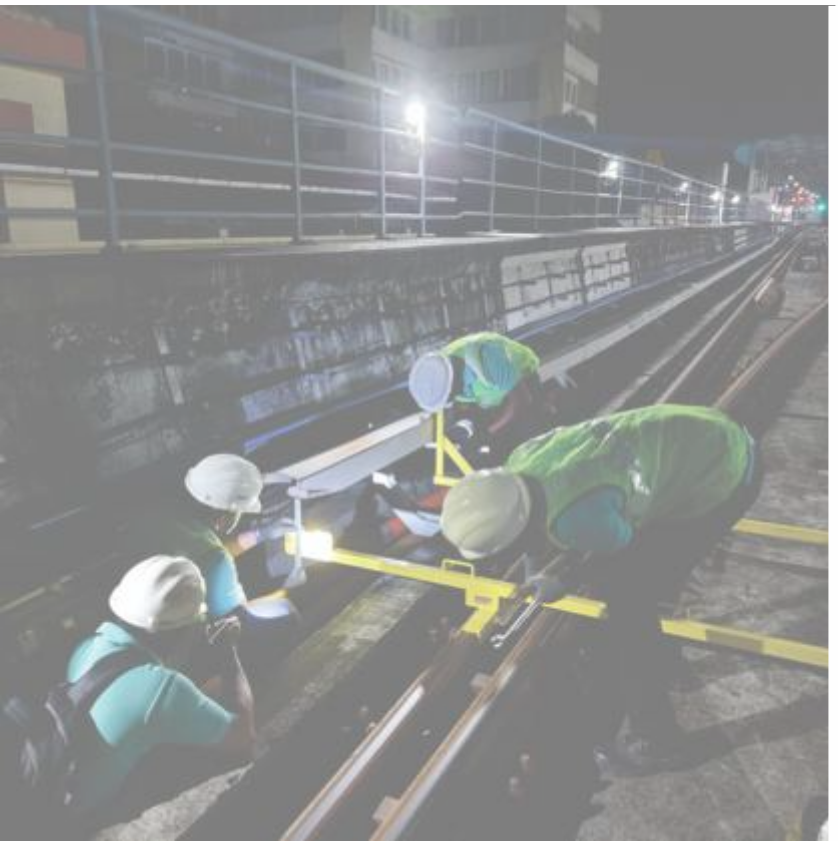

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

HEADQUARTER & REGIONAL OFFICES

NEW DELHI (HEADQUARTER)
Sh. Amitava Ray
Group Head (Admin)
National Productivity Council
Utpadakta Bhavan, 5-6, Institutional Area
Lodi Road, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24607369
Email: amitava.ray@npcindia.gov.in

BENGALURU
Sh. C. Narendra
Regional Director
National Productivity Council 2nd Floor, Abhaya Complex
KSDB Building, 55, Risaldar Street Seshadripuram
Bangalore 560 020
Tel.: 080-23467294
Email: c.narendra@npcindia.gov.in;bangalore@npcindia.gov.in

BHUBANESWAR
Sh. Avijit Nayak
Regional Director
National Productivity Council
A/7, Surya Nagar
Bhubaneswar-751003, Odisha
Tel.: 0674-2397381/26
Email: avijit.nayak@npcindia.gov.in;

CHANDIGARH
Sh. Suvyendu Shivakar
Assistant Director and In-charge of RD
National Productivity Council
Chandigarh, NCDC Building
Bay No. 1 & 2, Sector - 14
Panchkula, Haryana - 134113
Mob. 6287872655
Email: suvyendu.s@npcindia.gov.in

CHENNAI
Sh. D. Sreenivasulu
Head(AIP)
National Productivity Council No.
6, SIDCO Indl. Estate Amabattur
Chennai, Tamil Nadu – 600098
Tel.: 044-26241059, 7200208675
Email: d.sreenivasulu@npcindia.gov.in

GANDHINAGAR
Sh. Shirish Paliwal
Regional Director
National Productivity Council
E – 5, GIDC, Electronic Estate,
Sector 26, Gandhi Nagar, Gujarat – 382028
Tel.: 079-23287344
Email: shirish.p@npcindia.gov.in;gandhinagar@npcindia.gov.in

GUWAHATI
Dr. Rajat Sharma
Regional Director
National Productivity Council
Rajgarh Road, P.B. No. 32, Ulubari P.O.
Guwahati, Assam – 781 007
Tel : (O) 2453396, 2451896 Fax : (0361) 2450160, 0361-3512552
Email: rajat.sharma@npcindia.gov.in;guwahati@npcindia.gov.in

HYDERABAD
Dr. B. Hemant
Regional Director
National Productivity Council
10th Floor, Eastern Wing, Gagan Vihar Complex,
M.J. Road, Nampally Hyderabad
Andhra Pradesh -500001
Tel.: 040-24733473
Email: hemant.rao@npcindia.gov.in; hyderabad@npcindia.gov.in;

JAIPUR
Sh. Mukesh Singh
Regional Director
National Productivity Council
SB-96, Jawahar Lal Nehru Marg,
Bapu Nagar, Jaipur – 302 004
Tel.: 0141-2702935
Email: mukesh.singh@npcindia.gov.in;jaipur@npcindia.gov.in

KANPUR
Sh. Sunil Kumar
Regional Director
National Productivity Council
4th Floor, Kabir Bhavan (U.P.H.C. Ltd.'s building,
Directorate of Industries (U.P.) Campus) G.T. Road
Kanpur – 208 002
Tel.: 0512-2224176
Email: sunil.kumar@npcindia.gov.in

KOLKATA
Sh. S. Mallik
Regional Director
National Productivity Council
9, Syed Amir Ali Avenue, Park Circus
Kolkata,
West Bengal – 700017
Tel.: 033-22876069
Email: s.mallik@npcindia.gov.in,kolkata@npcindia.gov.in

MUMBAI
Ms. Arundhati Chattopadhyay
Regional Director
National Productivity Council
Novelty Chambers, 7th Floor, Grant Road
Mumbai, Maharashtra – 400007
Tel.: 022-23002924, 23071322,9869519366
EMail: achattopadhyay@npcindia.gov.in,mumbai@npcindia.gov.in

PATNA
Sh. P.R. Upadhyay
Regional Director
National Productivity Council
2nd Floor, Sudama Bhawan Boring Road Crossing,
Patna, Bihar – 800001
Tel.: 0612-2558311
Email: pr.upadhyay@npcindia.gov.in;patna@npcindia.gov.in

Vision

NPC to be the knowledge leader in productivity to provide state of our services to the Indian economy to become globally competitive.

Mission

Contribute to the sustainable, inclusive socioeconomic development of the country by enhancing productivity.

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

QUALITY POLICY

We, at NPC are committed to achieve excellence in providing best in class Services to make Indian economy globally competitive and,

- Act as Catalyst for assisting Government and Industry,
- Promote Productivity through Consultancy, Research, Training and Skill Development,
- Support and Develop ecosystem for Innovation, Quality and Sustainability,
- Ensure Client Satisfaction.

We shall strive to upgrade our Services, human capital and infrastructure by reviewing effectiveness of management systems for continual improvement.

Director General

Contents

Particulars	Page No.
From The Desk of DIrector General	v
About NPC	1
Leadership & Guidance	6
Professional Services	9
Domain Specific Services	11
Other Initiatives	15
Insight into major activities during FY 2021-22	17
Glimpses of Major Assignments	20
Select list of Consultancy assignments undertaken	49
Select list of Training Programmes	51
Select list of Webinars/Online Programmes	52
Select list of Water Audits undertaken	56
Select list of APO Programmes undertaken	58
Anuual Accounts of FY 2021-22	61

FROM THE DESK OF DIRECTOR GENERAL

The productivity movement in India, started in the 1950s and spearheaded by National Productivity Council (NPC), has contributed immensely to the country's socio-economic development. The productivity movement is needed more now than ever before, especially in the context of Aatmnirbhar Bharat. As a nodal body for productivity movement in the country, NPC has been developing and rendering leading edge consultancy and training services in various domains which are of paramount importance for any organization, be it public, private, MSME or cooperative through its huge talent pool from various fields such as Economics, Industrial Engineering, Human Resource Management, Energy, Environment, IT, Project Monitoring and Evaluation, Research, Agriculture, Allied agriculture etc.

Fostering our mission to contribute to the sustainable and inclusive socio-economic development of the country by enhancing productivity, we have been relentlessly serving the nation. Moving forward, we thank all our clients and Department for Promotion of Industries and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry for their support which has reinforced our commitment and belief in our values and purpose. I also thank our large network of Local Productivity Councils (LPC's) for assisting us in fostering productivity movement. I extend deep appreciation for NPC team and hope that they would continue to work for a stronger Bharat.

Sundeep Kumar Nayak, IAS
Director General

ABOUT NPC

GENESIS

Post independence during early 1950s, imperative need was felt for conscious and pragmatic productivity drive in India with focus on industrialization in order to compete and become at par with other countries of the world. Further, a high level delegation led by Dr. Vikram Sarabhai, father of Indian Space Movement, visited Japan in 1956 and submitted its report in1957 with recommendation to establish a central body to spearhead the productivity movement across the country covering various sectors of economy. In pursuance of this productivity delegation, its recommendations were disclosed at a seminar on productivity held on November 1957 under the auspices of the then ministry of commerce and industry. The seminar laid down certain guidelines for the establishment of an all-India body to promote industrial productivity. Thus, National Productivity Council (NPC) came into existence as an autonomous body with its head office in New Delhi.

NPC is a national level organization to promote productivity culture in India. Established by the Ministry of Industry, Government of India in 1958, it is an autonomous, non-profit organization with equal representation from employers' & workers' organizations and Government, apart from technical & professional institutions and other interests.

NPC since its inception has led and is leading the productivity movement in the country by extending its specialized services to help various stakeholders understand the difference between production and productivity and to comprehend the relationship between input resources and output achieved along with the means and ways to optimize the same thereby enhancing profitability and competitiveness. Besides this, NPC has also played a pivotal role over the past 64 years in capacity building of various stakeholders (Govt / PSU / PVT) in order to achieve the productivity mandate. NPC has also grown since its inception and has established pan India presence in 13 cities across the countries including a training institute at Chennai and also has diversified its spectrum of services in areas crucial to industrial / economic growth. NPC has also acclimatized to the changing industrial scenario and has established a centre of excellence in industry 4.0 in collaboration with APO for awareness generation and making Indian MSMEs I4.0 ready.

INTERNATIONAL LINKAGE

NPC has also established Centre for Excellence in Training for Energy Efficiency (CETEE) in its campus at Chennai. CETEE is the culmination of Indo-Japanese Governmental Co-operation and has been implemented with the assistance of Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power, Govt. of India, New Energy Development Organization (NEDO), Govt. of Japan.CETEE aims to achieve its objectives through its state of the art Hands-on Training facility to impart the advanced Energy Efficiency Technology and Techniques in the field of energy efficiency. CETEE is based on "learning by doing" pedagogy where trainees are exposed to "real-industry" projects.

Government of India is the founder member of the Tokyo-based Asian Productivity Organisation (APO), an Inter-Governmental Body, since 1961. NPC represents Government of India in APO and is also the Nodal Agency in charge of organizing Indian participation in the training programmes, workshops and seminars offered by APO to Member Countries on different subjects related to productivity. NPC also hosts APO programmes in India every year for participants of Member Countries.

APO Member Countries

STRUCTURE

The Union Minister for Commerce and Industry is the President of Council, and the Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade is the Chairman of the Governing Body of the Council. The Director General is the Principal Executing Officer of the Council.

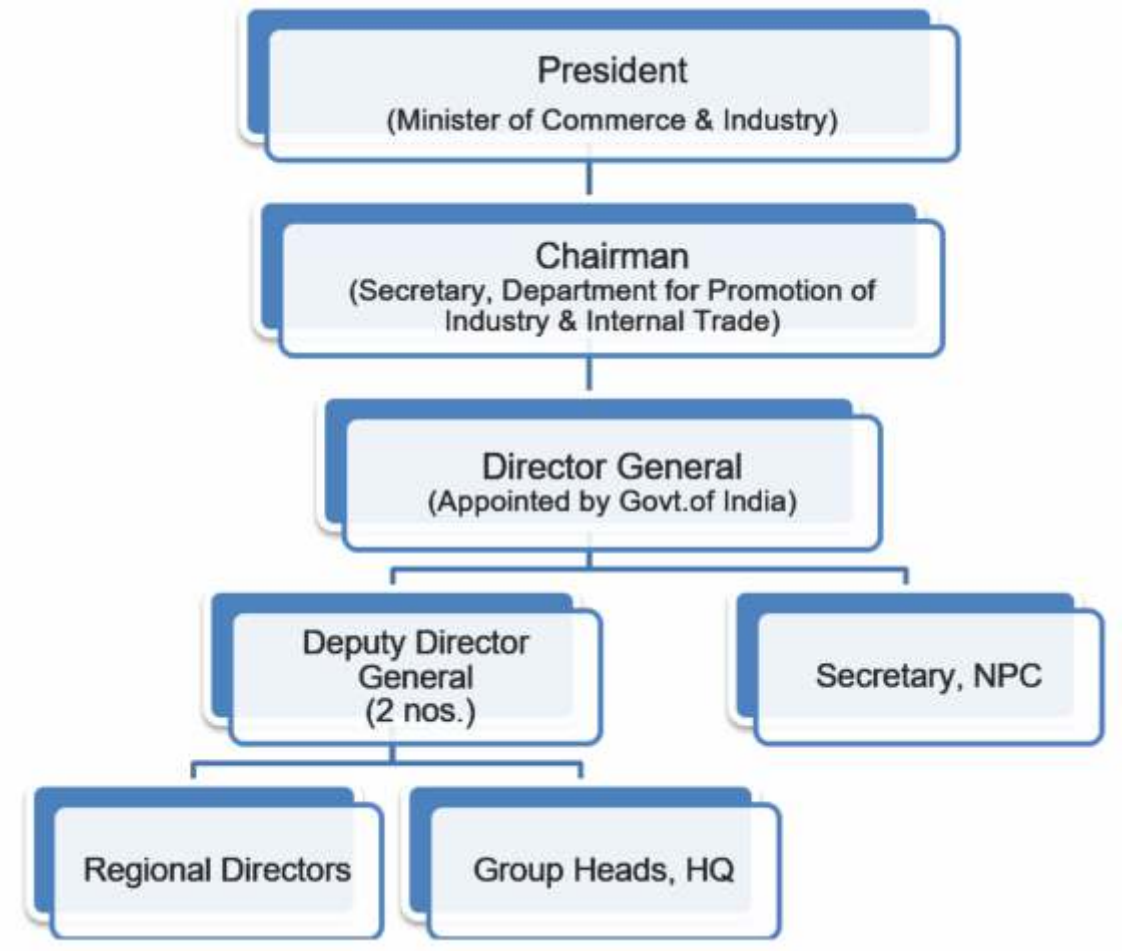

Table-1 Organisational Structure of NPC

PRESENCE

NPC has 12 Regional Offices located in major State Capitals/industrial centre with Headquarter in New Delhi and one Training Institute at Chennai, as shown in the Map. NPC has strength of around 110 full time professional/ consultants, additionally services of outside specialists and faculty are also enlisted on project-based requirements.

Pan-India Presence	
HQ, Delhi	1
Regional Directorates	12
AIP Institute, Chennai	1

OBJECTIVES OF NPC

I. To promote innovation - led productivity in a sustained manner in all spheres of national economy through holistic and inclusive approach by addressing the triple bottom line – Economic, Environmental and Social.

ii. To propagate productivity consciousness and culture amongst Govt., Business and Society.

iii. To demonstrate value addition through generation and application of advanced productivity tools and techniques for multiplier effect.

iv. To act as a total solution provider for Industry, Services, and Agriculture sectors for augmenting productivity through Training, Consultancy and Research wherever needed through alliances and partnerships

v. Act as a catalyst in institution building and developing platforms for collaborative networking to strengthen the productivity movement.

vi. To act as a think tank by providing productivity related evidence-based policy support and advice in while tracking the emerging trends.

vii. To be an independent oversight entity for various national programmes, schemes and interventions.

viii. To recognize productivity champions through awards, affiliations, certifications, accreditations etc.

ix. To enhance international outreach for sharing the gains of productivity on mutual basis.

x. To be repository of productivity and competitiveness data across all sectors at the state and national level.

xi. To devise national productivity standards across all sectors and self-assessment web-based measurement tools for productivity diagnosis.

ACTIVITY PROFILE

NPC aims at being a promotional body with a professional approach and competence. It seeks to realize its primary objective of productivity promotion through various means, including:

Consultancy: NPC undertakes consultancy work to promote productivity in the areas of agriculture, rural development, industry, and service sector. Its clientele includes Central and State Governments, Private and Public Corporate sectors, their agencies, and other client groups. The consultancy services of NPC rely on problem-solving and total solutions through a participative and holistic approach with a developmental approach.

Training: Human Resource Development programmes are undertaken for various levels of personnel engaged in the development of various sectors.

Promotion: Propagating productivity and quality consciousness through seminars, workshops, publications, organization of productivity and quality events, campaigns, motivational awards and other suitable methods.

Research: Undertaking evaluations and impact studies, conducting research surveys and studies both at micro and macro level in the area of socio-economic & technological development. Productivity measurement studies are also undertaken to develop a database for various sectors.

Strategic Planning: Identifying frontier areas in the field of productivity aand quality, catalyzing work on them suiting to the local needs and providing inputs to policymaking.

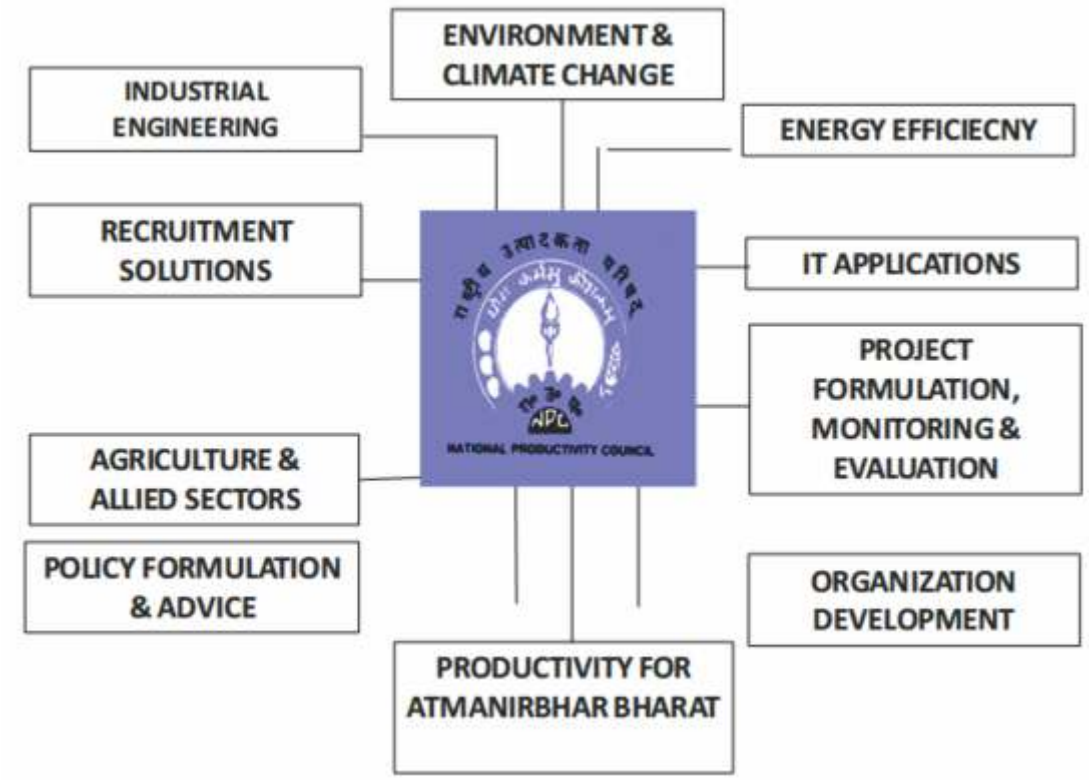

LEADERSHIP & GUIDANCE

Shri Piyush Goyal

Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs,
Food & Public Distribution and Textiles

Hon'ble Shri Piyush Goyal is the Minister of Commerce & Industry (2019-present), Consumer Affairs, Food & Public Distribution (2020-present), Textiles (2021-present) and Leader of the Rajya Sabha (2021-present). He has also held the portfolio of Minister of Railways, Finance, Corporate Affairs, Coal, Power, New & Renewable Energy and Mines previously. He is an ex -officio President of National Productivity Council.

In his tenure as Minister of Commerce & Industry, India achieved its highest ever exports of about $675 billion in 2021-22. He led the signing of a Free Trade Agreement (FTA) with UAE, the fastest ever negotiated FTA globally and the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA), India's 1st agreement with a developed country after a decade. He oversaw the launch of Production Linked Incentive (PLI) Schemes to bring manufacturing at the center stage and emphasize its significance in driving growth and creating jobs.

As Minister of Consumer Affairs, Food & Public distribution, he led the implementation of the world's largest food security programme, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) by distribution of free foodgrains to nearly 80 crore people over 2 years, providing support to the poor, vulnerable, weaker sections of society, who were affected the most during the COVID-19 pandemic. As Minister of Railways, India achieved the best ever safety record of zero passenger deaths in rail accidents. The Power, Coal and New & Renewable Energy ministries led transformational changes in India's power sector and successfully implemented the world's largest LED bulb distribution programme (UJALA) for energy efficiency. He also received the 4th Annual Carnot Prize in 2018 recognising the pathbreaking transformations in India's energy sector.

Shri Goyal has had a brilliant academic record - all India second rank holder Chartered Accountant and second rank holder in Law in Mumbai University. He was a well-known investment banker and has advised top corporations on management strategy and growth. He also served on the Board of India's largest commercial bank, the State Bank of India and Bank of Baroda. He was also nominated by the Government of India to the Task Force for Interlinking of Rivers in 2002.

LEADERSHIP & GUIDANCE

Shri Som Parkash

Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry

Hon'ble Shri Som Parkash, an I.A.S. (Retd.) officer of 1972 batch. He had started his career as a research officer in the Punjab State Planning Board in 1972. Thereafter, he became an excise and taxation officer in the Punjab Excise Department. He is M.A.(Economics) From Punjab University Campus, Chandigarh.

Shri Som Parkash had served as the deputy commissioner of Faridkot, Hoshiarpur and Jalandhar and also held posts like the Labour commissioner, Punjab Urban Planning and Development Authority (PUDA) Chief administrator, managing director of the Punjab Financial Corporation and Director of the Social Security Department. He had been also two-time Member Legislative Assembly (MLA) from the Phagwara Assembly constituency, (Punjab). Now he is Member of Parliament from Hoshiarpur Constituency.

LEADERSHIP & GUIDANCE

Shri Anurag Jain, IAS

Secretary, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry and Chairman NPC

Shri Anurag Jain, IAS (MP 1989), is Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India and ex-officio Chairman of NPC. Prior to taking over as Secretary, DPIIT, he served as Vice Chairman of Delhi Development Authority (DDA). He has also served as Joint Secretary in Prime Minister's Office. He as Joint Secretary in the Ministry of Finance is credited with conceptualizing and implementing one of the most successful initiatives 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana', the largest financial inclusion programme in the World.

Shri Anurag Jain has vast experience of Finance Sector, Information Technology, District Administration and Rural Development. As Secretary to Chief Minister, Madhya Pradesh, he was the prime mover of enactment of Public Service Delivery Management Act, an innovative concept adopted by more than a dozen States in the country. As Secretary, Information Technology, Govt. of Madhya Pradesh, he was instrumental in taking the State to top rungs in e-Readiness Assessment of States and Union Report. He was Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of Madhya Pradesh and was heading Finance Department. He also served as District Collector of Bhopal.

PROFESSIONAL SERVICES

NPC is a one stop solution for providing consultancy, capacity building, guidance and mentorship for any kind of productivity related issues.

a. **Productivity Promotion:** The formation of National Productivity Council is being celebrated every year all over the country by commemorating 12th February as Productivity Day and the whole month as Productivity Month. The purpose is to draw the attention of all concerned, towards the concept and encourage implementation of productivity tools and techniques with contemporary relevant themes.

b. **Consultancy:** Professional consultancy services are provided by NPC for improvement of productivity, quality, profitability, and growth at entire organizational level. NPC is promoting and disseminating productivity skills through consultancy to the private and public corporate sectors, Central and State Governments, industry associations, their members, etc.

c. **Research:** NPC conducts activity-based research on project basis, to collect and analyze data and information on productivity-related topics in various sectors of the Indian economy. The topics include the existing challenges and emerging needs of sectors.

d. **Training & Capacity Building**: NPC's major training activities are primarily focused on developing human resources: people who can act as catalysts within the productivity movement of Indian economy. These training courses cover a wide range of productivity management issues in various areas including industry and service, agriculture, energy, environment, and local/regional development. NPC also organizes regional and sectoral conferences to impart knowledge on emerging issues and findings and discuss management strategy for the same. It is conducting studies, research surveys and evaluations on matters relating to productivity /quality improvement for enterprises, governments and others.

e. **Monitoring & Evaluation:** NPC has been involved in productivity assessments and directly and indirectly in Monitoring & Evaluation (M&E) studies and Performance Management of various Government funded projects and schemes, as well as private sector initiatives including industrial processes and across supply chains. NPC through its various divisions has undertaken a vast variety of projects across sectors and sub-sectors for government, international organizations and other agencies. NPC is well eqipped with the tools that are utilized for project management and planning and for undertaking econometric and statistical analysis of data that need to be obtained through suitable sampling technique, besides having GIS software pertaining to GIS based applications. NPC has further developed institutional linkages in order to offer cloud based IT platforms for real time Monitoring & Evaluation of projects, including Government schemes and infrastructure development projects.

f. **Recruitment:** NPC is conducting both Online & Offline examinations for various government and private organisations such as for Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM), Airport Authority of India, BSES, Paradip Port Trust etc. NPC specializes in providing end to end solution for recruitment such as application processing, providing payment gateway, conduct of offline and online examination, question paper setting, evaluation, conduct of interviews etc. NPC has been conducting examinations at PAN India level and also conduct trade related skill tests and typing tests.

NPC aims to provide cost effective, fair and transparent examination procedure and ensures the completion of the entire examination process in an unbiased, strictly confidential, hassle free manner.

g. Dr. Ambedkar Institute of Productivity (AIP) is the Training Institute of NPC having facilities of classrooms, hostels, and state of art training facilities. AIP has Centre of Excellence for Training in Energy Efficiency (CETEE) which is well equipped with various Industrial Energy Utility Equipments designed to practically demonstrate ways of identifying energy efficiency opportunities and energy conservation techniques as applicable in industries. The trainees can operate the equipments and change the operating parameters to learn the impact of efficient operation, build energy saving scenarios and modes, conduct testing for performance evaluation of systems through:

- Pump Training Facility
- Compressor Training Facility
- Fan Training Facility
- Boiler Training Facility
- Steam Trap Training Facility
- Open Burner Training Facility and
- Combustion Furnace Training Facility

DOMAIN SPECIFIC SERVICES

- **AGRI BUSINESS SERVICES:**

Agri-Business group is engaged in Consultancy & Awareness generation for enhancing productivity in the spheres of Agriculture, Rural Development, Food Processing and allied sectors, both at micro and macro levels for National and International Organizations. The emphasis is to make the establishments and the projects cost-effective, target oriented, responsive to the dynamic socio-economic environment so as to achieve societal aspirations.

NPC's strength in the area of Agri Business lies in:

- Evaluation, Monitoring and Impact Assessment of Developmental Schemes and Programs
- Policy Formulation and Program Management
- Formulation of Energy & Rural Development Plans
- Cooperative Augmentation
- Data Base Development
- Crop Productivity Improvement
- Agribusiness & Post Harvest Management
- Techno Economic Feasibility Studies
- Productivity Measurement & Enhancement in Food Processing, Dairy & Poultry Processing Industries
- Value chain management in food and agri-business
- Conduct of trainings, programs, seminars & conferences
- Conducting Food Safety Audits of FBOs and Warehouses

ECONOMIC SERVICES

Economic Services Group of NPC specializes in macro and sub-macro level productivity and competitiveness studies with the objective of identifying relevant technological, economic and social factors and analysing the performance of the unit, sector and economy.

ES Group has undertaken a number of third party evaluation studies of various Central Government Ministries and Departments. These evaluation studies have substantially contributed towards modifying and making the schemes more useful.

Besides the evaluation studies, ES group has brought 4 special issues of Productivity Journal (Quarterly). NPC also provided partner institute services to IMD Switzerland in the preparation of World Competitiveness Yearbook 2020.

ES group also provided National expert services to Asian Productivity Organisation (APO) Japan in the forthcoming publication of APO Productivity Databook 2020.

The Division has a core team of specialists from Economics, Statistics, Management and Technology. The core competence of the group lies in:

- Sectoral / Industry / Product Profile Studies.
- Market Potential Assessment.
- Socio-economic Impact Studies.
- Policy Focus / Impact Studies.
- Productivity Data-Base Development.
- Productivity & Competitiveness Studies.
- Monitoring & Evaluation of Government Schemes.
- Marketing and Product Promotion Studies.

ENERGY MANAGEMENT

Energy Management (EM) Division of NPC offers Consultancy / Training services since 1964. The core strength of EM professionals includes about 20 BEE certified Energy Auditors. The areas of expert services of this division are:

- Energy Management and Audit in all types of Industries, Commercial buildings & establishment, Power- generating plants, Distribution system.
- Demand side Management potential with focus on the industrial sector.
- Strengthening policy aspects and increasing public awareness of Energy Conservation issues through modular training programmes for Senior, Middle and Shop floor level executives.
- Technological Upgradation and Resource Conservation in SME's through cluster approach.
- Technical Expertise Services to APO member Countries in Energy Efficiency.
- Hands on training at Centre Excellence for Training in Energy Efficiency and Indo-Japan project on Regional Energy Efficiency Centre at Dr. Ambedkar Institute of Productivity, Chennai.

ENVIRONMENT MANAGEMENT

Environment Management Group focuses on waste minimization and pollution prevention in line with productivity improvement. The Environmental services include Monitoring & Analysis, Design of pollution control systems and Resource Conservation. With the assistance of Indo-German Bilateral co-operation initiated in 1985, the Group has developed expertise in diversified fields in Environment Management.

The Group has assisted more than 2500 enterprises including SMEs and large industries, Central/State Pollution Control Boards, Ministry of Environment & Forests at Central/State level and several International organizations. The Group is extending its expert services to Asian Productivity Organisation (APO) and SAARC Member countries. The services offered include:

- Cleaner Production.
- Solid & Hazardous Waste Management.
- Biomedical Waste Management.
- CIS & Regional Environment Planning.
- Water & Air Pollution Control.
- Green Productivity.
- Environmental Audit & Environment Management System.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The HRM Group focuses on continuous development and growth of Human Resources to enhance competitiveness of the organisations. Consultancy and Training Services are provided in the following areas:

- Manpower Planning & Rationalisation.
- Organization Re-design Studies.
- HR Policy and Manual Review study.
- Competency / Skills Mapping / Assessment.
- Training Needs Assessment & Analysis.
- Counselling & Re-training for Redeployment.
- Job/Employee/Customer Satisfaction Surveys.
- Impact Evaluation Studies.
- Performance Management System.
- Complete Offline Recruitment Solutions.
- Job Description / Specification Review & Designing.
- Team Work & Team Management.
- Transformational Leadership & Self-Motivation.
- Communication & Presentation Skills.
- Problem Solving & Decision Making.
- Stress & Time Management.
- Knowledge Management.
- Effective Office Management.
- RTI Act Programmes.
- Programmes on Office Procedures.

INFORMATION TECHNOLOGY

The key strength of the IT group is the excellent knowledge and skill-base coupled with the strong system skills to meet the specific needs of the clients. The major business areas are consultancy and training.

NPC, IT Group has been offering services consultancy services for Strategic Policy & Planning matters for e-Governance/ICT Projects/Knowledge Management and web based application development as per sector specific as well as capacity building initiates for skill development of employees in IT-related areas for various organizations.

The consultancy services offered by IT group include:

- Business Process Re-engineering and Compliance Audit of the ICT initiatives
- e-Governance initiatives assessment and promotion
- Knowledge Management implementation and assessment
- Project Management Services for ICT project implementation
- Strategic Planning for Organizational ICT policy
- Web Based application development
- Promotion & Assessment of Innovations in ICT.

NPC, IT Group provides training services in various areas related to application of Information Technology in Management. Apart from general training programmes at regular intervals, it also offers customized training services in different areas.

INDUSTRIAL ENGINEERING

Industrial Engineering Group focuses on Process Improvement initiatives for productivity enhancement. Through Consulting, Workshop & Training it creatively applies its skills and experience to those components that profoundly affect an organization's performance and provide a foundation for growth and success. The services to the organizations are being provided in the following areas:

- Best Practices Benchmarking.
- Process and Productivity Improvement studies.
- Organizational restructuring and Manpower Rationalization.
- Lean Manufacturing.
- Productivity linked incentive schemes.
- Six Sigma
- ISO 9001 : 2015 & Quality Management.
- Assessment based on EFQM / MBNQA Business Excellence Framework.
- Project Management
- Time & Motion Study

INFORMATION TECHNOLOGY

The key strength of the IT group is the excellent knowledge and skill-base coupled with the strong system skills to meet the specific needs of the clients. The major business areas are consultancy and training.

NPC, IT Group has been offering services consultancy services for Strategic Policy & Planning matters for e-Governance/ICT Projects/Knowledge Management and web based application development as per sector specific as well as capacity building initiates for skill development of employees in IT-related areas for various organizations.

The consultancy services offered by IT group include:

- Business Process Re-engineering and Compliance Audit of the ICT initiatives
- e-Governance initiatives assessment and promotion
- Knowledge Management implementation and assessment
- Project Management Services for ICT project implementation
- Strategic Planning for Organizational ICT policy
- Web Based application development
- Promotion & Assessment of Innovations in ICT.

NPC, IT Group provides training services in various areas related to application of Information Technology in Management. Apart from general training programmes at regular intervals, it also offers customized training services in different areas.

INDUSTRIAL ENGINEERING

Industrial Engineering Group focuses on Process Improvement initiatives for productivity enhancement. Through Consulting, Workshop & Training it creatively applies its skills and experience to those components that profoundly affect an organization's performance and provide a foundation for growth and success. The services to the organizations are being provided in the following areas:

- Best Practices Benchmarking.
- Process and Productivity Improvement studies.
- Organizational restructuring and Manpower Rationalization.
- Lean Manufacturing.
- Productivity linked incentive schemes.
- Six Sigma
- ISO 9001 : 2015 & Quality Management.
- Assessment based on EFQM / MBNQA Business Excellence Framework.
- Project Management
- Time & Motion Study

TECHNOLOGY MANAGEMENT

Technology Management Services aim at improving Physical Assets Productivity in all the sectors of economy. Latest hardware and software have been acquired to execute consultancy projects and provide demonstration during the training courses. Consultancy and Training services are offered in the following areas:

- 5 S Implementation & Certification
- Technology Evaluation Studies
- Total Productive Maintenance
- Safety & Risk Assessment& Audits
- Maintenance Systems
- Condition Monitoring
- Maintenance Audit
- Third Party RTI Transparency Audit

NPC professionals have worked closely with the various institutions of international prominence like GTZ, Germany, Fraunhofer's Information Centre Benchmarking, German, Centre for Interfirm Comparison, U. K., PIMS, U.K., American Productivity and Quality Centre, USA, Jarett Thor International, USA, Asian Productivity Organisation, Tokyo, ILO, UNDP, UNEP etc.

OTHER INITIATIVES

Transparency initiatives

NPC conforms to statutory requirement stipulated by the Government of India and its working is based on well defined and transparent norms.

Right to Information Act, 2005

In pursuance of its goals of transparency, proactive disclosure and compliance to statutory obligations, NPC has been effectively providing information sought under the Right to Information (RTI) Act, 2005. Public Information Officers have been designated to comply with the statutory obligations under the RTI Act, 2005. The details of the CPIO, PIO and Appellate Authority are available on the NPC website.

Enhancing Vigiliance

Vigilance is an integral part of NPC management functions, aimed at ensuring robust systems and work practices, along with well laid out processes with effective checks and controls. It comprises preventive surveliance, and punitive measures, undertaken by the Chief Vigilance Officer (appointed by the GoI), in liaison with NPC's management.

Vigilance Awareness Week was observed from 26.10.2021 to 01.11.2021 with the theme "Independent India @75: Self Reliance with Intigrity". The activities commenced with the administration of a pledge in Hindi and English,

Surveillance measures like perusal of inspection reports and maintenance of data on non-performing assets, scrutiny of annual property statements and contracts, and random checks were undertaken.

Outsourcing

To meet the short fall in staff, NPC has been engaging suitable personnel on contractual basis. The performance of the outsourced persons is assessed periodically and corrective action is taken to ensure that the quality of the service outsourced conforms to the required level. It is also ensured that the service provider makes payments to persons deployed at NPC as per the minimum wages notified by the local government and also in compliance with other statutory requirements, in case of contractual staff hired through an agency.

NPC Library

NPC has a well equipped library with over 20220 books, journals, sector specific reports, productivity journals of APO, Magazines, technical journals, etc. It subscribes to 29 daily newspapers including 12 newspapers in Hindi published from Delhi and some metropolitan cities. The library uses Library Management Automation Software System (LIBSYS 4X) for storage and retrieval of information.

Knowledge Management Portal

Knowledge Management is one of the important processes of the total KM program of any organization. It helps in creating a platform for knowledge contribution, sharing and discussing for the employees of the organization. NPC's Knowledge management portal is repository of study reports, policy documents, training manuals, proposals, administrative notifications, online leave management etc.

INSIGHT INTO MAJOR ACTIVITIES DURING 2021-22

Hindi Pakhwada

The period between 14 Sep 2021 to 28 Sep 2021 was observed as “Hindi Pakhwada” across all regional offices and headquarters of NPC. During this period several activities like Hindi Debate, Hindi Essay writing competition, Hindi Poetry recitation, dictation etc were organized to motivate employees to adopt Hindi as their medium of official working. Top performers were awarded in each category of competitions. The events were organized mostly in online mode due to COVID restrictions..

Hindi Pakhwada Celibrations

GB MeetIng

The 111 Governing Body meeting of NPC was held on 29th March 2022 at DPIIT, under the Chairmanship of Shri. Anurag Jain, IAS, Secretary to GoI, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry. The meeting was attended by Representatives from Ministry of MSME, CSIR-NIScPR, FICCI, INTUC, AIFLPC (All India Federation of Local Productivity Council), etc.

NPC presented its major highlights of the activities of last three years (2018-2021) and the flagship projects undertaken. NPC discussed the new initiatives such as digital transformation of NPC and also the financial performance of NPC for the period FY2018-FY 2021.

In addition, NPC also discussed the activities planned for future, which included AMRIT KAAL and NPC in 2047, advancement of innovative and sustainable revenue streams, converting long term and high value pan India Projects into niche areas of NPC and expanding new revenue streams, upgradation of Information technology Infrastructure.

Productivity Promotion

NPC was established on 12th February 1958, since then every year on 12th February NPC celebrated its foundation day as Productivity Day. In February 2022, NPC celebrated the **"Productivity Month 2022" with theme – "Self Reliance Through Productivity"** by conducting training programs at different PSUs, Universities, Private organizations to inculcate the practices of productivity in different areas.

Major Productivity Week Events:

During the Productivity Week 2022, NPC Regional Directorate, Guwahati organized a total of 2 (Two) webinars in association with Indian Oil Corp. Ltd., Guwahati with about 50 participants on 15th Feb. 2022 entitled "Hydrogen Fuel Perspectives in Energy Transition" and on 17th Feb. 2022 entitled " Net Zero Emission and Way Forward".The program was held and organised by IOCL, Guwahati on their online platform. (Photographs are not available)

One Residential Program was organized during 14-18 Feb. 2022 at Gangtok on Procurement, GeM, Arbitration and Contract Management sponsored by DPE, Govt of India.20 participants attended the programme.

(Bhupendra Patel)
Chief Minister, Gujarat State

Date : 10.02.2022

MESSAGE

The right production process for each organization typically depends on factors like available technology, equal quantity of each product, how many products the company needs to produce and organization structure as well. Gujarat has established itself as a global business destination for next generation sustainable manufacturing and service industry that stimulate development and balanced regional growth. **Father of the nation Mahatma Gandhi** was earnest on the idea of Swadeshi towards making our country **"Atma-Nirbhar"**.

I am much pleased to learn that after formation of the **National Productivity Council in 1958**, 12-18 February of each year is being observed as **"Productivity Week"** to enhance productivity consciousness across all sectors of the company throughout the country. It is my appeal to all citizens and industries of the state, that during the forthcoming Productivity week, please adopt modern concepts of **Productivity improvement, and take-up "Make in India and Vocal and Local as the new definition of Swadeshi to attain self-reliance"** for further socio-economic growth and enhanced economic opportunities in Gujarat State. I convey my best wishes to National Productivity Council, Gandhinagar for conducting productivity improvement related activities in the state.

(Bhupendra Patel)
Chief Minister, Gujarat State

National Productivity Council

Message from Hon'ble Chief Minister of Gujarat for propagating productivity culture in the state was communicated to the stakeholders in coordination with Local Productivity Councils and other stakeholders in the Gujarat state.

The sessions on productivity concepts were conducted at office of Regional Directorate, Gandhinagar for internal stakeholders and employees.

NEW INITIATIVES

Setting up of IPL Centre for Rural Outreach

Indian Potash Limited has joined hands with NPC and has established the IPL Centre for Rural Outreach (ICRO) with the involvement, technical expertise and resources of NPC.

ICRO has been established as part of the Corporate Social Responsibility of IPL wherein NPC will be the service provider in execution of the project by ICRO and the project will have pan India activities for a period of three years. The major activities carried out by ICRO through NPC include conduct of rural outreach programmes, biomedical waste management studies in hospitals, energy / water audits in MSMEs, internship programmes etc.

Meeting of Advisory Committee of ICRO

GLIMPSES OF MAJOR ASSIGNEMNETS

❖ Study on Review of Work Allocation and Staff Pattern in Five Thermal Power Stations of TANGEDCO, Tamil Nadu

Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited (TANGEDCO) assigned the project to review the work allocation and staff pattern in their five Thermal Power Stations on nomination basis to AIP, NPC.

The study was completed at Tuticorin Thermal Power Station (TTPS) wherein optimization of man power requirement was done by 42.3% across 11 divisions.

Besides, recommendations for productivity improvement for each division and overall TTPS are given by NPC which was accepted by the management of TANGEDCO. **NPC Team at Coal Jetty, TTPS**

Thoothukudi Thermal Power Station, Tamil Nadu

The next phase study is being carried out at North Chennai Thermal Power Station-II (NCTPS-II).

Thoothukudi Thermal Power Station, Tamil Nadu

NPC Team at Coal Jetty, TTPS

❖ Conduct of 21st National Certification Examination for Energy Managers and Energy Auditors

On behalf of The Bureau of Energy Efficiency, the 21st National Certificate Examination (NCE) was conducted on 25th and 26th September 2021 at 24 centers across India. The total project value was 1, 99, 92,450/- (One crore Ninety-Nine lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred Fifty only) exclusive of GST. A total of 5641 candidates had registered for the exam out of which 592 candidates have qualified as Energy Managers and 179 have qualified as Energy Auditors. So far, NPC has created a pool of 9631 certified Energy Managers and 10609 Energy Auditors which supports the fulfillment of National Mission for Enhanced Energy Efficiency.

Exam Centre

Exam Team – Chennai Centre

❖ **Examination for Grant of Certificate of Proficiency (CoP) as Boiler Operation Engineer (BOE) under the Boilers Act, 1923 held on 11th and 12thDecember 2021**

Central Boilers Board (CBB), DPIIT, MoCI, GoI has entrusted AIP, NPC to conduct the examination for Grant of Certificate of Proficiency (CoP) as "Boiler Operation Engineer (BOE)" for a total value of Rs. 85.77 lakh. The examination was conducted on 11th and 12th December 2021 in 17 centers across India. A total of 3196 candidates applied and 2756 candidates appeared in the written examination and out of which 1893 candidates cleared the written examination and qualified to attend the Oral Examination.

This enabled AIP, NPC to assist CBB in bridging the gap of market requirement of certified BOEs across different states of the country, besides reducing the redundancy of conducting the examinations at each state level separately

Shri. TSG Narayanan, Technical Advisor (Boilers)

Snapshot of Shri T.S.G. Narayanan inspecting Chennai centre

❖ **Study of all the manufacturing operations of 200th WAP 7 Loco No. 39184 as a part of assignment of Diesel Locomotive Works(DMW), Patiala**

NPC , Chandigarh completed Time Study of all the manufacturing operations of 200th WAP 7 Loco No. 39184 as a part of assignment of Diesel Locomotive Works(DMW), Patiala(Punjab), Ministry of Railways on "review of Group Incentive scheme" and flagging off the loco was done by Shri S N Dubey, Principal Chief Administrative Officer, DMW Patiala on 22-09-2021 .

200th WAP 7 Loco No. 39184

❖ Risk assessment Study of Hydro, Solar, Wind and Thermal projects of SJVN Limited, Shimla

NPC Chandigarh carried out risk assessment of Hydro, Solar, Wind and Thermal projects of SJVN Limited, Shimla and risk mitigation plans were prepared. A gap assessment was done to determine the gaps in current practices of SJVN and identify the best practices as laid down in ISO 31000:2018 to bridge the gap.

Meeting with officers of SJVN and NPC for Risk Assessment Study

❖ MANPOWER MAPPING/MANPOWER ASSESSMENT STUDY OF THE TRIBUNE TRUST

NPC, Chandigarh conducted manpower mapping/manpower assessment study of Chandigarh Office, Tribune Printing centres located at Chandigarh, Jalandhar, Bhatinda and Gurugram and Tribune Sub Offices located at Delhi, Jalandhar, Bhatinda and Gurugram. The objective of the study was to improve efficiency in operation of the trust through manpower rationalisation for Editorial and Business operations and other allied activities

❖ AWARENESS PROGRAMME ON BASICS OF LIGHTNING PROTECTION FOR HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD., MUMBAI

RD, Chandigarh conducted an awareness programme on basics of lightning protection for Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai as part of National Electrical Safety Week celebration. The programme was attended by over 300 participants of HPCL. The programme was conducted on ZOOM platform for employees different offices of HPCL.

An awareness programme on basics of lightning protection for Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai

❖ ORGANIZATION STUDY FOR INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL):

HRM & CoE group, functioning from NPC headquarters, carried out an HR study titled 'Organization Restructuring and HR Policy review' for Indraprastha Gas Limited (IGL),a Gas Distribution company.

The purpose of the study was to suggest and recommend an efficient and effective organization structure for optimal utilization of human resource with appropriate HR Policies related to recruitment, promotion, performance management, training and transfer & job rotation. The study aimed at to determine the critical positions and requirement of skills to fill the positions according to qualifications/ experience etc. alongwith review of functioning of each department and job description for all unique roles.

❖ ORGANIZATION STUDY& RECRUITMENT FOR INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT):

IIFT was established in 1963 as an autonomous body under the Ministry of Commerce & Industry to contribute in the skill building for the external trade sector of India. Over the years, IIFT has emerged as a national university with focus on International Business Management and Strategy, and such focus is reflected in all three major activities of the Institute: Research, Training and Education.

A study was undertaken by NPC for IIFT to rightsize the institute for the present & future level of operations, suggest a new or improved structure with roles that align well with the organizational strategy, review recruitment rules (RRs) and develop a draft transition plan and budget for the support needed during the transition period.

❖ IMPACT EVALUATION OF BUFFER STOCKING POLICY OF PULSES

The Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution is the nodal agency for consumer protection in the country with a mandate of consumer's advocacy. The Price Stabilization Fund (PSF) Scheme is being implemented by the Department of Consumer Affairs with the objective of stabilizing the prices of pulses. With a view to assess the impact of the above Scheme, the Department of Consumer Affairs has entrusted a study to the National Productivity Council (NPC), New Delhi with the major terms of reference such as review of production, import, export, availability and demand of pulses in the country from 2016-17 to 2019-20,Gap between demand and supply of pulses, concept of buffer stock and buffer norms of pulses-procurement and disposal of buffer stock and operational issues of buffer stocks of pulses procurement, transportation, storages and disposal of pulses

❖ IMPACT EVALUATION OF NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT (NPDD) IN UTTARAKHAND

The Department of Dairying and Animal Husbandry, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India has initiated the National Programme for Dairy Development in February, 2014-15 with the objective of creating and strengthening dairy infrastructure in the country. The basic objective of the scheme is to create and strengthen infrastructure for production of quality milk including cold chain infrastructure and linking the farmers to the consumers. In the state of Uttarakhand, the procurement, processing and marketing of milk and milk products is being carried out by the Uttarakhand Cooperative Dairy Federations (UCDF) through its District Cooperative Milk Unions. Uttarakhand Cooperative Dairy Federation is the State Implementing Agency (SIA) and District Milk Unions (DMUs) are the End Implementing Agencies (EIAs) of the NPDD Scheme . A study on Impact Evaluation of National Programme for Dairy Development (NPDD) in Uttarakhand was conducted NPC. Five districts namely Nainital, Dehradun, Haridwar, Pithoragarh, and U.S. Nagar were covered under the study. Further in these selected districts 5 District Milk Unions, 5 Dairy Plants, 2 Bulk Milk Coolers, 38 Dairy Cooperative Societies and 230 Producer members have been covered.

❖ SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF AGRO TECHNOLOGIES OF WILD MARIGOLD DEVELOPED BY CSIR-IHBT

CSIR-IHBT has standardized agro-processing technologies and released an improved variety named 'Himgold' on the occasion of National Science Day in 2001 and made available the technologies for cultivation and processing to a large number of farmers for commercial use. With propagation of the technology for more than 15 years; CSIR-IHBT intended to evaluate the socio-economic impact of the agro-processing technologies for Wild Marigold (Tagetes minuta) .National Productivity Council (NPC) was entrusted study entitled “Socio-economic impact of the agro technologies for Wild Marigold”. In order to gauge the socio economic impact of the technology , feedback was taken from key stakeholders.

The study was undertaken in four States, namely Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh and Manipur. Total 74 samples from Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, J&K & Manipur covered under the study selected of beneficiaries for the wild marigold technologies of CSIR-IHBT.

❖ **Review of Existing PLBS and Reframing of New Productivity Linked Bonus Scheme (PLBS)**

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) entrusted study to NPC to review/ evaluate the existing Productivity Linked Bonus Scheme for Group 'C' employees along with framing of new PLB scheme. The study was carried out at ESIC Head office, New Delhi, 06 Regional offices like RO-Delhi, RO-Kolkata, RO Vadodara, RO-Chandigarh, RO-Jaipur and RO Chennai, DCBO-Falta (WB), SRO-Noida and Branch office-Noida, ESIC Medical College & Hospital, KK Nagar, Chennai, ESIC Dental College and Hospital, Rohini, Delhi.

❖ **Baseline Survey on Production and Productivity of Inland Fisheries**

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) entrusted study to NPC to review/ evaluate the existing Productivity Linked Bonus Scheme for Group 'C' employees along with framing of new PLB scheme. The study was carried out at ESIC Head office, New Delhi, 06 Regional offices like RO-Delhi, RO-Kolkata.

Fig: *Fish Farming using Sea Cages in Kollam District of Kerela State.*

Fig 2: *Fish Farming in Tank of Maa Shantoshi SHG Maneswar, Arda, Sambalpur/ Odisha*

Rs. 20,050 crore .The GoI has notified NPC as an End Implementing Agency (EIA) of the PMMSY for a period of 5 years from FY 2020-21 to FY 2024-25.

A study on "Baseline survey on Production and Productivity of Inland Fisheries in India" was awarded to NPC.The study has been conducted in 18 major fish producing States viz: Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Ladakh, J & K, Tamil Nadu and Telangana.The study has covered 1000 fish farmers.

❖ **Physical Inspection of Warehouses for WDRA under WDRA Act.**

NPC RD Hyderabad carried out the inspections of Warehouses of Food Corporation of India, State Warehousing Corporation and Private Entities in the states of Andhra Pradesh and Telangana and inspection reports prepared and submitted to WDRA, New Delhi

NPC team with Manager and Staff of State Warehousing Corporation –Warehouse, Warangal, Telangana State

❖ **Inspection of Private Secure Printers for renewal of licence of IBA empanelment**

NPC RD Hyderabad carried out the inspections of allotted Private Secure Printers in the states of Andhra Pradesh and Telangana and inspection report submitted to IBA, Mumbai.

❖ **Project Monitoring Agency (PMA) of MIIUS Scheme for DPIIT, Govt. of India**

For MIIUS Scheme, executing responsibility as PMA, NPC RD Hyderabad in coordination NPC HQ ECA Group has carried out the field visit of Pashamylaram Industrial Area, Medak District. The scheme is sanctioned with a total project value of Rs. 104.24 crores with central grant being Rs. 25.76 crores to the Telangana State where in TSIIC is designated as SIA.

NPC team with TSIIC officials and Stakeholders at the MIIUS project works located in the Pashamylaram Industrial Area, Medak District, Telangana State.

❖ **Base Line Survey on Production and Productivity of Inland Fisheries for Department of Fisheries, Govt. of India**

For the project titled "Base Line Survey on Production and Productivity of Inland Fisheries", NPC RD Hyderabad was entrusted with the task of carrying out field study in the States of Andhra Pradesh and Telangana covering a total of 25 nos. of districts respectively.

NPC team with District officials and workmen at the fingerling ponds (production units) located in the premises of O/o District Fishery Officer, Anantapuram District, Andhra Pradesh State.

❖ **Implementation and certification of 5S system at Business Units of GMR Group [GMR Hyderabad International Airport, GMR Hyderabad Air Cargo and GMR Hyderabad Airport Expansion Project.]**

As part of the Pan-India team of 5S, RD Hyderabad is involved in the implementation and certification of 5S system for the GMR Group business units located at Hyderabad. Accordingly, team members from RD Hyderabad are involved and successfully provided the consulting services for implementation of 5S in as per the scheduled programmes.

❖ **NCE Examination for Energy Managers/ Energy Auditors, on behalf of BEE, Govt. of India.**

As Centre Superintendent & Nodal Officer Mr. V. Sanjanna, Dy. Director from NPC RD Hyderabad, has successfully conducted the EM/EA examination for BEE at Nagpur Centre in the State of Maharastra as part of the all-India examination schedule.

Examination centre

❖ THIRD PARTY EVALUATION OF CENTRAL SECTORSCHEMES: PACKAGE II 2013 & IDS 2017

National Productivity Council (NPC) was entrusted to carry outstudies the Third-Party EvaluationStudy of two Schemes by DPIIT. First Scheme "Central Sector Schemes Package II (2013) for J & K (Capital investment Subsidy, Central Interest Subsidy and Comprehensive Insurance Subsidy) and for Himachal Pradesh & Uttarakhand (Capital Investment Subsidy)" and Second Scheme "Industrial Development Scheme for UT of J&K and UT of Ladakh-2017 (IDS-2017 for J&K and Ladakh) for the States of Himachal Pradesh & Uttrakhand-2017(IDS-2017 for H.P. & Uttarakhand)".NPC study team submitted both the Reports based on the analysis of the secondary dataand detailed field level interviews with the help of structured questionnaires and schedules of Beneficiary and Non-Beneficiary Units, Disbursing Agencies, State Directorate of Industries, Districts Industrial Centersand Industry Associations in various districts in UT of J&K and UT of Ladakh and States of Himachal Pradesh & Uttarakhand.

❖ INTEGRATED DEVELOPMENT OF NEW ECO TOURISM UNDER SWADESH DARSHAN NORTH EAST CIRCUIT AT THENZAWL & SOUTH ZOTE, DISTRICT SERCHHIP AND REIEK, MIZORAM

National Productivity Council (NPC) was entrusted to carry outthe Study by Ministry of Tourism. TheProject under the Swadesh Darshan Scheme North East Circuit for the "Integrated Development of Thenzawl& South Zote, District SerchhipandReiek". has already been completed and has been inaugurated in December 2019, Ministry of Tourism, would like to prepare a future roadmap for the Project with a view to achieve overall development of the region, employment generation, increase in tourist footfall, development of tourism infrastructure, unshackle future potential of tourism in the region, etc.The Project was sanctioned under the Integrated Development of New Eco Tourism under Swadesh Darshan - Northeast Circuitat Thenzawl & South Zote, District - Serchhip and Reiek, Mizoram with a sanctioned amount of Rs.92.25 Crore out of which an amount of Rs.64.48 Crore was sanctioned for various components at Thenzawl including the Golf Course.NPC study team undertook detailed field surveys with structured questionnaires with Ministry of Tourism, Golf Event Organizer, Hotel/Restaurant/Home Stay, Village Councils/Local Associations etc., andalso undertook the secondary data analysis.

❖ IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2018 (ANNUAL): PARTNER INSTITUTE FROM INDIA

Economic Services Group of NPC has been serving as Partner from India in the publication of World Competitiveness Yearbook for the last several years. WCY 2021 was brought out by the International Institute for Management Development (IMD) Lausanne, Switzerland with the support of partners from various countries. The association with IMD Switzerland has been continuing for more than one and a half decade. Partnership with IMD Switzerland started in 2000 and this association is still continuing. WCY 2021 reports the Competitiveness ranking of 64 economies in the world and the Competitiveness has been estimated for more than 300 (hard (published) and soft (survey)) data variables. Latest edition of the World Competitiveness Yearbook is for the year 2021 which provides ranking of India among 64 economies in the world based on Executive opinion surveys and secondary data (for the last five years) estimations for more than 300 parameters as per the survey format. India maintained 43rd rank on the annual World Competitiveness Index IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021.

❖ **Study on Operation & Maintenance Processes' of Kochi Metro Rail Limited**

- Completed the Assignment titled 'Conducting Study on Operation & Maintenance Processes' of Kochi Metro Rail Limited, located at Kochi. This was a challenging assignment carried out by RD Bangalore. Commenced in August 2020, the field study and the data compilation was carried out during the covid 19 pandemic and adhering to all the covid 19 restrictions and protocols.

- A study for cogeneration certification of captive power plant at MCF Limited, Mangalore was carried out during the covid 19 lockdowns in 2021-22.
- Assignment titled 'Job Analysis and Stratification' at Bosch Limited plants located in Karnataka, Maharashtra, Rajasthan and Tamilnadu, was carried out successfully during this year. Usually in job evaluation, the various activities performed by the individual are rated and the worth of the job calculated. In this case the activity was rated and the worth and position of the activity in comparison to others was tabulated. This was a first of the kind exercise for both the client and NPC. With detailed discussions and presentations to all the stakeholders in the 4 plants, the NPC team completed the assignment fulfilling the requirements of the client organization.
- An assignment titled 'Manpower Assessment Study' at M.S. Ramaiah Hospitals, being the first of the kind study both for the client organization and NPC was carried out to the satisfaction of the client organization. The study recommendations were well appreciated by the client organization.
- Assignment titled 'Conducting Fire Safety Audit', at South Western Railway's coaching depot located at KSR Railway Station, Bangalore, was carried out to the satisfaction of the client organization.

❖ **Evaluation Study of 8 Technical Institutions of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India**

National Productivity Council (NPC) was awarded work for “Evaluation Study of 8 Technical Institutions” by Development Commissioner- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India. The evaluation was conducted in following 8 autonomous institutions:

- Process and Product Development Centre (PPDC), Agra
- Process cum Product Development Centre (PPDC), Meerut
- Central Footwear Training Institute (CFTI), Agra
- Central Footwear Training Institute (CFTI), Agra

- Centre for the Development of Glass Industry (CDGI), Firozabad
- Fragrance & Flavor Development Centre (FFDC), Kannauj
- Electronics Services & Training Centre (ESTC), Ramnagar
- Institute for Design of Electrical Measuring Instruments (IDEMI), Mumbai

Under the study NPC has reviewed the institution's objectives, achievements and impact on the beneficiaries in last 5 years. The study comprises of collection of primary (through questionnaire survey) & secondary data and conducting stakeholders meetings. The site visits were also conducted to review their existing infrastructure and their current activities. The data collected from various sources were analysed, interpreted and evaluation report was prepared. The report also highlights the necessity of monitoring the financial ratios for utilizing the resources. The report was accepted by the client and the findings and suggestions of the evaluation report was helpful for integrating the future technologies requirements so that the institutions can become champion in their respective sector.

❖ Demonstration Project for Capacity Building & Handholding Support to Health Care Facilities (HCFs) for quality improvement in India"

National Productivity Council (NPC) and National Health Authority (NHA) under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India has taken initiative for the "Demonstration Project for Capacity Building & Handholding Support to Health Care Facilities (HCFs) for quality improvement in India". Under the project, funding support has been provided by Asian Productivity Organization (APO), Tokyo, Japan. This project is being implemented in 9 healthcare facilities/hospitals/medical institutes under central/ state government are supported by NPC empanelled service providers/agencies having vast experience in quality management systems. The NPC service providers/agencies assisting 9 HCFs in gap assessment, capacity building programme, preparing necessary documentation towards developing quality management system, as well as guiding and assisting the hospitals towards achieving entry-level certification of Quality Council of India (QCI) - National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH). The hospitals after handholding support provided through NPC would be in position for meeting the accreditation standard requirements and able to apply for QCI/NABH entry level certification which will ultimately benefit to the patients by having quality health care services.

❖ Random Verification of annual Inventory on Hazardous Waste Management

Central Pollution Control Board has engaged National Productivity Council (NPC) for auditing random inspections of the industries in Delhi/NCR region. The auditing exercise consist of inspecting the waste inventory, statutory approvals documentation, reviewing the production process, hazardous waste storage area and the controls put towards the management of hazardous waste by the industrial units. The audit reports of 11 industrial units were submitted to CPCB along with the suitable suggestions and recommendation for improvising hazardous waste management.

❖ Third Party Environmental Audit of TSDF at Nalagarh, Solan, H.P.

NPC has carried out Third Party Environmental Audit of Treatment, Storage and Disposal Facility (TS DF) site at Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh operated by M/s Shivalik Solid Waste Management Ltd. Under the study NPC has supervised the collection of Ground Water, Soil, Ambient Air and Stack Emission representative samples from the site and the nearby locations. The various environmental compliances, record and documentation were verified. Further the data was analysed, interpreted and report was prepared and submitted to client.

❖ Engagement of Young Professional in DPIIT

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India has assigned the work to NPC for assisting and facilitating the department in engaging Young Professionals. About 224 candidates applications were received for the post of Young Professionals and out of which only 183 candidates were shortlisted and appeared in the final interview.

❖ Comprehensive Environment Audit of TSDF BEIL

NPC completed the Comprehensive Environment Audit of TSDF (Treatment, storage and disposal facility) , BEIL located at Ankalehshwar Gujarat. This TSDF id is pioneer in waste management and is one of the largest in India for management of hazardous waste. It substantially contributes to the hazardous waste management in Gujarat caters to the industries located in Ankleshwar, Panoli, Jhagadia etc. districts of Gujarat. TSDF, BEIL has 688 member industries for secured landfill facility and 719 members for common incineration system.

❖ Consultancy services of setting up CBWTFs in Delhi, DPCC

NPC completed the assignment of Consultancy services of setting up CBWTFs in Delhi, under which NPC had undertaken the activities of : Gap analysis of requirement of numbers and capacities of additional CBWTF IN Delhi; Estimation of waste generation factor from health care establishments; Study of successful BMW management in 3 states to study BMW management system and pattern of establishment of CBWTFs; Estimation of cost of CBWTF; Financial modeling for various combinations of capacities and treatment technologies; Assessment of existing operational CBWTFs in Delhi; Analysis of future demand of Bio medical waste generation and corresponding requirement of CBWTF and finally come out with best existing BMW management scenario which may be applicable for Delhi

Online Session

❖ Development of 3 Tier Monitoring mechanisms for Environmental compliance

Ministry of climate Forests and climate change (MoEF&CC) has assigned NPC to develop 3 tier monitoring mechanism for post Environment compliance monitoring. Under this national flagship project, NPC along with its implementing partner NEERI, QCI and GIZ is involved in the following:

- Development of SOPs and templates
- Development of Certified Environment Auditors scheme
- Development of web portals and knowledge products
- Undertake capacity building need assessment for MoEF&CC, CPCB and SPCB
- Assessment of Legacy EC data PAN India and its subsequent sector wise classification

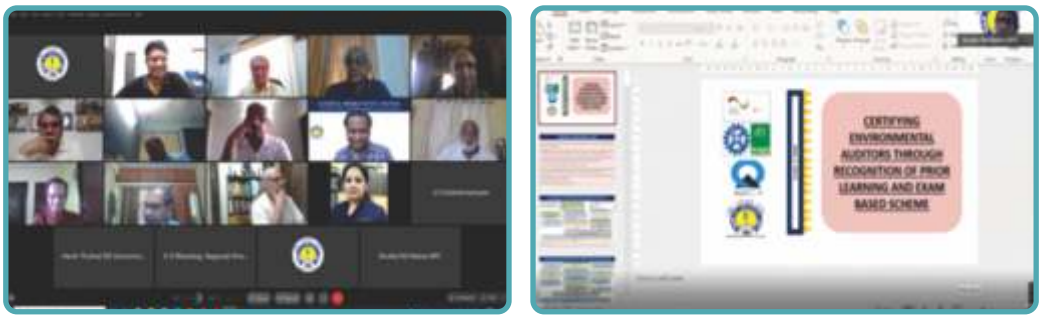

❖ Evaluation & Impact Assessment of Modified Special Incentives Package Scheme (M-SIPS)

The project “Evaluation and Impact Assessment of Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS)”, has been awarded to Environment & Climate Action Group, NPC, by the Ministry of Electronics and Information Technology. The scheme launched in year 2012 has been strengthened with evolving guidelines to address development of ESDM sector, and in essence to engage with 44 sectors / verticals enumerated as part of the Scheme coverage envisaged, via facilitation of enhancement of competitiveness in participating units, attracting investments, as well as providing CAPEX subsidy (20% CAPEX subsidy for units in SEZ areas and 25% for units in Non SEZ areas). The incentives disbursements of over Rs. 1189 Crores has been spread across units under sub-sectors such as automotive electronics, IT & Telecom, Mobile & Accessories, Consumer appliances, industrial electronics, solar, PCB, LED, strategic electronics etc. The evaluation highlighted market scenario and baseline trends, exports and imports of nature of products/raw materials etc and about sales features of participating units, employment generation aspects per Crore of investments, sectoral and regional features of investments by the firms etc. In addition the study delved into micro and macro aspects of the scheme and it's responsiveness, the

- process of applicant approvals and pace of incentives disbursements, documentation requirements and scope for optimization, along with reflecting industry and stakeholder expectations and issues and constraints faced, and also presented perspectives of participating units on Ease of Doing Business, financial ratios, uptake about indigenous technologies etc., and recommended additional scope and range of improvements to consider ahead by the Ministry in the context of the immense significance of the sector and the scheme.

Field visits to Industrial Units in Electronics sector in NCR

- **5"S" Certification of Industries**

For practicing &sustaining high quality housekeeping, waste control and safe operation, 5"S" is used as a tool by industries. To motivate and recognize Excellence in '5S' implementation,NPC offers Certification for visibly demonstrating progress. RD Bhubaneswar conducted certification audits and surveillance audit services to industries adopting the certification scheme.

NPC Team with GMR Kamalanga Energy Team during 5"S" Surveillance Audit

❖ *Feasibility Study and Preparation of Detailed Project Report for Establishment Of Mega CFCs at Mumbai and Surat*

The Gem and Jewelry Export Promotion Council (GJEPC) under the Ministry of Commerce and Industry has entrusted The National Productivity Council, Gandhinagar office a Project to "Conduct Feasibility Study and prepare the Detailed Project Report (DPR) with respect to the establishment of mega Common Facilitation Centers (CFC's) at Mumbai and Surat". NPC has earlier submitted the report for Phase I of the Project, that is, "Feasibility Study to assess the need and requirements for mega CFC at Surat and Mumbai". The Phase I report submitted by NPC was accepted by GJEPC.

The NPC Phase I study concludes that there is a need for Mega CFC in Surat and Mumbai regions and that the mega CFCs are feasible and commercially viable at Surat and Mumbai locations alongside other recommendations. NPC has also submitted the "Detailed Project Report for Mega CFC at Mumbai" as part of Phase II of the Project. The GJEPC has accepted the report. The mega Common Facility Center is essentially a place where, in a single center, the best of the 3T's (Technology, Techniques & Training) from around the world will be made available. The objective of the mega CFC is to give equal opportunity to all companies from the smallest to the largest to avail the 3 T's, in a very affordable and efficient way.

❖ *Performance Evaluation of Air Pollution Control Devices at Leading Tire Company*

The NPC, Gandhinagar office has undertaken a study on "Performance Evaluation of Air Pollution Control Equipment" in a leading tire company. NPC has carried out field study and undertaken emission monitoring of various Air Pollution Control Devices to ascertain their Performance. The monitoring results were compared with the emission discharge standards and reported upon. The evaluation study by NPC has helped the company identify their actual emission status/scenario and comply with the conditions of grant of Environmental Clearance.

❖ *Random Verification of Annual Inventory on Hazardous Waste Management*

The Central Pollution Control Board (CPCB) has awarded NPC, Gandhinagar office the project on "Random Verification of Annual Inventory on Hazardous Waste Management". As part of the project NPC, Gandhinagar officials have undertaken joint visit to Companies located in Gujarat and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli regions along with CPCB and GPCB officials, to study the Hazardous Waste Management practices adopted by these companies and respective reports along with recommendations for improvement in Hazardous Waste Management has been submitted to CPCB.

❖ ***"Energy and Resource Mapping of MSME Clusters in India" for Pharma Sector in Ahmedabad***

NPC Gandhinagar undertook the Energy & resource mapping study under the project sponsored by Bureau of energy efficiency, New Delhi In phase-I of the project NPC has surveyed the MSME Pharma units in the Ahmedabad region through a detailed data collection questionnaire. As per the survey outcome the Ahmedabad Pharmaceutical cluster comes out to be a formulation cluster. In phase - II, 10 units were selected for detailed energy audit profiling. The selected units represent variable pharma sector profiles having 5 Medium, 3 Small, and 2 Micro units engaged in different product formulations. The technical studies were conducted by NPC to identify energy conservation for operational cost reduction in both electrical and thermal utilities in the units. A dissemination workshop was later organized at Ahmedabad with support from the Bureau of Energy Efficiency, Indian Drug Manufacturers association- Gujarat state board on 17 September 2021 with the active participation of MSME pharma units from Gujarat region. The energy audit study has identified 14 interventions that can be readily implemented by any pharma unit to gain the benefit of energy saving in operations.

❖ ***Restructured Accelerated Power Development and Reforms Program (R-APDRP) Project***

National Productivity Council, RD Gandhinagar appointed as Third-Party Independent Evaluating Agency for the state of Gujarat by Power Finance Corporation, Ministry of Power, Government of India. NPC RD Gandhinagar had done the study for all four DISCOMs in the state of Gujarat. NPC has established The Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses for 84 towns of the project areas covering all the state of Gujarat. NPC has computed the losses for the entire utility for all four DISCOMs separately for the period of five years. Further NPC has done the verification of annual AT&C losses of the project areas i.e. 64 towns covered under the project in TOR2. The main aim of the RAPDRP project is to reduce AT&C losses of all the 84 towns of Gujarat covered under this project with focus on actual, demonstrable performance in terms of sustained loss reduction.

❖ ***Water Audits of Industries in the State of Gujarat***

National Productivity Council appointed as certified auditors by Central Ground Water Authority (CGWA) Ministry of Jal Shakti, Government of India to conduct the water audit of all industries abstracting groundwater in excess of 100 m3 per day. NPC, RD Gandhinagar has conducted more than 50 water audits in different types of industries in Gujarat and all the industries get benefited by large potential of water savings that can be achieved by water harvesting, through the recycling of water and the use of rainwater. These water audit studies provide a way to inventory all water uses in industry facilities and identify ways to increase water use efficiency which leads to reduced water losses.

❖ Formulation of Schedule of Rates (SOR) for Central Coalfields Ltd Ranchi

Central Coalfields Ltd Ranchi are outsourcing the work of extracting and transporting coal in their open Cast Projects. This requires determining the realistic cost of various operations which would form a basis for awarding the contract to outsourcing private agencies.

NPC prepares a document consisting of Schedule of Rates for various jobs of mining and transportation of OB & coal. This document facilitates coal subsidiaries to float tenders at optimum costs for bidders. Formulation of Schedule of rates for various activities helps the coal subsidiaries in reducing the overall cost of execution of works. Since such work entails huge volumes of extraction and transportation of OB and coal, the coal subsidiaries are able to achieve substantial cost reduction for these operations. This study also helps in measuring and improving productivity viz. the fleet size of various HEMMs, equipment utilisation, the throughput rate, direct and indirect manpower, energy usage etc also. Study helps measuring and improving productivity viz. the fleet size of various HEMMs, equipment utilisation, the throughput rate, direct and indirect manpower, energy usage etc also.

Payloader at work in Open Cast Project

Cutting of coal with Surface Miner

❖ State Level studies on hazardous and other wastes generating industries/units Inventorization in all districts of Tripura

A State level project on Hazardous and other waste generating Industries/units Inventorization studies in all districts of Tripura state was conducted by National Productivity Council, Regional Directorate, Kolkata. The project was awarded by Tripura State Pollution Control Board (TSPCB). The studies include field level visits in the Tripura state, analysis of Hazardous and other waste samples, Identification of Hazardous and other wastes contaminating sites and development of Hazardous waste generation factor based on the type of waste. Based on the field visits, hazardous waste generating units operating in the state and total generation of hazardous waste were estimated during the course of inventorization exercise. Also, it was proposed to set up a Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDFs) in the state for non-recyclable, non-utilizable hazardous waste either for landfilling in secured landfill or incineration, since the state of Tripura does not have a Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) for non-recyclable, non-utilizable hazardous waste. This would further strengthen the waste disposal options in the North-Eastern Region. Biharenergy usage etc also.

Report presentation by NPC at TSPCB Office

❖ **External Safety Audit as per IS:14489 conducted at Texmaco Rail & Engineering Ltd., West Bengal**

National Productivity Council, Kolkata conducted an External Safety Audit as per IS 14489 at M/s Texmaco Rail & Engineering Ltd., West Bengal.

The basic objective of the Audit was to determine ways to improve upon the entire safety quotient of the various units of the organization.

Walkthrough inspection as per all relevant IS codes & rules such as Factories act and rules; Indian Electricity rules etc. was conducted stressing on various facets of safety including electrical, chemical etc. Thermography based on all available electrical facilities such as HT/LT substation, panel rooms, DB's etc. was conducted.

The recommendations were very well received & the feedback of the top management was very positive

❖ **Conducting Research Study for the Startups of the North Eastern Region**

This study titled “Research Study for the Startups of NER” was entrusted to NPC by o/o DC MSME, Ministry of Micro, Small, & Medium Enterprises, GoI. The key objectives of the study were to develop the baseline status of the Startups of NER and Sikkim, documentation of national and international best policy/practices/initiatives that best suit the need of the startup ecosystem of the NER.

Various aspects of the startups ecosystem of the NER have been assessed in the study. Primary data has been collected through field survey in all the eight states of the region namely Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim and covering various stakeholders of the study like Startups, Incubators, Mentors, Investor and, States department engaged in implementation of Startup initiative. Startup ecosystems of Maharashtra and Kerala have also been covered for documentation of best practices, policies and initiatives that suit the Startup ecosystem of the NER. Further, documentation of Startup ecosystem of Israel, South Korea, Thailand and Taiwan have been covered and their initiatives have been segregated based on the need of the Startups ecosystem of the NER.

❖ **Capacity Building of State/UTs for data on domestic & Foreign Tourist Visits/Visitors, Ministry of Tourism, Govt. of India**

Ministry of Tourism has engaged National Productivity Council as a project Management Unit (PMU) for building the capacity of the State/UT tourism departments for estimation of the Domestic & foreign Tourist visitors and visits in their State/UT.

A dashboard is being developed for dissemination ofdistrict wise Tourism Development Indicators such as Tourist visits, room occupancy, employment, foreign exchange earnings, International Tourist Arrivals, Indian National departures. The dashboard would provide a mechanism to State Tourism departments to monitor the Tourism indicators of their states and plan their policies and initiatives in right direction.

❖ Online Training Program on "Issues related to public procurement/GeM & contract management/ Arbitration in CPSE's

Online Training Program on "Issues related to public procurement/GeM & contract management/ Arbitration in CPSE's" from 6th December 2021- 10th December 2021 which was sponsored by: Department of Public Enterprises, M/o Finance, Govt of India was conducted. The program was attended by officers of Central/State PSU's and was well appreciated by them.

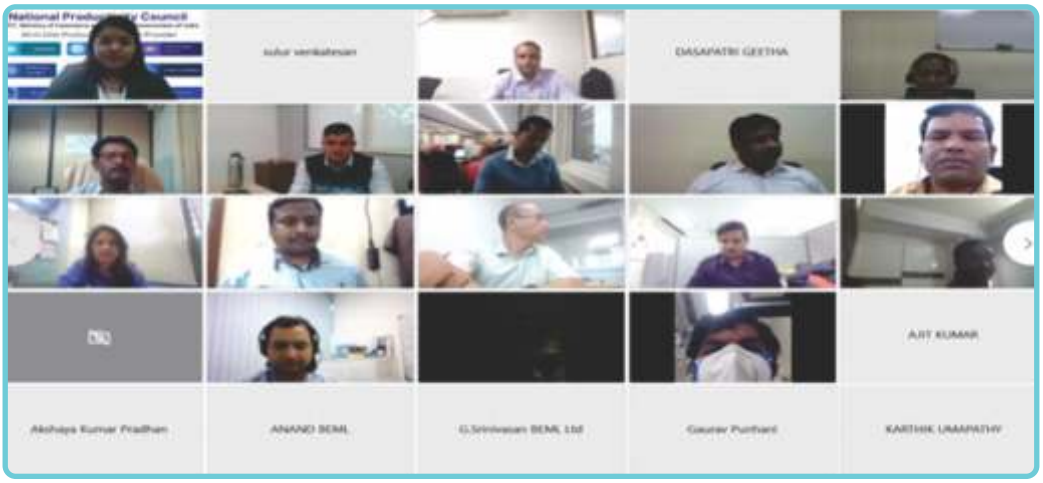

❖ Training programme on Lean Management & Six Sigma

NPC Group Conducted 2 days Onsite training programmes on Lean Management & Six Sigma for employees of Hamdard Laboratories, Manesar Plant.

❖ Inspection division of NPC conducted webinar titled FSSAI (Labelling and Display Regulations), 2020 on 11.06.2021 in which 698 paid participants registered for the webinar. Major Webinar Participants include Mother Dairy Fruits and Vegetables Pvt. Ltd., Banas Dairy (AMUL), Dudhmansagar Dairy (AMUL), GHCL (formerly Gujarat Heavy Chemicals), Sun Pharmaceuticals Vadodra, Hamdard, Kancor Ingredients Limited, Bisleri International Pvt.Ltd., Parag Milk Foods Ltd., Dabur India Limited, Kannan Devan Tea Plantation, Munnar, Sonipat Sugars, Haldiram, etc.

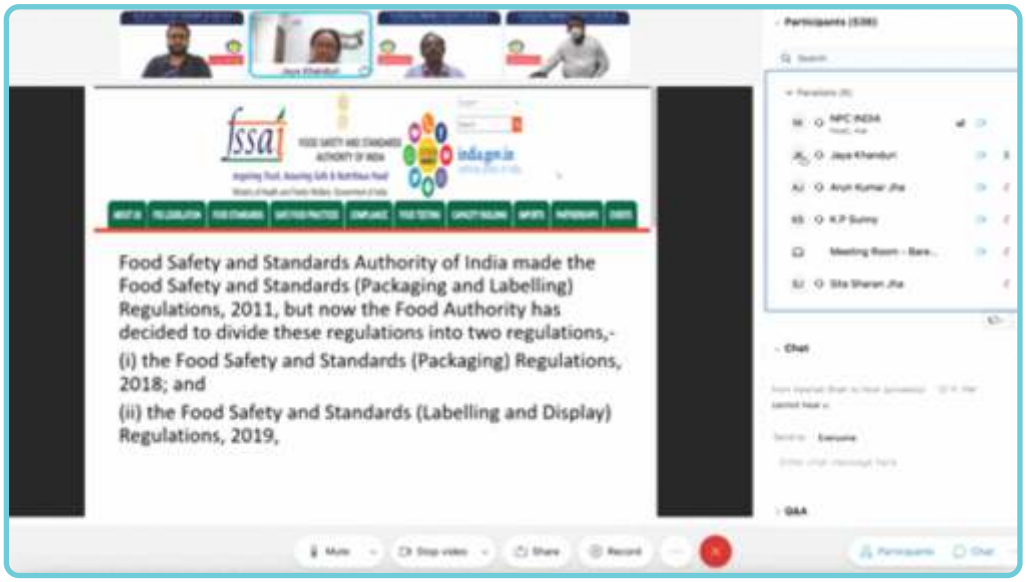

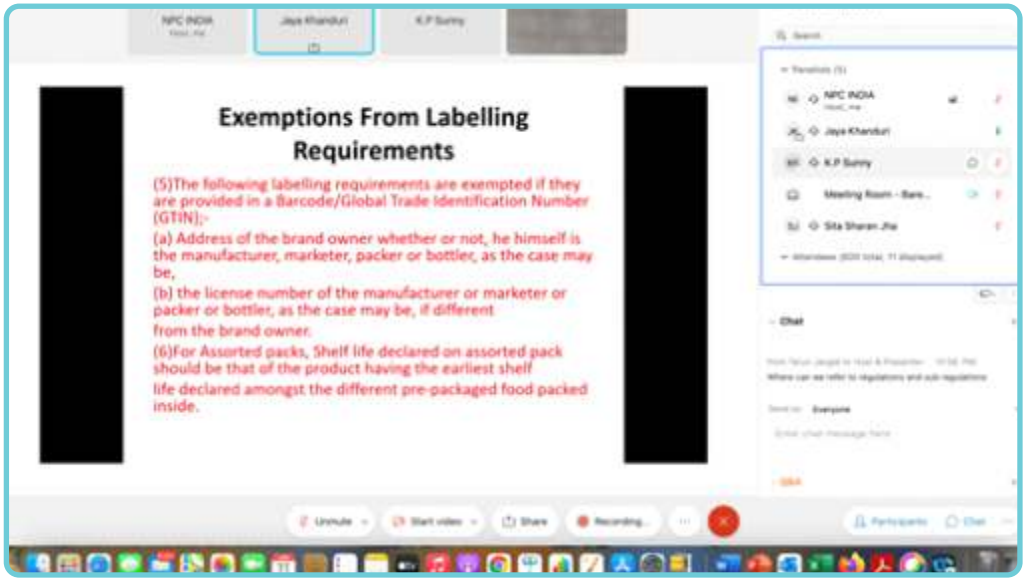

❖ NPC Inspects 147 FCI Depots under WDRA across the country

NPC has been empanelled with Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) as the Inspection Agency for undertaking Inspections of Warehouses as per WDRA Rules, 2017. Inspection Division of NPC has undertaken Inspection work of 147 FCI Depots under WDRA spread across different parts of India during August- November 2021.

Guwahati team carried out a Water Audit Studies for different clients as per CGWA guidelines & norms. These studies highlighted water conservation opportunities for the units and compliance status as per CGWA norms. Some pictures of field study for water audits are as under:

Pic. 1 Field photograph - Water audit study

Pic. 2 Field photograph - Water audit study

Pic. 3 Field photograph - Water audit study

Pic. 4 Field Photograph - Water audit study

Pic. 5 Field photograph - Water audit study

Pic. 6 Group Photograph- residential training program on Cyber Security

❖ **"Research Study for the Startups of NER" was entrusted to NPC by o/o DC MSME, Ministry of Micro, Small, & Medium Enterprises, GoI. The key objectives of the study were to develop the baseline status of the Startups of NER**

Various aspects of the start-ups ecosystem of the NER have been assessed in the study. Primary data has been collected through field survey in all the eight states of the region namely Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim and covering various stakeholders of the study like Startups, Incubators, Mentors, Investor and, States department engaged in implementation of Startup initiative. Startup ecosystems of Maharashtra and Kerala have also been covered for documentation of best practices, policies and initiatives that suit the Startup ecosystem of the NER. Further, documentation of Startup ecosystem of Israel, South Korea, Thailand and Taiwan have been covered and their initiatives have been segregated based on the need of the Startups ecosystem of the NER.

Study findings point the scope of improvement in some of the key areas of Startup ecosystem of NER such as development of knowledge centres, development of a dedicated cluster system for implementation of startups initiatives in the NER, interlinking of various national and international institutions for transfer and sharing of knowledge and technology, more focus on capacity building of various stakeholders of the startup ecosystem and, to contain the brain drain and retaining of talented youngsters in the region.

❖ **Capacity Building of State/UTs for data on domestic & Foreign Tourist Visits/Visitors, Ministry of Tourism, Govt. of India**

Ministry of Tourism has engaged National Productivity Council as a project Management Unit (PMU) for building the capacity of the State/UT tourism departments for estimation of the Domestic & foreign Tourist visitors and visits in their State/UT.

A dashboard is being developed for dissemination ofdistrict wise Tourism Development Indicators such as Tourist visits, room occupancy, employment, foreign exchange earnings, International Tourist Arrivals, Indian National departures. The dashboard would provide a mechanism to State Tourism departments to monitor the Tourism indicators of their states and plan their policies and initiatives in right direction.

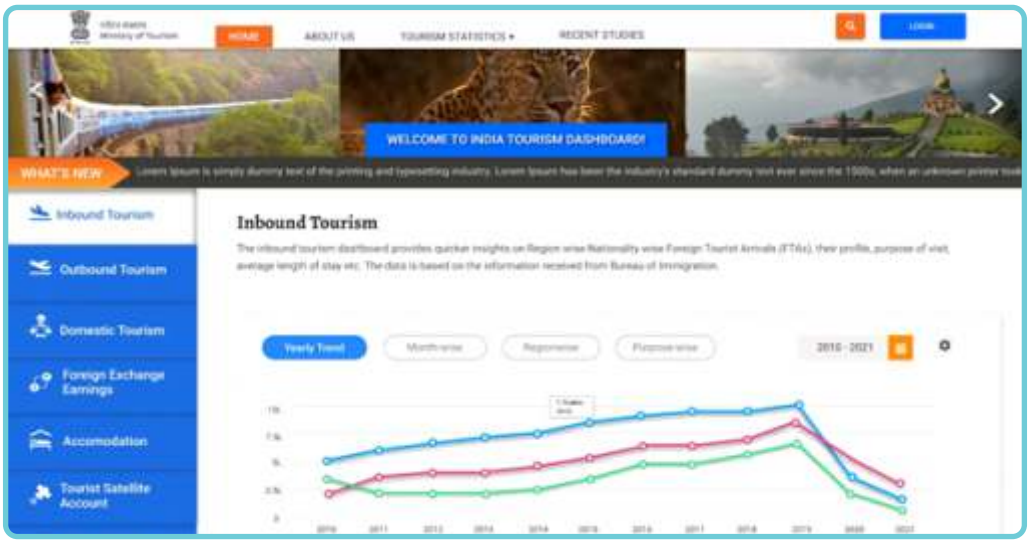

❖ Energy Audit

RD Bhubaneswar conducted 11 number of Energy Audits in sectors such as Commercial Buildings, Hospitals, Thermal Power Stations, and Pumping Stations. The Studies aimed at performance evaluation of energy using utilities and bringing out energy conservation opportunities.

❖ Detailed Energy & Water Audit at Diamond Beverages Pvt. Ltd., Kolkata

National Productivity Council, Kolkata conducted a Detailed Energy & Water Audit at M/s Diamond Beverages Pvt. Ltd., Kolkata.

The management of M/s Diamond Beverages Pvt. Ltd., Kolkata approached NPC Kolkata with the intent to audit its entire Energy & Water consumption of its manufacturing facility & bottling plant and the scope of the study included both the Specific Energy & Water Consumption assessment using Gate to Gate approach.

In the energy audit, entire electrical distribution system including transformers, circuit breakers, prevailing harmonics in the system etc. was analyzed with special emphasis on existing HVAC system, motors, insulation system etc. The recommendations and energy/water saving measures being both feasible & practical was very well received & the feedback of the management was very positive.

Report Findings presentation& Field Audit Snapshots by NPC at Diamond Beverages, Kolkata

❖ **Energy Audit Study was conducted at M/s SRI KVS INDUSTRIES under ICRO project of Indian Potash Limited and energy conservation measures were recommended as part of IPL CSR Activity**

❖ **<u>Mandatory Energy Audit at Rajashree Cement Works, Karnataka</u>**

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Mandatory Energy Audit at "RajashreeCement Works, Ultratech Cement Limited, Malkhed, Gulbarg, Karnataka" with an objective to as certain performance of various processe quipment / systems and find out the opportunities for energy conservation. The audith as been in stated by the plant to meet mandatory energy audit requirement under EC Act-2001.The audit team has carried out the study in Cement Plant and as well as Integrated Thermal Power Plant. In Cement Plant study focused on various process systems such as Preheater, Kiln, Cooler, Raw Mill, Coal Mill, Cement Mills and utilities.

The energy audit study has identified savings in terms of thermal savings of 47.47 kCal/kg clinker thus results in 20,076 Tons of Coal, whereas in terms of Electrical 18.64Million Units. On an overall this energy audit has identified savings of Rs 22.99Crores.

❖ Mandatory Energy Audit at Kotputli Cement Works, Rajasthan

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Mandatory Energy Audit at "Kotputli Cement Works, Ultra tech Cement Limited, Kotputli, Jaipur, Rajasthan" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation .The audit has been instated by the plant to meet mandatory energy audit requirement under EC Act-2001.The audit team has carried out the study in Cement Plant and as well as Integrated Thermal Power Plant.

The energy audit study has identified savings in terms of thermal savings of 6.88 k Cal/kg clinker thus results in 5,266 Tons of Coal, whereas in terms of Electrical 11.67Million Units. On an overall this energy audit has identified savings of Rs 8.28Crores.

❖ Mandatory Energy Audit at KCP Cements Limited, Andhra Pradesh

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Mandatory Energy Audit at "KCP Cements Limited, Muktyala Unit, Andhra Pradesh" with an objective to

as certain performance of various processe quipment / systems and findout the opportunities for energy conservation.The audit has been instated by the plant to meet mandatory energy audit requirement under EC Act-2001.The audit team has carried out the studyin Cement Plant and as well as Integrated Thermal Power Plant. In Cement Plant study focused on various process systems such as Preheater, Kiln, Cooler, Raw Mill, Coal Mill, Cement Mills and utilities.

The energy audit study has identified savings in terms of thermal savings of 54.3 kCal/kg clinker thus results in 11,124 Tons of Coal, whereas in terms of Electrical 7.38 Million Units. On an overall this energy audit has identified savings of Rs 12.76 Crores.

❖ Energy Audit Study at Granules India Limited, Hyderabad

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Granules India Ltd., Gagilapur, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation .

The energy audit study has identified savings in terms of thermal savings of 54.3 k Cal/kg clinker thus results in 141 Tons of Coal, whereas in terms of Electrical 0.86Million Units. On an overall this energy audit has identified savings of Rs 0.70Crores.

❖ **Energy Audit Study at Aurobindo Pharma Limited Unit-4 (EugiaPharmaSpecialities Ltd Unit-3)**

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Aurobindo Pharma Limited Unit-4 (Eugia Pharma Specialities Ltd Unit-3, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation .The audit has been instated by the plant to meet energy audit requirement under EC Act-2001.

The energy audit study has identified savings in terms of electrical savings of 27.44 Lakh kWh, thermal savings (Coal & Furnace Oil) of 471 Tons with a Monitory savings (Electrical & Thermal) of Rs. 2.25 Crores with an investment of Rs 98.73 Lakhs thereby reducing the CO_2 emission of 2986 tons of Co_2.

❖ **Energy Audit Study at Aurobindo Pharma Limited Unit-3**

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Aurobindo Pharma Limited Unit-3, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation. The audit has been instated by the plant to meet energy audit requirement under EC Act-2001.

The energy audit study has identified savings in terms of electrical savings of 10.62 Lakh kWh, thermal savings (Coal & Furnace Oil) of 138 Tons with a Monitory savings (Electrical & Thermal) of Rs.1.25 Cr with an investment of Rs. 167.7 Lakhs thereby reducing the CO_2 emission of 1182 tons of Co_2.

❖ **Energy Audit Study at Aurobindo Pharma Healthcare Limited Unit-1**

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Aurobindo Pharma Limited Unit-1, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation .The audit has been instated by the plant to meet energy audit requirement under EC Act-2001.

The energy audit study has identified savings in terms of electrical savings of 6.62 Lakh kWh, thermal savings (Coal &Furnace Oil) of 33 Tons with a Monitory savings (Electrical & Thermal) of Rs.58 Lakhs with an investment of Rs.56 Lakhs thereby reducing the CO_2 emission of 710 tonsof CO_2.

❖ Energy Audit Study at Deepak Nitrate Limited Unit-1

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Deepak Nitrate Limited Unit-1, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation. The audit has been instated by the plant to meet energy audit requirement under EC Act-2001.

The energy audit study has identified savings in terms of electrical savings of 2.59 Lakh kWh, thermal savings (Coal & Furnace Oil) of 182.57 Tons with a Monterey savings (Electrical & Thermal) of Rs.30.56 Lakhs with an investment of Rs.31.59 Lakhs thereby reducing the CO_2 emission of 509 tons of CO_2.

❖ Energy Audit Study at Deepak Nitrate Limited Unit-2

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Deepak Nitrate Limited Unit-1, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation .The audit has been instated by the plant to meet energy audit requirement under EC Act-2001.

The energy audit study has identified savings in terms of electrical savings of 7.45 Lakh kWh, thermal savings (Coal & Furnace Oil) of 888.56 Tons with a Monterey savings (Electrical & Thermal) of Rs.395 Lakhs with an investment of Rs.221 Lakhs thereby reducing the CO_2 emission of 3045 tons of CO_2.

❖ Energy Audit Study at Deepak Nitrate Limited Unit-3

National Productivity Council, Hyderabad has conducted Energy Audit Study at "Deepak Nitrate Limited Unit-1, Hyderabad" with an objective to ascertain performance of various process equipment/systems and find out the opportunities for energy conservation.The audit has been instated by the plant to meet energy audit requirement under EC Act-2001.

The energy audit study has identified savings in terms of electrical savings of 1.90 Lakh kWh, thermal savings (Coal &FurnaceOil) of 81.74 Tons witha Monterey savings (Electrical & Thermal) of Rs.17.94 Lakhs with an investment of Rs.14.10 Lakhs thereby reducing the CO_2 emission of 296 tons of CO_2.

❖ Water Audit in Industries

NPC Team Inspecting Borewell Water Flow meter

Regional Directorate Bhubaneswar Conducted about 35 Water Audit studies in different industries belonging to sectors such as Metal, Mining, Chemical, Cement, Food processing etc. The Audit aimed at accounting ground water consumption by different utilities inside the plant/mine and bringing out water conservation potentials. All the water audit studies are conducted inline to guidelines issued by Central Ground Water Authority. This is a partof our Resource Conservation Services.

❖ Detailed Water Audit at Uranium Corporation of India Ltd., Jamshedpur

National Productivity Council, Kolkata conducted a Detailed Water Audit at M/s Uranium Corporation of India Ltd., Bhatin Mines – Jamshedpur.

The management of M/s UCIL approached NPC Kolkata with the intent to audit its entire Water consumption of its Bhatin Mines unit and the scope of the study included the Specific Water Consumption assessment using Gate to Gate approach.

The primary objective of Detailed Water Audit was to determine ways to reduce the total Water consumption. It was the second mine among the seven mines of UCIL (after Narwapahar Mines) located throughout the country to have conducted such an exercise.

The recommendations and Water saving measures being both feasible & practical was very well received & the feedback of the UCIL management was very positive.

Field Audit Snapshots by NPC at Uranium Corporation of India Ltd., Jamshedpur

List of Consultancy Projects undertaken in FY 2021-22	
S. No.	**Name of Consultancy Project**
1	Energy Audit for SBI Administrative Building, BBSR
2	Surveillence Audit of SA 8000 in respect of Six Operative Mines for OMC,BBSR
3	Turbine Performance Study for NTPC-SAIL Power Company Ltd, Rourkela
4	Environment Awareness Training Programme for JSW Cement, Jajpur
5	IGEA Audit Sewerage Treatment Plant at Puri for SDA,Odisha
6	SA 8000 Certification in respect of 3 Mines
7	IGEA Audit At DHH,Phulbani For SDA, Odisha
8	Training Programe on Retirement Plan For NPCIL,Mumbai
9	Organizing Road Show For Promotion of Electric Vehicles For SDA, Odisha
10	Time & Motion Study At Khondalite Mines of OMC, BBSR
11	5-S Certification Audit for Adani Hazira Port Ltd., Surat
12	5-S Certification Audit for Marine Infrastructure Developer Pvt. Ltd., Chennai
13	Third Party Independent Evaluation Agency-RAPDRP for Gujarat region for Power Finance Corporation, New Delhi
14	5-S Certification Audit for Adani Ennore Container Terminal Pvt. Ltd., Chennai
15	5-S Certification Audit for Adanu Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd
16	5-S Certification Audit for PG India Logistics Pvt Ltd., Sanad
17	Manpower Optimization & Restructuring Study for Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd
18	5-S Certification Audit for BASF India Ltd., Bharuch
19	Random verification of annual inventory of hazardous waste management for Central Pollution Control Board, Delhi
20	Training of 64-Safaimitras for Municipal Corporation, Singrauli
21	Preliminary Visit for Time & Motion Study for Adani Wilmar Limited, Ahmedabad
22	5-S Certification Audit for Adama India Pvt Ltd
23	Performance evaluation of pollution control systems including ESP, Bag filters installed in 20 MW CPP for Bal Krishna Industries Ltd, Bhuj
24	Manpower Optimization Study for Adani Wilmar Limited, Ahmadabad
25	5-S Certification Audit for Adani Hazira Port Ltd., Surat
26	5-S Certification Audit for Marine Infrastructure Developer Pvt. Ltd., Chennai
27	5-S Certification Audit for Adani Ennore Container Terminal Pvt. Ltd., Chennai
28	5-S Certification Audit for Adanu Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd
29	5-S Certification Audit for PG India Logistics Pvt Ltd., Sanad

List of Consultancy Projects undertaken in FY 2021-22	
30	Manpower Optimization & Restructuring Study for Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd
31	5-S Certification Audit for BASF India Ltd., Bharuch
32	Random verification of annual inventory of hazardous waste management for Central Pollution Control Board, Delhi
33	Training of 64-Safaimitras for Municipal Corporation, Singrauli
34	Preliminary Visit for Time & Motion Study for Adani Wilmar Limited, Ahmedabad
35	5-S Certification Audit for Adama India Pvt Ltd
36	Performance evaluation of pollution control systems including ESP, Bag filters installed in 20 MW CPP for Bal Krishna Industries Ltd, Bhuj
37	Manpower Optimization Study for Adani Wilmar Limited, Ahmadabad
38	Research study for the Start ups and develop the baseline status of the Start-ups of North Eastern Region
39	The study and analysis of Hazardous and other waste samples, Identification of Hazardous and other wastes contaminating sites and development of Hazardous waste generation factor based on the type of waste
40	A Detailed Energy & Water Audit at M/s Diamond Beverages Pvt. Ltd., Kolkata.
41	Third-Party Evaluation Study of two Schemes "Central Sector Schemes Package II (2013) for J & K (Capital Investment Subsidy, Central Interest Subsidy and Comprehensive Insurance Subsidy) and for Himachal Pradesh & Uttarakhand (Capital Investment Subsidy)" and "Industrial Development Scheme for UT of J&K and UT of Ladakh-2017 (IDS-2017 for J&K and Ladakh) for the States of Himachal Pradesh & Uttrakhand-2017(IDS-2017 for H.P. & Uttarakhand).
42	Study on Operation & Maintenance Processes
43	Study for cogeneration certification of captive power plant at MCF Limited
44	'Manpower Assessment Study' at M.S. Ramaiah Hospitals`
45	Manpower Assessment Study', at Britannia Industries Limited plant
46	Consultancy services of setting up CBWTFs in Delhi, DPCC

List of Training Programs for FY 2021-22	
S. No.	**Name of Program**
1	Training programs for the Department of Public Enterprises, Government of Karnataka
2	Advance training on electrical safety: hazards, safety audit, standards ,electrical safety act, 2003
3	Awareness programme on basics of lightning protection for Hindustan Petroleum Corporation Ltd. as part of National Electrical Safety Week celebration
4	Training Program on 'Energy Efficiency Practitioners Course in Industrial Utilities
5	Training Program on Industrial Environment Management through Techno-Managerial and Policy Issues
6	Energy Efficiency Practitioner's Course in Industrial Utilities
7	Technical Policy Instruments & Frameworks for shifting to Renewable Energy for ITEC
8	Effective Office Administration and Financial Management in Leh, Ladakh
9	Project Management Planning and Monitoring& Evaluation in Gangtok, Sikkim
10	Performance & Financial Management for Organizational Excellence
11	Training programme on Effective Office Administration and Financial Management
12	Online training on Environment management and Energy efficiency for officials of M/s Brookfield properties
13	Training Program on Air Pollution & Air Modelling
14	Training Programon 'How to improve your cities/town's ranking under Swachh Survekshan Ranking'
15	ETP & CETP Operation and Maintenance
16	Adequacy & Efficacy PETP ETP and CETP
17	Oil and Waste Management – HPCL
18	Residential Training Program for CPSEs & SPSEs
19	Residential Training Program for Divyang participants
20	Procurement, GeM, Arbitration and Contract Management sponsored by DPE, Govt of India
21	Self run training program on Administrative Effectiveness, Focus: RTI & Preventive Vigilance at Goa
22	Training Programme on Supply Chain Management
23	Training Programme on Effective Office Secretary
24	Training Programme on Creative Problem Solving
25	Training Programme on Developing Managerial & Supervisory Skills
26	Training Programme on Office Procedure: Noting & Drafting
27	Training Programme on Public Financial Management System
28	Training Programme on Establishment Rule
29	Training Programme on Tendering Process & Contract Management
30	Training Programme on Public Procurement: e-Procurement & GEM
31	Training Programme on Preventive Vigilance
32	Training Programme on Right to Information Act
33	Training Programme on Vigilance & Disciplinary Proceedings
34	Training Programme on General Financial Rule
35	Training program on Lean Management & Six Sigma

List of Webinars and Online Training Programs for FY 2021-22		
S. No.	Name of Program	Type of Program (Webinars/ Online Training Program)
1	Implementation of 50001 :2018 energy management system for improving energy performance	Webinar
2	Industrial safety and industrial safety acts, rules and regulations	Webinar
3	Effective implementation of the energy conservation act, 2001	Webinar
4	Process safety, process safety management and ensuring process safety through ISO HAZOP	Webinar
5	Integrated implementation of ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 and ISO 45001 :2018 standards	Webinar
6	Education 4.0 – digital transformation of education aligning with industry 4.0	Webinar
7	Safety audit, safety audit techniques, planning and conducting a safety audit	Webinar
8	Marketing 4.0 – digital transformation of marketing function aligned with industry 4.0	Webinar
9	Smart manufacturing – digital transformation of manufacturing	Webinar
10	ISO 22000:2018 food safety management system- documentation, implementation and certification	Webinar
11	Manuals preparation to document ISO 45001 :2018 occupational health and safety management system	Webinar
12	Lockout/ tagout (loto) for control of hazardous energy	Webinar
13	ISO 37001:2016 anti-bribery management system - documentation, implementation and certification	Webinar
14	Methods/practices for achieving higher energy efficiency in industry	Webinar
15	Industrial safety , industrial safety acts, rules ,regulations, implementation issues and challenges	Webinar
16	Electrical safety, electrical safety audit, electrical hazards , electrical safety act, 2003 and rules	Webinar
17	How to document Energy Management System for effective implementation of ISO 50001:2018 Standard?	Webinar
18	Fire safety, fire risk assessment, fire safety audit and control of fire hazards	Webinar
19	Smart factory– digital transformation of processes at shop floor	Webinar
20	Documentation requirements of ISO 14001 :2015 standard and preparation of manuals for an environment management system	Webinar
21	Lightning & earthing precautions during heavy wind /stormy weather :lightning /thunderstorm safety	Webinar
22	Advance course on RTI act, 2005 with judgments of CIC/SIC & various high courts & supreme court of India	Webinar
23	First aid, first aid kits and occupational diseases and remedial and preventive measures	Webinar
24	Non-destructive testing (ndt) methods, technologies and their applications in industry	Webinar
25	Energy efficient technologies and their implementation	Webinar
26	Manuals preparation to document quality management system as per ISO -9001:2015 standard	Webinar
27	Manuals preparation to document iso 27001:2013 information security management system	Webinar

List of Webinars and Online Training Programs for FY 2021-22

28	Hazardous chemicals rules, 1989 and latest amendments, material safety data sheet (msds) and its usage	Webinar
29	Six waste management rules,2016	Webinar
30	Manufacturing 4.0 & maintenance 4.0 –use of digital technologies for operational excellence	Webinar
31	Detailed energy audit: objectives, methodology, instruments used, report preparation & presentation	Webinar
32	Personal protective equipment(PPE) : usage, types, kits, proper maintenance, storage & disposal of PPE's	Webinar
33	Manuals preparation to document food safety management system as per ISO 22000:2018 standard	Webinar
34	Maximizing benefits by implementing ISO 45001: 2018 occupational health & safety management system	Webinar
35	Fire safety,control of fire hazards,fire evacuation plan,fire safety audit,control of fire incidents	Webinar
36	Maximizing benefits from implementation of iso 50001: 2018 energy management system	Webinar
37	Plant safety management practices for minimizing hazards, risks, accidents and near misses	Webinar
38	Occupational safety,health& working conditions code,2020, electricity act& hazardous chemical rules	Webinar
39	Vibration analysis for effective preventive and predictive maintenance	Webinar
40	Behavior based safety(BBS): principles ,method, practices & tools to develop good safety behaviour	Webinar
41	Operational excellence through digital technologies under manufacturing 4.0 & quality 4.0	Webinar
42	Advance training on electrical safety: hazards , safety audit, standards ,electrical safety act, 2003	Webinar
43	Energy audit: preliminary & detailed energy audit, methodology, instruments used, conducting an energy audit	Webinar
44	Chemical Safety, Control of Chemical Hazards, MSDS, hazardous chemical rules, 1989, PPE's requirements	Webinar
45	Manual preparation for integrated management system as per ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 & ISO 45001 :2018	Webinar
46	Energy conservation in electrical utilities & electrical system for reducing power & energy demands	Webinar
47	Lightning & thunderstorm safety: safety measures, protecting lives, installations, buildings or structures	Webinar
48	Improving plant safety for minimizing hazards, risks, accidents and near misses	Webinar
49	Smart factory–key components, principles & technology used in its creation for smart manufacturing	Webinar
50	Advance training on electrical safety: hazards , safety audit, standards ,electrical safety act, 2003	Webinar
51	Design, development, application and maintenance of tools, dies, jigs and fixtures	Webinar
52	Fire safety management , control of fire hazards and accidents and fire emergency plan	Webinar
53	Improving energy performance by implementing an effective ISO 50001: 2018 energy management system	Webinar

List of Webinars and Online Training Programs for FY 2021-22		
54	Electrical safety, control of electrical hazards and electrical emergency plans and procedures	Webinar
55	Improving health & safety perpormance by controlling hazards by implementing ISO 45001: 2018 system	Webinar
56	Planning and conducting safety audit, effective safety audit management for maximizing benefits	Webinar
57	Six waste management rules,2016	Webinar
58	Design, development, application and maintenance of tools, dies, jigs and fixtures	Webinar
59	Improving quality and customer satisfaction by implementing ISO -9001:2015 quality management system	Webinar
60	Improving environmental performance by implementing ISO 14001 :2015 environment management system	Webinar
61	Safety acts -occupational safety, health & working conditions code,2020, electricity act,2003 & hazardous chemicals rules,1989	Webinar
62	Effective plant safety management for controlling hazards & preventing accidents	Webinar
63	Improving quality & customer satisfaction through ISO 9001 2015 & IATF 16949 2016 QMS implementation	Webinar
64	Improving workplace safety through behavior based safety(BBS) methods and practices	Webinar
65	Improving information security & reliability through ISO 27001:2013 isms	Webinar
66	Electrical safety, measures against electrical accidents& implementing electrical emergency plans	Webinar
67	2 day online practice training course on boiler efficiency calculation	Webinar
68	Boiler Engineering Drawing	Webinar
69	Cleaner Production- Need of Hour	Webinar
70	Constructional features and functioning of DC Batteries, Procedure of first charging and their Resi	Webinar
71	Data Analysis and QC tools With Excel	Webinar
72	E- Waste (Management) Rules, 2016	Webinar
73	Energy Saving in HVAC and Compressors through MAXR100-200 Technology	Webinar
74	Go Beyond HAZOP- Do LOPA and SIL Studies to safeguard your plant from disasters	Webinar
75	How to write a Book	Webinar
76	Improving Productivity in Services	Webinar
77	Introduction to advanced supply chain concepts - Day1	Webinar
78	Material Flow CostAccounting: ISO 14051	Webinar
79	Measuring the Performance of People- A case study	Webinar
80	Plastic Waste Management Rules, 2016	Webinar
81	Resume Writing & 8 Steps of Job Application	Webinar
82	Super Critical Technology	Webinar
83	Online Training & Certification Program on 'Six Sigma Green Belt' covering advanced concepts of Six Sigma Technology	Online Training
84	Online Training & Certification program on 'transformation to data driven decision making	Online Training
85	Online Training & Certification program on 'six sigma green belt' covering advanced concepts of six sigma methodology	Online Training
86	Unlocking The Secretes & Science Of Happiness For PGCIL, BBSR	Online Training

List of Webinars and Online Training Programs for FY 2021-22

87	In company e-training program on Public Procurement & RTI for NABARD	Online Training
88	In company e-training program on Preventive Vigilance & Right to Information Act for DVC	Online Training
89	In company e-training program on Preventive Vigilance for Goa Shipyard Ltd., Goa	Online Training
90	In company e-training program on Enhancing Interpersonal communication skills for MSTC Ltd.	Online Training
91	E-training program on Pre promotion training for SIDBI	Online Training
92	Two Days Online Training Programme on Carbon Footprint Reduction and Clean Development Mechanism (CDM)	Online Training
93	Online Training Program on "Issues related to public procurement/GeM& contract management/ Arbitration in CPSE's	Online Training
94	1 Day Online Training Programme on Implementation of 5S for Bharat Oman Refineries Limited	Online Training
95	How PSUs Can help in Atmanirbhar Bharat of Govt of India (IOCL)	Online Training
96	Green building design constraints	Online Training
97	Procurement Management through GeM	Online Training
98	How to start Oxygen Manufacturing Plant	Online Training
99	Introduction to Sustainable Development in Business	Online Training
100	Online Training on Right to Information ACT	Online Training
101	How to setup Solar PV System for residential & commercial establishments	Online Training
102	Two day online Training on Excellence in Leadership	Online Training
103	Setting up an Oxygen Manufacturing Plant in India	Online Training
104	SA 8000 - Social Certification	Online Training
105	Value Stream Mapping for Industries	Online Training
106	Internal Auditing of Integrated Management System- ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001	Online Training
107	Reservation in Services and preparation of Roster	Online Training
108	Operational Excellence through Lean Management and Six Sigma	Online Training
109	Salient Features of RTI Act and Records Management in government organisations	Online Training
110	Financial Basics for Entrepreneurs and Startups	Online Training

List of Clients of Water audits undertaken In FY 2021-22	
S. No.	**Client**
1	Visaka Industries Ltd, Sambalpur
2	Apar Industries Ltd, Jharsuguda
3	Shyam Metalics & Energy Ltd, Sambalpur
4	Prakash Industries,Cg
5	Ultratech Cement Ltd, Balkunth,Cg
6	Brandsteel, Keonjhar
7	Imfa,Rayagada
8	N.H Goel World School,Cg
9	Shiva Cement, Rourkela
10	Magnum Sea Foods Ltd, Bbsr
11	Triveni Mines, Keonjhar
12	Godawari Natural Resources Pvt Ltd, Cg
13	J.K.Lakshmi Cement Ltd, Cuttack
14	Ultratech Cement Works, Cuttack
15	Sreerangam Exports Pvt Ltd, Bbsr
16	Nuvoco Vistas Corporation(Sonadih Cement Plant),Cg
17	Misrilal Mines, Jajpur & Dhenkanal
18	R.R.Energy Ltd, Cg
19	Nuvoco Vistas Corporation(Arasmeta Cement Plant),Cg
20	Hari Marine Pvt, Ltd, Balasore
21	Sevenstar Steels Ltd, Jharsuguda
22	Grasim Industries,Ganjam
23	Rexon Strips Ltd, Rourkela
24	Rungta Mines Ltd, Keonjhar
25	Adani Enterprises Ltd,Cg
26	Apar Industries Ltd,Sambalpur
27	Suraj Products Ltd,Rajgangpur
28	Ultratech Cement Jharsuguda
29	Ardent Steel Pvt Ltd, Keonjhar
30	Sarda Mines Ltd, Keonjhar
31	Abc Ashpro,Cuttack
32	Falcon Marine Exports Ltd., Balasore
34	BanswaraSyntex, Banswara
35	Dr.Oetker India Pvt. Ltd., Alwar
36	Jaqar SP-53 & SP 496B, Alwar
37	Maharaja AgroAgro Foods Pvt. Ltd.
38	Roochi Soya
39	Reliance Chemotex
40	Kemwell Biopharma Private Limited
41	Resipharm Pharmaservices Private Limited
42	IPCA Laboratories Limited, Ranoli, Baroda
43	TTK Prestige Ltd., Vadodara
44	J K Lakshmi Cement Ltd., Sirohi
45	Huber Group India Pvt. Ltd., Silvassa
46	Huber Group India Pvt. Ltd., Daman
47	Gadre Marine Export Pvt. Ltd, Chorwad
48	TML Industries Ltd, Bharuch

List of Clients of Water audits undertaken In FY 2021-22	
49	Gujarat Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd, Ahmedabad
50	Ambuja Cements Ltd., Gir Somnath
51	TranspekSilox Industry Pvt. Ltd., Vadodara
52	TML Industries Ltd., Vadodara
53	Aarti Surfactants Ltd., Silvassa
54	Mayur Dyechem Intermediates Ltd., Vadodara
55	Sun Pharmaceutical Medicare Ltd., Panchmahal
56	Gujarat Insecticides Ltd., Ankleshwar
57	Sabic IP India Pvt. Ltd., Vadodara
58	Astron Paper & Board Mill Ltd., Morbi
59	Archean Chemical Industries P Ltd, Kutch
60	Reliance Industries Ltd., Vadodara
61	Siddhi Industries Ltd., Ahmedabad
62	Lonsen Kiri Chemical Industries Ltd, Padra, Baroda
63	Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd., Surat
64	Saurashtra Cement Ltd., Porbandar
65	Gujarat Sidhee Cement Ltd., Sidheegram
66	Nirma Ltd. Kalol
67	Nirma Ltd. Mehsana
68	Nirma Ltd. Porbandar
69	AIA Engineering Ltd., Ahmedabad- 1
70	BanswaraSyntex, Banswara
71	Dr.Oetker India Pvt. Ltd., Alwar
72	Jaqar SP-53 & SP 496B, Alwar
73	Maharaja AgroAgro Foods Pvt. Ltd.
74	Roochl Soya
75	Reliance Chemotex,
76	M/s Ajanta Pharma
77	M/s Hindustan Unilever Ltd.
78	M/s NEEPCO Ltd.
79	M/s Excelcare Hospitals
80	M/s NEFA Breweries
81	M/s Star Cement Ltd.
82	M/s Rhino Agencies
83	M/s Brahmaputra Crackers & Polymer Ltd.
84	M/s Ultratech Cement Limited,Near Daniyaw Village Shajahnapur
85	M/s. Shah Sponge & Power Ltd, JURI, Near HATA,
86	Metalsa India | Jamshedpur Plant
87	Britania Industries Ltd.
88	Triveni Sainik Mining Pvt Ltd
89	M/s Majhaulia Sugar PvtLtd.
90	M/s. Mateshwari Paper Mill Pvt Limited, Mahuli, Patna City
91	M/s. Smrity Paper Mill Pvt Limited, Chhitma, Mahooli Road, Patna City
92	M/s Madhepura Electric Locomotive plant
93	Bholaram Papers & Power Pvt. Ltd
94	M/s Hindustan Urvarak &Rasayan Limited, Bihat (Nagar Parisad) Barauni,Begusarai, Bihar

List of APO Programmes in FY 2021-22		
S.No.	Project	Date
1	Conference on Smart Agriculture	19-Apr-21
2	5th International Conference on Bio-fertilizers and Bio-pesticides: Marketing and Commercialization	28 April 2021
3	Workshop on Productivity promotion movement in the Digital Age	20–22 April 2021
4	Workshop on Green Productivity for Sustainable Development	7–9 April 2021
5	Basic Training Course on Foresight for Public-sector Organizations	25-27 May 2021
6	Workshop on Diversity and Organizational Performance in the Public Sector	18–20 May 2021
7	Training Course on Critical Big Data Analytics to Drive Productivity (DMC)	26-28th April 2021
8	Conference on Emerging Technologies for Productivity Enhancement	8th April 2021
9	Multi-country Observational Study Mission on Modern Farm Machinery	15-17 June 2021
10	Workshop on Women's Empowerment for Productivity Gains	22-24 June 2021
11	Workshop on Service Design for Business Growth and Improvement	1-3 June 2021
12	Multi-country Observational Study Mission on Advanced Food Safety Management.	28–30 June 2021
13	Individual-country Observational Study Missions	April–December 2021
14	Technical Cooperation Program for COVID-19 Pandemic Recovery: Capability Development on Cold Chain Systems in Agri-food SMEs	1 December 2020–30 November 2021
15	Research on an Aging Asia and Pacific: Preparing for the Future	April–December 2021
16	Management of the APO Accreditation and Certification Program	April–December 2021
17	Development of Demonstration Companies and the Application Guidelines.	April–December 2021
18	Workshop on Ecological Models of Agro-forestry Systems	16–18 June 2021
19	Workshop on Productivity Gain-sharing Models in Agribusiness Enterprises	14–16 July 2021
20	Labor Productivity Index	June–December 2021
21	Research on Labor Market Policies for Changing Market Demands	June–December 2021
22	Research on the Complementarities of the Circular Economy and Green Productivity	June–December 2021
23	Observational Study Mission on Emerging Models of Controlled-environment Agriculture	27–29 July 2021
24	Conference on Enabling Regulations to Accelerate Agricultural Innovations	22-Jul-21
25	Training Course on Productivity Measurement for Service-Sector Organization	21–23 July 2021
26	Conference on Promoting the Circular Economy in Manufacturing through Green Productivity	30-Jul-21
27	Workshop on Modern Food Transportation and Regulation	13–15 July 2021
28	Workshop on Regulatory Ecosystems for Startups	28–30 July 2021
29	Conference on Public-sector Productivity: Ensuring Public Services in the New Normal	25-Aug-21
30	Workshop on Smart Transformation for Various Economic Sectors	21 July to 23 July 2021
31	Multi-country Observational Study Mission on Enhancing Equal Opportunities for Inclusive Engagement of the Workforce	28-30 July 2021
32	Workshop on Enhancing Productivity for SMEs: Measuring and Analyzing Productivity Gains	11-13 August 2021

List of APO Programmes in FY 2021-22		
33	Research on Innovation-led Productivity Growth for Middle-Income Trap Avoidance	July–December 2021
34	Training Course on Internet of Things Applications for Smart Manufacturing	25–27 August 2021
35	Conference on Social Empowerment in Agriculture	Thursday, September 2, 2021
36	Workshop on Agricultural Innovations	15–17 September 2021
37	Training of Assessors for the Green Productivity Specialists Certification	23-25 August 2021
38	Workshop on Cyber security and Network Resilience Approaches for industry 4.0	7-9 September 2021
39	Workshop on Blockchain Solutions for SME Productivity	25-27 August 2021
40	Workshop on Continuing Education for the Aging Societies	15-17 September 2021
41	Workshop on Rural Economic Development through Development of Village Tourism	5-7 October
42	Conference on Urban Agro-ecology and Food Security	Thursday, September 9, 2021
43	Workshop on Digitization of SMEs in the Manufacturing Sector	28-30 September 2021
44	Conference on Organic Farming and Agro-ecology	Thursday, October 7, 2021
45	Training Course for Green Productivity Specialists	13–17 September 2021
46	Workshop on the Circular Economy in the Agro-industry Sector and guidelines on the implementation procedures	12-14 October 2021
47	Strengthening the Center of Excellence on IT for Industry 4.0 (India)	September–December 2021
48	Workshop on Evaluating Regulatory Quality and Performance to Improve Public-sector Productivity	10-12 Nov 2021
49	Workshop on Enhancing Service Productivity through Effective Business Models	19-21 October 2021
50	Workshop on Development of New Innovation Standards for SMEs	13-15 October 2021
51	Multicountry Observational Study Mission on Service Quality and Productivity for the Retail Industry	27-29 October 2021
52	Research on Need Assessment on Innovation Management	October–December 2021
53	Development of APO-certified Public-sector Productivity Specialists	6-10 December 2021 (three days)
54	Multicountry Observational Study Mission on Support for Digital Transformation for SMEs	10–12 November 2021
55	Training Course on Innovative Aquaculture Models	16–18 November 2021
57	Training Course on Service-sector Productivity Specialists	10–12 November 2021
58	Workshop on Innovations in Farmers' Cooperatives and Producers' Associations	9–11 November 2021
59	Multicountry Observational Study Mission on Data Governance in the Public Sector to Improve Productivity	24–25 November 2021
61	Workshop on Waste Management in Manufacturing SMEs through MFCA and Lean	24–26 November 2021
62	Workshop on Food Storage Models	30 November–2 December 2021
63	Workshop on Modern Mechanization Technologies for Increasing Rice Productivity	24–26 November 2021
64	Workshop on Developing National Innovation Systems	23–25 November 2021
65	Workshop on Innovative Business Models for Industry 4.0	24–26 November 2021

List of APO Programmes in FY 2021-22		
66	Workshop on Nurturing Social Enterprises	6–8 December 2021
67	Workshop on the Circular Economy for the SDGs	
68	Workshop on Agroecological Systems	14–16 December 2021
69	Workshop on Adoption of Industry 4.0 Applications for SMEs	7–9 December 2021
70	Training Course on Strategic Management for Public- sector Productivity Enhancement	30 November-3 December 2021
71	Workshop on Requirements and Management System for APO Certification of Persons Scheme	7–9 December 2021
72	Development of APO-certified Public-sector Productivity Specialists	6–10 December 2021
73	Training Course on Data Analysis and Applications for Digitization in SMEs	14–17 December 2021
74	Training Course on Energy Audits and Management	20-24 December 2021 (four days)
75	Workshop on Enhancing Employee Productivity in the Digital Workplace	23–25 February 2022
76	Demonstration Farm on Innovative Agriculture	January 2022–August 2024
77	Development of APO-certified Productivity Specialists	7–11 March 2022 (five days)
78	Workshop on the Internet of Things in Agriculture and Food Supply Chain Management	9–11 March 2022 (three days)
79	Workshop on Decentralized Governance and Public Accountability	23–25 March 2022 (three days)
80	Workshop on Talent Development for the Future of Work	29–31 March 2022 (three days)

वार्षिक लेखा
वित्तीय वर्ष 2021-22

BALANCE SHEET
FINANCAL YEAR 2021-22

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

(उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

SANDEEP SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
WZ-1390/7A, NANGAL RAYA,
PANKHA ROAD,
NEW DELHI-110046
MAIL: sandeep_fca2003@yahoo.co.in
(M) 9899104355

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
5-6 Institutional Area, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **National Productivity Council** which comprise the Balance Sheet as at **31st March 2022**, the Statement of Income & Expenditure Account for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other applicable statement and explanatory information.

The Balance Sheet, Statement of Income & Expenditure dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained by the council.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, **subject to the observations given in Annexure-A(point No. 1 to 19) and their consequential effect on Income and Expenditure, Assets and Liabilities and read together with accounting policies and notes thereon,** give a true and fair view:

i) In case of the statement of affairs of the council as at **31st March 2022;** and
ii) In the case of Income & Expenditure Account of the excess of expenditure over income of the Council for the year ended on the date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Council's preparation of the financial

Sandeep Singh & Co. FRN: 021822N New Delhi Chartered Accountants

statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by those Charged with Governance of the Council, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Responsibilities Management and Those Charged with Governance for the Financial Statement

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statement in accordance with the societies Registration Act, 1860 of India and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the council's ability to going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the society to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charges with governance are responsible for overseeing the council's financial reporting process.

Auditor's Responsibility

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of these financial statements.

For SANDEEP SINGH & CO.
Chartered Accountants

CA. SANDEEP SINGH
(Prop.) M. No. 094439
FRN: - 021822N
Place: New Delhi
Dated: 29.09.2022
UDIN NO.

Annexure A referred to in our report on the accounts of National Productivity Council for the Year ended 31st March 2022.

1. **GST**:-

   i) It is observed that the council has not taken the ITC (Input Tax Credit) of Rs. 49,36,342/- in the GST returns filed.

   ii) There are mismatch in the amounts of Output as per GSTR-1 and as per Books of Accounts(**Refer annexure-1)**

   iii) There are mismatch in the amounts of Output as per Books and as per GSTR-3B Returns of the Council.(**Refer annexure-2**)

2. **Unclaimed Receipts : -**

   We observed that amount of Rs. 1,22,62,438.01/- is recorded in books of Accounts as unclaimed receipts pertaining to FY 2016-17 to 2021-22. Unclaimed receipts is receipts which are unclear to HQR NPC. We are unable to comment on its impact in the absence of any confirmation from debtors, whether these amounts can be adjusted against outstanding balances of various debtors. Moreover, the council has also deposited GST on the unclaimed amounts which may result in double GST deposits to the Government.

Unclaimed Income (2016-17-18)	728496.00
Unclaimed Receipts FY 2019-20	3615714.00
Unclaimed Receipts FY 2020-21 (IOB BANK)	1646572.00
Unclaimed Receipts FY 2020-21 (IOB-WEBINAR)	247599.40
Unclaimed Receipts FY 2020-21 (SBI-WEBINAR)	170633.48
Unclaimed Receipts FY 2021-22 (IOB Bank)	3302338.47
Unclaimed Receipts FY 2021-22 (IOB-WEBINAR)	729227.31
Unclaimed Receipts FY 2021-22 (SBI-WEBINAR)	1332064.35
Unclaimed Recepits FY 2018-19	489793.00
Grand Total	**12262438.01**

3. **Sundry Debtors: -**

   i) The management has not obtained debtors balance confirmation for the F.Y 2021-22. The Letters were sent by NPC for Balance Confirmation but no reply was received.

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

ii) Debtors where payments are not received for more than one year amounts to Rs. 1,79,31,705/-.

iii) Provision for doubtful debts Rs. 55,40,667/- is created during the year in the books of accounts.

4. **TDS: -**

i) It is observed that there are defaults of TDS as per TRACES Portal of Rs. 8,33,004.14/-

TDS default has been found on Income tax portal. Please find below detail

S. No.	FY	Short payment	Short Deduction	Interest on Payment u/s 201	Interest on Deduction defaults u/s 201	Late filing u/s 234E	Interest u/s 220(2)	Total Defaults
1	2021-22	0.00	169680.43	6506.50	6805.00	15400.00	260.00	198651.93
2	2020-21	0.00	7942.03	17008.50	613.00	11800.00	472.00	37835.53
3	2019-20	2302.00	0.00	2788.00	0.00	200.00	66.00	5356.00
4	2018-19	0.00	20166.88	0.00	990.00	0.00	0.00	21156.88
5	Prior Years	126850.00	238517.30	49066.50	152732.00	2600.00	238.00	570003.80
Total		129152	436306.64	75369.50	161140	30000.00	1036.00	833004.14

ii) TDS Refunds of Ass. Yr. 2013-14 to 2016-17 are still pending for recovery.

iii) It is noticed that TDS receivable of Rs. 2,83,762/- relating to F.Y. 2020-21 is now entered in F.Y 2021-22. Moreover TDS receivable of Rs. 14,00,689/- booked in F.Y 2021-22 is not been reflected in Form 26AS. It is advised that respective parties may be contracted to correct their TDS returns.

5. **Fixed Assets : -**

i) Fixed Assets Register No. 1 :- As per index, there are total 40 categories of Fixed Assets but in the register only 9 categories are entered, wherever the Assets are Purchased.

ii) Fixed Assets Register No. 2:- Total 52 Categories total entries entered 6 No's.

iii) Fixed Assets Register No. 3:- Total 18 Categories entered in Register 12 categories.

6. On the test check basis of FORM -2 reconciliation, we observed that NPC HQ missed the bills of expenses to feed in FY 2021-22.(**Ref Annexure-3**).

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

7. **NPC-QCI Section of Dipp" Ministry of Commerce & Industries** :- **Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 21,15,001/-**

   Original bill was issued on 14.12.2018 for Rs. 17,32,055/- GST of Rs. 3,11,770/- was charged and paid to GST department. Amount is not received till date from party. GST of Rs 3,11,770/- was paid in FY 2018-19 on Sales of Rs. 17,32,055/- which is also to be received. Confirmation of Amount receivable is not available from party above.

8. **BSES Rajdhani Power SP –IE : - Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 16,95,224/-**

   Original bill was issued on 08.07.2019 for Rs. 14,36,629/- GST of Rs. 2,58,594/- was charged and paid to GST department. Amount is not received till date from party. GST of Rs 2,58,594/- was paid in FY 2019-20 on Sales of Rs. 14,36,629/- which is also to be received. Confirmation of Amount receivable is not available from party above.

9. **Bureau of Energy Efficiency SC-EMU : - Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 3,80,710/-**

   Payment of Rs. 3,80,710/- is receivable since 01.04.2021. We observed that Bill issued on October 2021 was received in December 2021 and Bill issued on June 2022 was received in July 2022. But the party is deliberating not paying 3,80,710/- which is receivable since 01.04.2021.

10. **Directorate of General of Quality Assurance (DGQA): - Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 14,75,000/-**

    Original bill was issued on 11.08.2021 for Rs. 14,75,000/- GST of Rs. 2,25,000/- charged and paid to GST department. Amount is not received till date from party. Confirmation of Amount receivable is not available from party above.

11. **Petroleum and Explosives Safety Organisation – HRM: - Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 12,56,110/-**

    We observed that payment of Rs. 1230988 is received from 25.02.2022 in HQR accounts but same is not recorded in Party account.

12. **Prasar Bharti - SP/PMG : - Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 37,22,107/-**

    We observed that amount of Rs. 3722107 is receivable since FY 2007-08 as per explanation received. We observed that no legal notice is served to party and complete legal follow-up for payment is pending.

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

13. **West Bengal Pollution Control Board – HRM :- Amount receivable as on 31.03.2022 is Rs. 1,57,29,938/-**

No payment is received from party since 01.04.2022 to till date. The payment is receivable for more than 1 year from the date of sales bill issued on dated 13.10.2021. No legal notice is served to party and complete legal follow-up for payment is pending. Also No party confirmation is available on record. We observed that GST of more than 22 lacs is paid by NPC HQR without receiving any amount from party.

14. Misc advance ledgers are shown as advances in books till 31.03.2022 and no expenses are recorded against it. Provide Confirmation of balances from following parties listed below: -

PARTY	AMOUNT
PAO (BOC ETC) MA	24304.00
SHRI RAJESH KUMAR ,STAFF CAR DRIVER - MA	11461.25
SHRI SHRI PRASAD-TA	26721.00
Grand Total	**62486.25**

15. **Sundry Debtors where advance is received but Sale Bills are not issued amount to Rs. 1,82,32,860.70.**

16. **Differences between RDs and HQR balances given below:-**

Name	Balance in HQR books	Balance in branch	Diff.
GANDHI NAGAR	31736991.70	31735717.30	1274.10
JAIPUR	10714196.23	10708488.74	5707.49

17. **Detail of Security Deposit of Rs. 8,04,443/- in AIP RD is not available.**

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

18. Internal Audit:-

During the year under audit, it was observed that there are no adequate internal controls. Internal control needs to be strengthen and strictly followed commensurate to the size of the council.

19. Confirmation: -

The balances of Sundry Debtors, Sundry Creditor, advance recoverable, advance payable, security deposits/payable with/to various agencies/parties etc. as on 31.03.2022 are subject to confirmation and reconciliation which may have impact on the profitability and state of affair of Council as on 31.03.2022.

For SANDEEP SINGH & CO.
Chartered Accountants

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

CA. SANDEEP SINGH
(Prop.) M. No. 094439
FRN: - 021822N
Place: New Delhi
Dated: 29.09.2022
UDIN NO.

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

RECONCILIATION OF OUTPUT TAX AS PER GSTR 1 AND BOOKS

Annexture -1

HQ (07AAATN0402F1Z8)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	8,333,864.65	8,288,196.09	8288196.09	24,910,256.83
Sales as per Books	6,580,526.49	4,780,290.54	4,780,290.54	16,141,107.57
Difference	**1,753,338.16**	**3,507,905.55**	**3,507,905.55**	**8,769,149.26**

1 PATNA (10AAATN0402F2ZK)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	739047.42	263392.2	263392.2	1265831.82
Sales as per Books	739047.42	263392.2	263392.2	1265831.82
Difference	-	-	-	-

2 Bangalore (29AAATN0402F1Z2)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	412,407.79	329,437.84	329,437.84	1,071,283.47
Sales as per Books	412,407.79	329,382.84	329,382.84	1,071,173.47
Difference	-	**55.00**	**55.00**	**110.00**

3 KANPUR (09AAATN0402F1Z4)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	**464,971.77**	**387,791.82**	**387,791.82**	**1,240,555.41**
Sales as per Books	464,971.77	387,791.79	387,791.79	1,240,555.35
Difference	-	**0.03**	**0.03**	**0.06**

4 JAIPUR (08AAATN0402F1Z6)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	1,025,807.03	302,795.71	302,795.71	1,631,398.45
Sales as per Books	**999,665.16**	**309,662.80**	**309,662.80**	1,618,990.76
Difference	**26,141.87**	**(6,867.09)**	**(6,867.09)**	**12,407.69**

5 MUMBAI (27AAATN0402F1Z6)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	90,967.50	535,987.17	535,987.17	**1,162,941.84**
Sales as per Books	90,967.50	536,518.17	536,518.17	**1,164,003.84**
Difference	-	**(531.00)**	**(531.00)**	**(1,062.00)**

6 BHUBANESHWAR (21AAATN0402F3ZG)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	510,120.00	813,298.50	813,298.50	**2,136,717.00**
Sales as per Books	510,120.00	813,298.50	813,298.50	**2,136,717.00**
Difference	-	-	-	-

7 GUWAHATI(18AAATN0402F1Z5)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

Sales as per GSTR-1	235,116.00	213,925.61	213,925.61	662,967.22
Sales as per Books	235,116.00	214,067.50	214,067.50	663,251.00
Difference	-	(141.89)	(141.89)	(283.78)

8 GANDHINAGAR(24AAATN0402F1ZC)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	3,993,337.80	1,122,287.87	1,122,287.87	6,237,913.54
Sales as per Books	3,660,795.92	1,061,193.50	1,061,193.50	5,783,182.92
Difference	332,541.88	61,094.37	61,094.37	454,730.62

9 KOLKATA(19AAATN0402F1Z3)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	4,786,741.97	201,957.74	201,957.74	5,190,657.45
Sales as per Books	4,787,613.07	201,958.74	201,958.74	5,191,530.55
Difference	(871.10)	(1.00)	(1.00)	(873.10)

10 HYDERABAD(36AAATN0402F1Z7)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	986,716.80	455,762.88	455,762.88	1,898,242.56
Sales as per Books	986,716.77	421,742.90	421,742.90	1,830,202.57
Difference	0.03	34,019.98	34,019.98	68,039.99

11 AIP CHENNAI(33AAATN0402F1ZD)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	1,459,607.04	985,466.52	985,466.52	3,430,540.08
Sales as per Books	1,459,608.00	986,268.00	986,268.00	3,432,144.00
Difference	(0.96)	(801.48)	(801.48)	(1,603.92)

12 CHANDIGARH(04AAATN0402F1ZE)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-1	862,057.08	191,137.14	191,137.14	1,244,331.36
Sales as per Books	876,243.00	191,268.00	191,268.00	1,258,779.00
Difference	(14,185.92)	(130.86)	(130.86)	(14,447.64)

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

RECONCILIATION OF OUTPUT TAX AS PER GSTR GSTR-3B AND BOOKS

Annaxure-2

HQ (07AAATN0402F1Z8)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	7,983,175.40	10,194,072.27	10194072.27	28,371,319.94
Sales as per Books	6,580,526.49	4,780,290.54	4,780,290.54	16,141,107.57
Difference	**1,402,648.91**	**5,413,781.73**	**5,413,781.73**	**12,230,212.37**

1 **PATNA (10AAATN0402F2Z**

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	739047.42	288736.2	288736.2	1316519.82
Sales as per Books	739047.42	263392.2	263392.2	1265831.82
Difference	-	**25,344.00**	**25,344.00**	**50,688.00**

2 **Bangalore (29AAATN0402**

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	412,407.79	330,039.84	330,039.84	1,072,487.47
Sales as per Books	412,407.79	329,382.84	329,382.84	1,071,173.47
Difference	-	**657.00**	**657.00**	**1,314.00**

3 **KANPUR (09AAATN0402F1Z4)**

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	**464,971.77**	**390,944.97**	**390,944.97**	**1,246,861.71**
Sales as per Books	464,971.77	387,791.79	387,791.79	1,240,555.35
Difference	-	**3,153.18**	**3,153.18**	**6,306.36**

4 **JAIPUR (08AAATN0402F1Z6)**

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	992,075.03	302,795.82	302,795.82	1,597,666.67
Sales as per Books	**999,665.16**	**309,662.80**	**309,662.80**	1,618,990.76
Difference	**(7,590.13)**	**(6,866.98)**	**(6,866.98)**	**(21,324.09)**

5 **MUMBAI (27AAATN0402F1Z6)**

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	90,967.50	535,987.17	535,987.17	**1,162,941.84**
Sales as per Books	90,967.50	536,518.17	536,518.17	**1,164,003.84**
Difference	-	**(531.00)**	**(531.00)**	**(1,062.00)**

6 **BHUBANESHWAR (21AAATN0402F3ZG)**

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	510,120.00	813,298.50	813,298.50	**2,136,717.00**
Sales as per Books	510,120.00	813,298.50	813,298.50	**2,136,717.00**
Difference	-	-	-	-

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

7 GUWAHATI(18AAATN0402F1Z5)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	235,116.00	215,775.00	215,775.00	666,666.00
Sales as per Books	235,116.00	214,067.50	214,067.50	663,251.00
Difference	-	1,707.50	1,707.50	3,415.00

8 GANDHINAGAR(24AAATN0402F1ZC)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	3,620,790.36	1,086,030.15	1,086,030.15	5,792,850.66
Sales as per Books	3,660,795.92	1,061,193.50	1,061,193.50	5,783,182.92
Difference	(40,005.56)	24,836.65	24,836.65	9,667.74

9 KOLKATA(19AAATN0402F1Z3)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	464,971.71	390,944.97	390,944.97	1,246,861.65
Sales as per Books	4,787,613.07	201,958.74	201,958.74	5,191,530.55
Difference	(4,322,641.36)	188,986.23	188,986.23	(3,944,668.90)

10 HYDERABAD(36AAATN0402F1Z7)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	986,716.80	421,743.00	421,743.00	1,830,202.80
Sales as per Books	986,716.77	421,742.90	421,742.90	1,830,202.57
Difference	0.03	0.10	0.10	0.23

11 AIP CHENNAI(33AAATN0402F1ZD)

PARTICULAR	IGST	CGST	SGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	1,459,606.92	1,040,092.40	1,040,092.40	3,539,791.72
Sales as per Books	1,459,608.00	986,268.00	986,268.00	3,432,144.00
Difference	(1.08)	53,824.40	53,824.40	107,647.72

12 CHANDIGARH(04AAATN0402F1ZE)

PARTICULAR	IGST	CGST	UTGST	TOTAL TAX
Sales as per GSTR-3B	862,057.08	191,137.14	191,137.14	1,244,331.36
Sales as per Books	876,243.00	191,268.00	191,268.00	1,258,779.00
Difference	(14,185.92)	(130.86)	(130.86)	(14,447.64)

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

LISIT OF BILLS NOT ENTERED IN THE BOOKS OF ACCOUNTS : -

Annexure-3

GSTN	NAME	Bill no	DATE	TOTAL	Gross	IGST	CGST	SGST
07AAACN2185J1ZE	National Informatics Centre Services Inc.	SEP/SC/2122/2552	28/09/2021	1,111,088.00	941,600.00	-	84,744.00	84744.00
30AALCS8980K1ZS	SUN VILLAGE RESORTS PVT.LTD.	0207FMBIL0004322	26/03/2021	663,200.00	575,535.70	-	34,532.14	34532.14
07AAACN2185J1ZE	National Informatics Centre Services Inc.	DEC/SC/2122/2757	28/12/2021	662,433.12	561,384.00	-	50,524.56	50524.56
08AAACJ8578R1ZJ	JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LTD.	SSrAORev221	02/06/2021	591,053.50	500,892.80	90,160.70	-	-
30AALCS8980K1ZS	SUN VILLAGE RESORTS PVT.LTD.	0207FMBIL0002888	17/12/2021	209,079.98	186,678.56	-	11,200.71	11200.71
19AAFCR3857G1Z2	RIS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	RIS/0148/22-23	23/07/2022	162,260.00	137,508.29	24,751.49	-	-
Grand Total				**3,399,114.60**	**2,903,599.35**	**114,912.19**	**181,001.41**	**181,001.41**

Sandeep Singh & Co. Chartered Accountants FRN : 021822N New Delhi

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2022

Particulars	Sch. No		As at March 2022		As at March 2021
SOURCES OF FUNDS					
Capital Fund	1		321,412,096		322,906,020
Project Financed by Various Agencies	2		56,916,079		62,803,045
Current Liabilities & Provisions	3		408,925,281		316,293,140
TOTAL			787,253,457		702,002,205
APPLICATION OF FUNDS					
Fixed Assets	4				
Gross Block-Plan		96,088,810		338,269,105	
Gross Block-Non Plan		65,336,403	161,425,213	57,921,038	396,190,143
Less :Depreciation					
Plan		29,905,093		263,409,740	
Non Plan		44,874,610	74,779,703	39,827,714	303,237,454
Net Block			**86,645,534**		**92,952,689**
Current Assets, Loans and Advances	5				
Sundry Debtors		92,842,695		45,138,967	
Cash & Bank Balance		131,587,313		176,051,236	
Investments in Fixed Deposit		219,592,178		154,429,965	
Loans & Advances		41,383,656		27,526,341	
Income Tax Recoverable		36,012,473	521,418,315	38,455,711	441,602,221
Branch			6,982		-
Deferred Revenue Expenditure			-		-
Proj. financed by various agencies.	2		1,983,236		1,435,271
Excess of expenditure over income	6		177,199,390		166,012,024
TOTAL			787,253,457		702,002,205
Significant accounting Policies and Notes of the Accounts	16				

As per our separate report of even date attached

For Sandeep Singh & Co
Chartered Accountants
Firm Registration Number :021822N

CA Sandeep Singh, Proprietor
Membership Number : 094439

Sandeep Singh & Co.
FRN : 021822N
New Delhi
Chartered Accountants

Date : September 29, 2022
Place : New Delhi
UDIN : 22094439AXKEFO4287

For National Productivity Council

Dr K P Sunny
Group Head (Finance)

Sundeep Kumar Nayak, IAS
Director General

Dr. K. P. Sunny
Director & Group Head (Finance)
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
(Under Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
Lodhi Road, New Delhi-110003

Sundeep Kumar Nayak, IAS
Director General
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
Department for Promotion of Industry & Internal Trade
Ministry of Commerce & Industry

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

Particulars	Sch. No.	As at March 2022		As at March 2021	
INCOME					
Grant-in-aid from Govt.					
PLAN					
Recd. during the year		161,526		1,820,000	
Balance b/f (+)		574,710		2,315,236	
		736,236		4,135,236	
Less: Assets purchased during year		-		-	
		736,236		4,135,236	
Less: Unspent Balance of Grant		-574,710	161,526	574,710	3,560,526
NON PLAN					
Recd. Grant during the Year			137,300,000		203,345,000
Activity Revenue	7		269,322,908		209,543,754
Receipts from publication	8		127,550		126,350
Other Receipts	9		35,034,484		34,701,667
TOTAL			**441,946,467**		**451,277,297**
EXPENDITURE					
Employees Remuneration & Benefits	10		304,455,277		352,125,523
Office & Admn. Expenses	11		125,385,263		98,318,878
Plan Project*	12		-		3,560,526
Misc.& other charges	13		8,619,656		114,603
Interest & Finance charges	14		151,817		378,093
International Cooperation	15		2,289,626		-
Depreciation	4		12,232,194		12,537,651
Excess of income over expenditure			-11,187,366		-15,757,977
TOTAL			**441,946,467**		**451,277,297**
Significant accounting Policies and Notes of the Accounts	16				

As per our separate report of even date attached

For Sandeep Singh & Co
Chartered Accountants
Firm Registration Number :021822N

CA Sandeep Singh, Proprietor
Membership Number : 094439

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

For National Productivity Council

Dr K P Sunny
Group Head (Finance).

Sundeep Kumar Nayak, IAS
Director General

डा. के. पी. सन्नी/Dr. K. P. Sunny
निदेशक एवं समूह प्रमुख (वित्त)
Director & Group Head (Finance)
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन)
(Under Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
लोधी रोड, नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-110003

संदीप कुमार नायक, आई.ए.एस./Sundeep Kumar Nayak, IAS
महानिदेशक/Director General
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्/NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/Department for Promotion of Industry & Internal Trade
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार, नई दिल्ली/Govt. of India, New Delhi

Date : September 29, 2022
Place : New Delhi
UDIN : 22094439AXKEF04287

Schedule: 1 Capital Fund

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
Opening Balance as per Last Year Audited Balance Sheet*	322,906,020	324,663,578
Add : Asset Purchased from Grant Fund during the Year	-	-
Less : Depreciation on Asset donated by Japan**	1,493,924	1,757,558
Total	**321,412,096**	**322,906,020**

* Included asset donated by Japan Government in earlier years.
** Deprecation on WDV of Rs.99,59,497/- as on 01.04.2021 @ 15%

Schedule: 3 Current Liabilities & Provisions

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
A:Current Liabilities		
Sundry Creditors HQ	11,489,902	12,569,675
Sundry Creditors RDs	949,755	1,570,371
Others Payable-HQ	109,387,147	44,190,485
Others Payable-RDs	20,388,556	15,140,683
Unspent balance (Plan)	574,710	574,710
Advance from Vendor	519,000	7,331,326
Sub Total A	**143,309,069**	**81,377,251**
B:Provisions		
Leave Encashment		
As per last Account	107,816,056	94,453,628
Add : Provision during the year	34,799,027	27,462,054
Less: Payments during the year	6,320,552	14,099,626
Closing Balance	**136,294,531**	**107,816,056**
Gratuity		
As per last Account	127,099,833	146,018,762
Add : Provision during the year	17,845,287	6,571,079
Less: Payments during the year	15,623,439	25,490,008
Closing Balance	**129,321,681**	**127,099,833**
Sub Total B	**265,616,212**	**234,915,889**
Total (A+B)	**408,925,281**	**316,293,140**

SCHEDULE -2, PROJECT FINANCED BY VARIOUS AGENCIES (ALIVE) AS ON 31/03/2022

S.NO.	Figures for the previous year 2020-21 Dr.	Figures for the previous year 2020-21 Cr.	Name of the Project	Group	Receipt upto 1.4.2021	Reciept During the year 2021-22	Total as on 31/03/22	Exp upto 1.4.2021	Expen. During the year 2021-22	Written down value of assets	Total as on 31/03/2022	Balance DR.	Balance CR.	Ongoing /Closed
1	-	10,309,364	ABG/C-DAP/2017-18	AB	23,310,000	1,186,000	24,496,000	13,000,636	11495364	-	24,496,000	-	-	Closed
2	-	611,610	ABG/CSIR-IHBT/2017-18	AB	1,687,500	-	1,687,500	1,075,890	-	-	1,075,890	-	611,610	Ongoing
3	-	770,084	ABG/CSIR-IHBT/WM-KD/2019	AB	961,700	-	961,700	191,616	-	-	191,616	-	770,084	Ongoing
4	-	-	ABG/DSJH/P/02/2019-20	AB	3,428,313	-	3,428,313	3,428,313	-	-	3,428,313	-	-	Closed
5	-	935	ABG/Evaluation/P/DOCA/2019-20	AB	8,332,275	-	8,332,275	8,331,340	935	-	8,332,275	-	-	closed
6	483,428	-	ABG/MMA-DOS/2017-18	AB	3,227,064	-	3,227,064	3,710,492	-	-	3,710,492	483,428	-	Ongoing
7	-	-	ABG/NJB-ICARE/2018-19	AB	2,991,800	-	2,991,800	2,991,800	-	-	2,991,800	-	-	Closed
8	-	377,072	ABG/P/04/2019-20	AB	618,792	-	618,792	241,720	-	-	241,720	-	377,072	Ongoing
9	-	2,058,128	ABG/PFC/P/05/2019-20	AB	2,548,800	-	2,548,800	490,672	488	-	491,160	-	2,057,640	Ongoing
10	-	-	ABG/RKVY-LTP/2018-19	AB	1,243,000	-	1,243,000	1,243,000	-	-	1,243,000	-	-	Closed
11	-	-	ABG/UP-RKVY/16-17	AB	25,053,600	-	25,053,600	25,053,600	-	-	25,053,600	-	-	Closed
12	103,166	-	ABG/P/06/2019-20	AB	2,868,464	-	2,868,464	2,971,630	-	-	2,971,630	103,166	-	Ongoing
13	-	-	ABG/P/07/2019-20	AB	1,061,409	-	1,061,409	1,061,409	-	-	1,061,409	-	-	Closed
14	-	12,100,965	NMPB2016-17(AB)	AB	24,897,276	-	24,897,276	12,796,311	-	-	12,796,311	-	12,100,965	Ongoing
15	-	437,640	ABG/P/01/2020-21	AB	589,764	-	589,764	152,124	84,960	-	237,084	-	352,680	Ongoing
16	-	3,780,000	ABG/P/02/20-21	AB	4,460,400	-	4,460,400	680,400	2,105,553	-	2,785,953	-	1,676,447	Ongoing
17	-	-	ABG/P/01/21-22	AB	-	2,016,400	2,016,400	-	2,331,453	-	2,331,453	315,053	-	Ongoing
18	250,832	-	APDP EM	EM	-		-	250,832		-	250,832	250,832	-	Ongoing
19	74,354	-	Deplomat & Demenstration Of New For Impeoved For Glass Ferozabad	EM	1,410,381	-	1,410,381	1,484,735	-	-	1,484,735	74,354	-	Ongoing
20	-	214,350	RDD/EM/P/01/MNRE/BPGTP	EM	542,800	814,200	1,357,000	328,450	1,028,550	-	1,357,000	-	-	Closed
21	-	109,695	East Third Party Independent Evaluation-Em, (West Bengal & Sikim)	EM	7,280,848	-	7,280,848	7,171,153	-	-	7,171,153	-	109,695	Ongoing
22	-	-	RDD/EM/P/01/Boiler Workshops /2019-20	EM	2,273,860	-	2,273,860	2,273,860	-	-	2,273,860	-	-	Closed
23	-	34,567	West Third Party Independent Evaluation-Em, (Daman & Gujrat)	EM	9,368,588	-	9,368,588	9,334,021	-	-	9,334,021	-	34,567	Ongoing
24	-	-	ES/DIPP/05/2018-19	ES	789,420	-	789,420	789,420	-	-	789,420	-	-	Closed
25	-	-	ES/DIPP/P/02/2016-17	ES	3,880,100	-	3,880,100	3,880,100	-	-	3,880,100	-	-	Closed
26	-	-	ES/NCUI/06/2017-18	ES	480,000	-	480,000	480,000	-	-	480,000	-	-	Closed
27	-	-	ES/PROJ/MOT/14/2018-19	ES	2,938,200	-	2,938,200	2,938,200	-	-	2,938,200	-	-	Closed
28	-	3,896,487	HQ/ES/DIPP/07/2018-19	ES	5,723,198	2,453,102	8,176,300	1,826,711	6,349,589	-	8,176,300	-	-	Closed
29	-	-	HQ/ES/DOJ/ARS/05/2019-20	ES	1,122,000	-	1,122,000	1,122,000	-	-	1,122,000	-	-	Closed
30	-	-	HQ/ES/MOC/09/2019-20	ES	590,000	-	590,000	590,000	-	-	590,000	-	-	Closed
31	-	-	HQ/ES/MOC/11/2019-20	ES	654,192	-	654,192	654,192	-	-	654,192	-	-	Closed
32	-	-	HQ/ES/MOT/02/2018-19	ES	1,761,000	-	1,761,000	1,761,000	-	-	1,761,000	-	-	Closed
33	-	-	HQ/ES/MOT/06/2019-20	ES	2,863,860	-	2,863,860	2,863,860	-	-	2,863,860	-	-	Closed
34	-	-	HQ/ES/MOT/12/2019-20	ES	2,096,860	-	2,096,860	2,096,860	-	-	2,096,860	-	-	Closed
35	-	-	HQ/ES/PROJ/MOT/07/2019-20	ES	1,923,350	-	1,923,350	1,923,350	-	-	1,923,350	-	-	Closed
36	-	1,166,032	HQ/ES/PROJ/MOT/08/2019-20	ES	1,623,090	695,610	2,318,700	457,058	1,861,642	-	2,318,700	-	-	Closed
37	-	-	HQ/ES/PROJ/MOT/16/2019-20	ES	3,048,544	-	3,048,544	3,048,544	-	-	3,048,544	-	-	Closed
38	-	-	HQ/ES/DOJ/P/02/2020-21	ES	2,937,020	-	2,937,020	2,937,020	-	-	2,937,020	-	-	Closed
39	-	918,812	HQ/ES/DPIIT/P1/2020-21	ES	1,422,000	-	1,422,000	503,188	409,652	-	912,840	-	509,160	Ongoing
40	-	-	HQ/ES/DGQI/03/2021-22	ES	-	737,000	737,000	-	353,700	-	353,700	-	383,300	Ongoing
41	-	-	HQ/ES/MOT/04/2021-22	ES	-	599,440	599,440	-	640,361	-	640,361	40,921	-	Ongoing
42	-	3,402,679	HQ/IE/P/05/2019-20	IE	4,922,370	-	4,922,370	1,519,691	783,170	-	2,302,861	-	2,619,509	Ongoing
43	-	-	HQ/IE/TRG/INTL/1/19-20	IE	4,425,000	-	4,425,000	4,425,000	-	-	4,425,000	-	-	Closed
44	-	-	HQ/IE/P/04/2019-20	IE	2,905,160	-	2,905,160	2,905,160	-	-	2,905,160	-	-	Closed
45	-	1,983,509	HQ/IE/P/01/2020-21	IE	3,055,988	-	3,055,988	1,072,479	1,371,920	-	2,444,399	-	611,589	Ongoing
46	-	1,317,789	HQ/IE/P/02/2020-21	IE	2,360,000	2,360,000	4,720,000	1,042,211	3,677,789	-	4,720,000	-	-	Closed
47	-	1,096,096	HQ/IE/P/03/2020-21	IE	1,532,230	1,532,230	3,064,460	436,134	2,628,326	-	3,064,460	-	-	Closed
48	-	1,178,951	HQ/IE/P/04/2020-21	IE	1,482,080	1,520,043	3,002,123	303,129	388,892	-	692,021	-	2,310,102	Ongoing
49	-	2,880,361	NPC/HQ/IE/P/05/2020-21	IE	3,400,000	-	3,400,000	519,639	1,315,491	-	1,835,130	-	1,564,870	Ongoing
50	-	-	NPC/HQ/IE/P1/02/21-22	EN	-	1,408,000	1,408,000	-	1,738,405	-	1,738,405	330,405	-	Ongoing
51	-	168,908	RDD/EN/C/04/MOMA/18-19	EN	2,166,480	-	2,166,480	1,997,572	-	-	1,997,572	-	168,908	Ongoing
52	-	445,372	RDD/EN/P/01/DPCC/19-20	EN	913,792	2,055,040	2,968,832	468,420	352,228	-	820,648	-	2,148,184	[illegible]
53	-	4,870,001	RDD/EN/P/04/UNEP/19-20	EN	8,064,100	-	8,064,100	3,194,099	4,870,001	-	8,064,100	-	-	Closed
54	-	-	RDD/EN/P/05/DPCC/19-20	EN	64,900		64,900	64,900	-	-	64,900	-	-	Closed
55	0	-	RDD/EN/P/05/MOEFCC/18-19	EN	27,678,080	-	27,678,080	27,678,080	-	-	27,678,080	0	-	Closed
56	-	-	RDD/EN/P/07/DPIIT/2019-20	EN	344,560	-	344,560	344,560	-	-	344,560	-	-	Closed
57	-	-	RDD/EN/P/01/UPPCB/20-21	EN	173,900		173,900	173,900	-	-	173,900	-	-	Closed
58	-	6,237,521	RDD/EN/P/06/MoEFCC/19-20	EN	9,455,253	1,900,000	11,355,253	3,217,732	8,137,521	-	11,355,253	-	-	Closed

SCHEDULE -2, PROJECT FINANCED BY VARIOUS AGENCIES (ALIVE) AS ON 31/03/2022

S.NO.	Figures for the previous year 2020-21		Name of the Project	Group	Receipt upto 1.4.2021	Reciept During the year 2021-22	Total as on 31/03/22	Exp upto 1.4.2021	Expen. During the year 2021-22	Written down value of assets	Total as on 31/03/2022	Balance DR.	Balance CR.	Ongoing /Closed
	Dr.	Cr.												
59	-	453,100	RDD/EN/P/01/DOE/20-21	EN	2,589,500	-	2,389,500	1,936,400	718,198	-	2,654,598	265,098	-	Ongoing
60	-	-	RDD/EN/P/02/UNDP/20-21	EN	2,260,870	-	2,260,870	2,260,870	-	-	2,260,870	-	-	Closed
61	157,714	-	RDD/EN/P/03/DPIIT/2019-20	EN	157,766	157,714	315,480	315,480	-	-	315,480	-	-	Closed
62	165,852	-	RDD/EN/P/03/UNDP/2020-21	EN	1,693,536	165,852	1,859,388	1,859,388	-	-	1,859,388	-	-	Ongoing
63	-	-	RDD/EN/P/11/BEIL/2020-21	EN	560,500	-	560,500	560,500	-	-	560,500	-	-	Closed
64	199,925	-	RDD/EN/P/15/NOIDA/2020-21	EN	1,194,160	2,662,564	3,856,724	1,394,085	2,462,639	-	3,856,724	-	-	Closed
65	-	375,400	RDD/EN/P/16/WHO/20-21	EN	1,370,000	5,096,400	6,466,400	994,600	3,526,400	-	4,521,000	-	1,945,400	Ongoing
66	-	276,578	RDD/EN/P/17/MOPSW/20-21	EN	700,000	300,000	1,000,000	423,422	576,578	-	1,000,000	-	-	Closed
67	-	-	RDD/EN/P/07/MoSJ&E/19-20	EN	1,180,000	-	1,180,000	1,180,000	-	-	1,180,000	-	-	Closed
68	-	1,331,040	RDD/EN/P/13/MEITY/20-21	EN	1,331,040	-	1,331,040	-	642,616	-	642,616	-	688,424	Ongoing
69	-	-	RDD/EN/P/01/APO/2021-22	EN	-	4,703,934	4,703,934	-	3,417,204	-	3,417,204	-	1,286,730	Ongoing
70	-	-	Counter measure against marine and riverine plastic litering (RDD/EN/P/02/UNEP/2021-22)	EN	-	15,350,025	15,350,025	-	7,459,298	-	7,459,298	-	7,890,727	Ongoing
71	-	-	RDD/EN/P/03/MSME/2021-22	EN	-	-	-	-	119,979	-	119,979	119,979	-	Ongoing
72	-	-	RDD/EN/P/04/MoEFC/2021-22	EN	-	29,500,000	29,500,000	-	12,900,204	-	12,900,204	-	16,599,796	Ongoing
73	-	-	RDD/EN/P/08/CPCB/2021-22	EN	-	155,760	155,760	-	57,140	-	57,140	-	98,620	Ongoing
74	-	-	RDD/EN/P/10/DPIIT/2021-22	EN	-	195,644	195,644	-	195,644	-	195,644	-	-	Closed
75	-	-	RDD/EN/P/05/DPCC/2019-20	EN	-	195,644	195,644	-	195,644	-	195,644	-	-	Closed
76	-	0	RDD/HRM/P/01/17-18(CGPDTM)	HRM/RD	47,950,380	-	47,950,380	47,950,380	-	-	47,950,380	-	0	Closed
77	-	0	Sida	GDNGR	6,860,918	-	6,860,918	6,860,918	-	-	6,860,918	-	0	Closed
	1,438,271	62,803,046	Total		302,602,031	77,760,602	380,362,633	241,234,257	84,195,533	-	325,429,790	1,983,236	56,916,079	

Schedule No. 4 Fixed Assets

Consolidated-Fixed Assets Chart

S. No.	Description of Asset	COST					DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE	
		As on 1.4.2021	Addition during 1st Half	Addition during 2nd Half	Sale/Tr. Written off/CWIP into FA during the year	Total as on 31.3.2022	Depreciation as on 1.4.2021	Depreciation during the year	Sale/Tr. Written off during the year	Total upto 31.3.2022	Written Down Value as on 31.3.2022	Written Down Value as on 31.3.2021
		1	2	3	4	5=(1+2+3-4)	6	7	8	9=(6+7-8)	10=(5-9)	11
	A NON PLAN											
1	Land	258,786	-	-	-	258,786	-	-	-	-	258,786	258,786
2	Building	11,007,314	-	-	-	11,007,314	6,599,281	440,803	-	7,040,084	3,967,230	4,408,033
3	Plant & Machinery	4,165,672	86,693	4,013	44,762	4,211,616	2,588,294	243,197	-	2,831,491	1,380,125	1,577,378
4	Electrical Equipments	2,371,228	1,000,704	1,278,791	2,000	4,648,723	1,253,305	413,403	-	1,666,708	2,982,015	1,117,923
5	Office Equipments	4,428,221	12,710	58,386	500	4,498,817	3,837,925	94,753	-	3,932,678	566,139	590,296
6	Computer	16,557,843	2,680,339	1,508,925	35,088	20,712,019	12,666,217	2,916,536	-	15,582,753	5,129,266	3,891,626
7	Furniture & Fixtures	7,604,031	338,009	139,000	66,322	8,014,718	3,448,407	449,681	-	3,898,088	4,116,630	4,155,624
8	Vehicles	3,415,225	-	-	-	3,415,225	2,760,795	98,162	-	2,858,957	556,269	654,430
9	Audiovisual Equipments	4,336,121	-	-	-	4,336,121	2,983,959	202,821	-	3,186,780	1,149,341	1,352,162
10	Books	3,590,494	-	3,404	14,096	3,579,802	3,575,658	977	-	3,576,635	3,167	14,836
11	Software	186,102	321,209	-	-	507,311	113,869	157,377	-	271,246	236,065	72,233
12	Solar Module	-	-	145,950	-	145,950	-	29,190	-	29,190	116,760	-
	TOTAL A (Non Plan)	**57,921,038**	**4,439,664**	**3,138,469**	**162,768**	**65,336,403**	**39,827,710**	**5,046,900**	**-**	**44,874,610**	**20,461,793**	**18,093,328**
	B PLAN											
1	Building	61,979,980	-	-	-	61,979,980	11,778,382	5,020,160	-	16,798,542	45,181,438	50,201,598
2	Plant & Machinery	2,824,988	-	-	-	2,824,988	784,582	306,061	-	1,090,643	1,734,345	2,040,406
3	Electrical Equipments	2,300,147	-	4,068	-	2,304,215	638,291	249,584	-	887,875	1,416,341	1,661,856
4	Office Equipments	24,482,988	-	-	-	24,482,988	6,794,030	2,653,344	-	9,447,374	15,035,614	17,688,958
5	Computer	597,262	-	-	-	597,262	345,053	100,884	-	445,937	151,325	252,209
6	Furniture & Fixtures	2,950,119	-	-	477	2,949,642	560,523	238,912	-	799,435	2,150,207	2,389,596
7	Vehicles	259,439	-	-	-	259,439	71,994	28,117	-	100,111	159,328	187,445
8	Audiovisual Equipments	497,144	-	-	-	497,144	137,959	53,877	-	191,836	305,308	359,185
9	Laboratory Equipments	6,290	-	-	-	6,290	1,745	682	-	2,427	3,863	4,545
10	Books	163,735	-	-	-	163,735	104,790	23,578	-	128,368	35,367	58,945
12	Software	13,096	-	-	-	13,096	5,730	2,946	-	8,676	4,420	7,366
13	Capital Work in progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	EPABX System	10,031	-	-	-	10,031	2,784	1,087	-	3,871	6,160	7,247
	TOTAL B	**96,085,219**	**-**	**4,068**	**477**	**96,088,810**	**21,225,863**	**8,679,230**	**-**	**29,905,093**	**66,183,717**	**74,859,356**
	(Total (A+B)	**154,006,257**	**4,439,664**	**3,142,537**	**163,245**	**161,425,213**	**61,053,573**	**13,726,130**	**-**	**74,779,703**	**86,645,534**	**92,952,684**

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL New Delhi

Sandeep Singh & Co. Chartered Accountants FRN : 021822N New Delhi

Schedule : 5 Current Assets, Loans & Advances

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
Sundry Debtors		
I)Considered Good	92,842,695	45,138,965
ii)Considered Doubtful	22,851,719	17,311,052
Total Book Debts	**115,694,414**	**62,450,017**
Less: Provision for doubtful debts	22,851,719	17,311,052
Total Book Debts excluding Doubtfull Debts	**92,842,695**	**45,138,965**
Cash & Bank Balances		
i) SBI Bank	1,527,439	78,682,422
ii) Cash in Hand-RDs	-	-
iii) Indian Overseas Bank -RD PLAN	9,735	-
iv) Indian Overseas Bank /B-HQ-plan	6,309,109	788,494
v) Postage in Hand incl.F.M-HQ	-	-
vi) Postage in Hand incl.F.M.-RDs	10,378	12,243
vii) Indian Overseas Bank/B-HQ	121,846,142	66,437,133
viii) Indian Overseas Bank CC 850-HQ	131,299	16,484,952
ix) Indian Overseas Bank-II-RDs	1,753,211	13,645,992
Total	**131,587,313**	**176,051,236**
Gratuity & Other Investments		
i) Term Deposit (FDR)	219,592,178	154,429,965
Total	**219,592,178**	**154,429,965**
Loans & Advances		
i) Festival Advances to Staff-HQ	-	-
ii) Festival Advances to Staff-RDs	-	-
iii) Adv.Recov from Staff-HQ	1,212,786	1,208,127
iv) Adv.Recov. from Staff-RDs	603,739	411,621
v) Adv. Recov.from Others-RDs	-	-
vi) Others Recoverable	8,672,803	3,599,684
vii) Security Deposit/E.M-HQ	5,241,176	2,657,028
viii) Security Deposit/E.M.-RDs	1,956,725	1,731,455
ix) Others Recoverable H.Q./Misc	23,696,427	17,918,427
Total	**41,383,656**	**27,526,341**
T.D.S. (Recoverable)		
HQ	11,702,790	22,478,424
RDs	24,309,683	15,977,287
Total	**36,012,473**	**38,455,711**
Grand Total	**521,418,315**	**441,602,219**

Schedule: 6 Excess of Expenditure over Income

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
Opening Balance	166,012,024	150,254,047
LESS/ ADD		
Excess of income over Expenditure	11,187,366	15,757,977
Total	**177,199,390**	**166,012,024**

Schedule:7 Activity Revenue

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
Receipt from Consultancy & Training Programme	243,550,090	201,495,151
Self Run Programmes	25,726,208	8,031,128
Application Processing Fees	46,610	17,475
Total	**269,322,908**	**209,543,754**

Schedule:8 Receipts from Publication

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
Royalty from Publication	127,550	126,350
Total	**127,550**	**126,350**

Schedule:9 Other Receipts

Particulars	As at March 2022	As at March 2021
Interest receipt	12,321,099	13,277,678
Miscellaneous receipt	400,224	101,183
Rent receipt	20,636,172	16,171,576
Conference Hall charges	143,000	20,000
Interest Received on Income Tax Refund	1,533,685	4,673,075
Profit on sale of assets	304	-
Provision Written Back	-	458,155
Total	**35,034,484**	**34,701,667**

NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL New Delhi

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

Schedule No:10 Employees Remuneration & Benefits

S.no	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2022	HQ	RDs	Total As at March 2021
1	Salary & Allowances/ Stipend	86,483,963	140,912,527	227,396,490	83,535,612	143,159,506	226,695,118
2	CPF (Council share)	20,895,447	-	20,895,447	21,676,278	-	21,676,278
3	Gratuity	17,636,082	-	17,636,082	6,567,605	-	6,567,605
4	Employee's Welfare & CGHS	1,194,074	1,718,297	2,912,371	1,753,507	2,307,491	4,060,998
5	Leave Encashment*	54,799,027	-	54,799,027	92,008,636	-	92,008,636
6	Canteen & Welfare	613,785	162,074	775,860	809,623	267,265	1,076,888
7	Compassionate Fund	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
	TOTAL	161,662,378	142,792,898	304,455,277	206,391,261	145,734,262	352,125,523

* During current FY 2020-21 Deferred Revenue Expenditure of Leave Encashment was expensed for Rs 6,45,46,582/-

Schedule No:11 Office & Administrative Expenses

S.no	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2022	HQ	RDs	Total As at March 2021
1	AMC & Maintainence	730,412	862,255	1,592,667	862,141	696,442	1,558,583
2	Audit Fees	-	-	-	150,000	-	150,000
3	Bldg.&House Keeping & rent	32,186,271	9,927,481	42,113,752	9,274,496	8,202,261	17,476,757
4	Development of Business Activity	1,758,008	563,094	2,321,102	1,482,521	239,983	1,722,503
5	Expert Fees/salary contract	15,030,697	6,364,559	21,395,256	16,340,479	4,924,316	21,264,795
6	Legal & Professional Charges	710,804	4,822,627	5,533,431	66,500	3,655,972	3,722,472
7	Printing & Stationery	763,595	556,565	1,320,160	1,054,093	407,347	1,461,440
8	Programme Activity Exp.	8,927,156	25,887,702	34,814,858	17,047,759	14,682,482	31,730,242
9	Promotional work in Hindi	76,890	2,000	78,890	564,706	2,000	566,706
10	MSME-LMCS Exp.	-	-	-	-	-	-
11	Telephone & Postage	1,886,683	491,845	2,378,526	653,683	397,881	1,051,564
12	Traveling Allowance/L.C/LTC	2,961,088	3,105,568	6,066,656	8,957,475	3,040,126	11,997,601
13	Vehicle Maintenance	258,340	-	258,340	329,853	-	329,853
14	Rates and Taxes	73,580	128,045	201,626	-668,901	178,246	-490,655
15	Prior Period Adjustment	1,156,581	57,098	1,213,679	1,626,547	77,577	1,704,124
16	EMD Written off	-	-	-	-	-	-
17	Debtor Written Off	-	94,300	94,300	-	258,305	258,305
18	Swachchta Action Plan (SAP)	26,996	3,000	29,996	388,170	-	388,170
19	Provision for Doubtful Debts	5,540,667	-	5,540,667	3,416,617	-	3,416,617
20	Productivity Week Exp.	90,000	2,000	92,000	30,000	-	30,000
21	Water Charges arrears	-	-	-	-	-	-
22	Insurance Premium	319,519	9,838	329,357	-	-	-
23	Tender Fees	-	10,000	10,000	-	-	-
24	ITC Reversal (GST Exempt Supply)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	72,497,287	52,887,976	125,385,263	61,575,939	36,742,939	98,318,878

Schedule No:12 PLAN PROJECTS EXPENDITURE

S. No	Item of Expenditure	As at March 2022	As at March 2021
PROJECT BASED SUPPORT TO AUTONOMUOUS INSTITUTIONS			
1	Upgration Of Aip Into Centre Of Exc (/Project Based Support To Autonomous Institutions - New Scheme 2017-18)	-	-
2	COE For It For Industry 4.0(2018-2019)	-	-
3	COE On Quality Management (Coe-Qm)	-	119,634
4	COE For It For Industry 4.0(2018-2019)	-	-
5	COE For It For Industry 4.0(2019-2020)	-	1,184,670
6	COE For It For Industry 4.0(2020-2021)	-	1,569,708
7	COE On Quality Management	-	686,514
		-	-
	TOTAL	-	3,560,526

Schedule No 13 Miscellaneous & Other Charges

S. No	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2022	HQ	RDs	Total As at March 2021
1	Misc.Expenses	8,433,974	81,513	8,515,487	7,736	36,333	44,070
2	Loss on sale of assets	-	-13,525	-13,525	-	-	-
3	Subscription to Journal/Periodical	117,694	-	117,694	70,533	-	70,533
	TOTAL	8,551,668	67,988	8,619,656	78,269	36,333	114,603

Schedule No:14 Interest & Finance Charges

S.no	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2022	HQ	RDs	Total As at March 2021
1	Bank charges	128,300	23,518	151,817	350,381	27,712	378,093
	TOTAL	128,300	23,518	151,817	350,381	27,712	378,093

*** Bank charges includes Interest charges

Schedule No:15 International Cooperation

hba	Item of Expenditure	HQ	RDs	Total As at March 2022	HQ	RDs	Total As at March 2021
1	APO Programme	-	2,289,626	2,289,626	-	-	-
	TOTAL	-	2,289,626	2,289,626	-	-	-

DETAIL OF SUNDRY CREDITORS							
AS AT 31.3.2021							
		As at March 2022			As at March 2021		
S.No.	Head	HQ	RMPG	Total	HQ	RMPG	Total
A	**Sundry Creditor**	11,489,902	949,755	12,439,657	12,569,675	1,570,371	14,140,046
		11,489,902	**949,755**	**12,439,657**	**12,569,675**	**1,570,371**	**14,140,046**
B	**OTHERS PAYABLE**						
1	Salary Payable	13,951,390	600	13,951,990	2,695,305	-	2,695,305
2	Rent Payable	-	6,958,986	6,958,986	-	6,940,453	6,940,453
3	CPC	36,777	-	36,777	30,297	-	30,297
4	CPC Payable (6th & 7th)	21,671,830	-	21,671,830	21,629,581	-	21,629,581
5	TDS Payable	2,589,048	2,162,887	4,751,935	762,166	1,675,203	2,437,369
6	GST Payable	-3,302,235	6,793,667	3,491,431	3,327,980	1,297,038	4,625,019
7	Retention Money	-	394,553	394,553	-	300,501	300,501
8	Earnest Money / Security	5,618,141	804,443	6,422,584	5,610,941	804,443	6,415,384
9	Council Share Payable	470,916	-	470,916	820,311	-	820,311
10	Professional Tax	-	9,540	9,540	-	29,540	29,540
11	Expense Payable	29,195,050	3,100,399	32,295,449	3,413,033	4,093,505	7,506,538
12	NPC T/C Society	16,969	-	16,969	5,119	-	5,119
13	Court Case Recoveries	1,830,604	-	1,830,604	1,830,604	-	1,830,604
14	Court Case Deduction	141,928	-	141,928	141,928	-	141,928
15	Leave Salary Contribution	-	-	-	-	-	-
16	Other Payable	37,166,729	163,481	37,330,210	3,923,220	-	3,923,220
	TOTAL	**109,387,147**	**20,388,556**	**129,775,702**	**44,190,485**	**15,140,683**	**59,331,168**

DETAIL OF SUNDRY DEBTORS							
AS AT 31.3.2021							
		As at March 2022			As at March 2021		
S.No.	Head	HQ	RD	Total	HQ	RD	Total
A	**Specialist Charges**	32,048,888	85,745,045	117,793,933	24,766,920	37,683,096	62,450,017
	TOTAL	32,048,888	85,745,045	117,793,933	24,766,920	37,683,096	62,450,017
B	**OTHERS RECOVERABLE**						
1	Group Insurance	-	-	-	-	-	-
2	Retention Bank a/c	-	791,796	791,796	-	697,744	697,744
3	Programme A/c	8,262,293	-	8,262,293	7,753,775	-	7,753,775
4	Ashok Petronet	-	-	-	-	-	-
5	Prepaid Expenses	270,465	165,123	435,588	1,034,388	333,177	1,367,565
6	Interest Accrued on Fixed Deposits	12,403,637	-	12,403,637	9,040,210	-	9,040,210
7	Misc debtor	2,760,032	42,250	2,802,282	90,054	7,566	97,620
		23,696,427	**999,169**	**24,695,596**	**17,918,427**	**1,038,487**	**18,956,914**
	TDS AY OUTSTANDING						
	TDS AY 2006-07	87,774	1,389,437	1,477,211	87,774	1,389,437	1,477,211
	TDS AY 2007-08	1,454,888	1,644,615	3,099,503	1,454,888	1,644,615	3,099,503
	TDS AY 2010-11	741,136	-	741,136	741,136	-	741,136
	TDS AY 2011-12	1,278,978	-	1,278,978	1,278,978	-	1,278,978
	TDS AY 2012-13	943,550	-	943,550	943,550	-	943,550
	TDS AY 2013-14	11,296	-	11,296	11,296	-	11,296
	TDS AY 2014-15	243,631	-	243,631	243,631	-	243,631
	TDS AY 2015-16	640,051	-	640,051	640,051	-	640,051
	TDS AY 2016-17	-	-	-	-	-	-
	TDS AY 2017-18	-	-	-	-	-	-
	TDS AY 2018-19	-	-	-	-	-	-
	TDS AY 2019-20	-	-	-	-	-	-
	TDS AY 2020-21	-7,744,944	7,268,558	-476,386	10,298,421	7,268,558	17,566,979
	TDS AY 2021-22	6,694,509	5,926,268	12,620,778	6,778,699	5,674,677	12,453,376
	TDS AY 2022-23	7,351,921	8,083,604	15,435,525	-	-	-
	TDS AY 2023-24	-	-2,800	-2,800	-	-	-
	TOTAL	**11,702,790**	**24,309,683**	**36,012,473**	**22,478,424**	**15,977,287**	**38,455,711**

Schedule 16 : Notes to the Accounts for the year ending on 31st March 2022

A. GENERAL

i) Previous year figures have been regrouped and rearranged to the extent required.

ii) Schedule No. 1 to 16 Forms integral part of accounts.

B. BALANCE SHEET

i) The balances of Sundry Debtors, Sundry Creditor, advance recoverable, advance payable, security deposits/payable with/to various agencies/parties etc. as on 31.03.2022 are subject to confirmation and reconciliation which may have impact on the profitability and state of affair of Council as on 31.03.2022.

ii) Schedule of Project Accounts relates to projects sponsored by various agencies.

a) Net Credit Balances : Receipts minus Capital and Revenue Expenditure.

b) Net Debit Balance : Capital and Revenue Expenditure minus Receipts.

iii) Latest Physical Verification of Fixed Assets was done on 12.08.2022.

C. PROVISIONS

i) Provision for Leave encashment during the year is made for Rs. 3,47,99,026/-

ii) Provision for Gratuity have been made during the year amounting to Rs.1,78,45,287/- (Previous Year Rs. 65,71,079/-).

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

D. CONTINGENT LIABILITIES

i) Bank Guarantee of Rs.218.18 Lakhs (Previous Yr. Rs. 173.32 Lakhs) furnished in favour of clients against consultancy jobs.

ii) There is a CPC (TDS) communication regarding defaults in TDS statements for the earlier Assessment Years amounting to Rs. 8,34,168.14/- as per online TDS Portal of Income Tax Department in the name of the Council which is under reconciliation.

iii) The Council has received a notice from Telengana State Housing board for arrears of rent of Hyderabad RD for Rs. 1,00,37,846/- (Consisting of Rent 68,08,509/- and Interest 32,29,336/-) out of which provision has been made for Rs. 68,08,509/- during the FY 2019-20 and for interest a request has been sent to the competent authority of TSHB for Waiving of above interest amounting to Rs. 32,29,336/-.

For SANDEEP SINGH & CO.
Chartered Accountants

Sandeep Singh & Co. FRN : 021822N New Delhi Chartered Accountants

CA. SANDEEP SINGH
(Prop.) M. No. 094439
FRN: - 021822N
Place: New Delhi
Dated: 29.09.2022
UDIN NO.